RNI No.: MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य 50 रूपए
वर्ष 03, अंक 11 मासिक पत्रिका
25 नवम्बर 2024

हमारा देश हमारा अभिमान

हर हर महादेव

सिंहस्थ महापर्व-2028

सिंहस्थ महापर्व-2028 में 9 अप्रैल से 8 मई की अवधि में 3 शाही स्नान और 7 पर्व स्नान प्रस्तावित हैं. सिंहस्थ महापर्व में लगभग 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों को सम्मिलित करते हुए सिंहस्थ-2028 के लिए प्रारंभिक कार्ययोजना बनाई गई

उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ-2028 के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए डीजीपी ने ली वृहद बैठक

उज्जैन पदस्थ रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने साझा किये अपने अनुभव

उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ-2028 के शांति एवं गरिमापूर्ण आयोजन के लिए मध्यप्रदेश पुलिस की तैयारियां गति पकड़ रही हैं। पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना ने बुधवार 13 नवंबर को पुलिस मुख्यालय भोपाल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वृहद बैठक कर कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उज्जैन आईजी तथा एसपी भी उपस्थित रहे।

बैठक में विशेष रूप से श्री सरबजीत सिंह सेवानिवृत्त विशेष पुलिस महानिदेशक जो सिंहस्थ-2004 में आईजी उज्जैन तथा सिंहस्थ 2016 में विशेष पुलिस महानिदेशक इंटेलीजेंस के पद पर रहे तथा श्री उपेन्द्र जैन विशेष पुलिस महानिदेशक जो सिंहस्थ- 2004 में उज्जैन एसपी रहे और श्री मनोहर वर्मा सेवानिवृत्त आईपीएस जो सिंहस्थ-2016 में एसपी उज्जैन रहे, ने अपने अनुभव साझा किए।

डीजीपी श्री सक्सेना ने कहा कि उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ महाकुंभ - 2028 विश्व का सबसे वृहद धार्मिक - सांस्कृतिक आयोजन होगा। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों का आगमन इस दौरान होगा। अतः सुव्यवस्थित यातायात और सुरक्षा के इंतजाम भी इसके अनुकूल हों। उन्होंने कहा कि क्राउड कंट्रोल और क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। क्राइम कंट्रोल, एंटी नेशनल एलिमेंट कंट्रोल तथा टेरेरिस्ट गतिविधियों पर सजग निगाहें रखना जरूरी है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी व्यक्तियों की परस्पर संचार व्यवस्था तथा अन्य विभागों से भी अच्छा सम्पर्क और समन्वय होना अत्यावश्यक है। ड्रोन कैमरों तथा सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था और 24x7 मॉनीटरिंग हेतु डेडिकेटेड कार्मिक होना बहुत जरुरी है। डीजीपी श्री सक्सेना ने बैठक में इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की।

सुरक्षा व्यवस्था

इस बार सिंहस्थ में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। मेले की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, और फेस रिकग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाए। साथ ही, मेला क्षेत्र में मोबाइल पुलिस चौकियाँ स्थापित की जाएं। पूरे मेला क्षेत्र में 24 घंटे पुलिस गश्त रहेगी और एंटी-टेरर स्क्वॉड तथा बम निरोधक दस्ते को भी तैनात किया जाए। विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष दल तैनात किए जाएं। पुलिस और अन्य विभागों के बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए एडवांस वायरलेस सिस्टम और कमांड सेंटर का उपयोग किया जाए। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए QRT, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हर समय तैयार रखें। डीजीपी ने कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। इनके लिए विशेष सहायता केंद्र और मेला क्षेत्र में नजदीकी पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सिंहस्थ मेला क्षेत्र को विभिन्न ज़ोन और सेक्टर में विभाजित किया जाए। प्रत्येक सेक्टर में एक प्रभारी अधिकारी तैनात होगा, जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा।

ट्रैफिक व्यवस्था

इस बार ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न रूट प्लान बनाए जाएं। उज्जैन के नजदीकी जिलों को भी ट्रेफिक प्लान में सम्मिलित कर विस्तृत प्लान बनाएं। मेला क्षेत्र में वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सिटी बसों के साथ-साथ ई-रिक्शा की भी व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए मुख्य मार्गों पर सूचना केंद्र बनाए जाएंगे और रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उज्जैन के बाहरी क्षेत्रों में भी रेलवे स्टेशन तथा नजदीकी जिलों में भी व्यापक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।

विशेष प्रबंध

पुलिस प्रशासन इस बार सिंहस्थ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगा, जो 24x7 सक्रिय रहेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पडेस्क और बाल सुरक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जाए। इसके अलावा, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाए।

बैठक में उपस्थित सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों ने अपनी-अपनी शाखाओं की सिंहस्थ की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि उज्जैन पुलिस से समन्वय कर सभी शाखाएं अपनी विस्तृत कार्ययोजना बनाकर 15 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। हर ब्रांच अपना दायित्व, मेनपॉवर, ट्रेनिंग, परमानेंट स्ट्रक्चर, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, उपकरण, वाहन तथा वर्तमान में संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकतानुसार बजट की मांग अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित करें।

पूर्व में उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान कार्यरत् रहे सेवानिवृत्त आईपीएस श्री सरबजीत सिंह ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि क्राउड मूवमेंट का विशेष ध्यान रखें। साथ ही टेली कम्यूनिकेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। स्पेशल डीजी श्री उपेन्द्र जैन ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सभी विभागों से पुलिस का अच्छा समन्वय होना कार्य को आसान बना देता है एवं से.नि. आईपीएस श्री मनोहर वर्मा ने उपस्थित अधिकारियों से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्नान घाट तकनीकी रूप से अच्छी प्लानिंग के अनुसार बनें तथा ट्रेफिक एवं महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए उज्जैन के पड़ोसी जिलों को भी कार्य योजना में शामिल किया जाए।

उज्जैन सिंहस्थ कुंभ के लिए मोहन सरकार का मेगा प्लान

हमारा देश
हमारा अभिमान

25 नवम्बर 2024

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन • श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडों कमल किशोर (पूर्व सांसद)
- श्री के. कान्याल • श्री मधु सुदन मिश्रा
- राजेश कुमार त्रिपाठी

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

विशेष संवाददाता
• रवि परिहार • रविकांत शर्मा

कानूनी सलाहकार
• एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
• एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
• दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

ब्यूरो : अविनाश जाजपुरा (उज्जैन संभाग)
छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजोरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजोरिया
- हेमाटोलाजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादौन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट
- रागिनी चतुर्वेदी
- प्रवेंद्र चतुर्वेदी
- प्रखर सिंह

शरद आनंद ऑनर (गहना ज्वैलर्स)

सह सलाहकार

सोनीष वशिष्ठ,कमल वर्मा,अनिल शर्मा, मंगला चतुर्वेदी ,संजू शर्मा ,चंचल शर्मा ,रुचि चतुर्वेदी

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर
मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन
मार्केटिंग मैनेजर
• सुनील • हरशूल

सह मार्केटिंग ब्यूरो ग्वालियर एवं सह संवाद दाता: सुनिता कुशवाह, अर्जना खन्ना

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी ।
(सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

सुविचार

आत्मविश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। खुद पर विश्वास हमे की ओर ले जाता है।

विवरणिका

संपादकीय 04-05
मध्य प्रदेश 06-22
ग्वालियर 23-24
इंदौर 25-26
देश-प्रदेश 27
अंतराष्ट्रीय 28-29
महाराष्ट्र-झारखण्ड चुनाव..... 30
पर्यटन..... 32
धर्म..... 33-34
शिक्षा..... 35-39
वास्तु 40
स्वास्थ्य..... 41-44
वेल्थ मैनेजमेंट..... 45-46
ऑन लाइन शॉपिंग 47
फैशन..... 48-49
टेक्नोलॉजी 51

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ये हैं बेस्ट जगहें

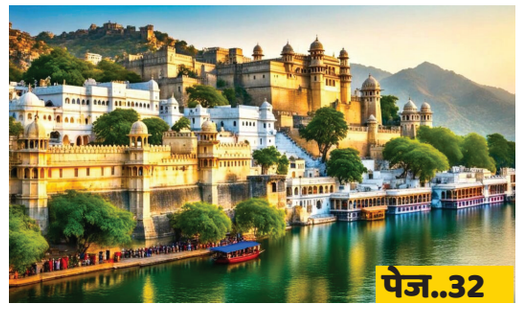

पेज..32

रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदते समय न खाएं धोखा!

पेज..51

संपादक
मनोज चतुर्वेदी

सम्पादकीय

आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना

वरिष्ठ नागरिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

भारत में लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष से अधिक अवस्था के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार ने आयुष्यमान वय वंदना कार्ड प्रस्तुत किया है। उपरोक्त कार्ड के आधार पर इस व्यवस्था से सभी नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। उपरोक्त कार्ड में आय संबंधी कोई बंधन नहीं होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। क्योंकि उनमें से करे लोगों को महँगी चिकित्सा उपचार करना पड़ता है। एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उपरोक्त योजना निश्चय ही भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी।

डॉ. श्रीमन
नारायण मिश्रा
वरिष्ठ संरक्षक

मणिपुर हिंसा का समाधान परस्पर संवाद से ही संभव

मणिपुर में विगत दो वर्ष से अधिक समय से मैतेय एवं कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा चिंता का बहुत बड़ा कारण बन गयी है। मैतेय समुदाय को जनजातिय समुदाय का दर्जा दिए

जाने पर विचार किए जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद दोनों समुदायो के बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया था। यह संघर्ष मानवता के हनन की तमाम सीमाओं को पार कर गया है। मणिपुर में मैतेय समुदाय के 40 तथा कुकी समुदाय के 20 विधायक है। मेंतेय प्रमुखतः इंफाल घाटी वे मैदानी इलाकों में फैले हैं। कुकी पहाड़ी इलाको में स्थापित है। यह सही है कि लगातार शांति प्रयास जारी हैं। दोनो समुदायों के 20 विधायकों ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है।भारत की एकता और अखंडता की दृष्टि से भी मणिपुर में शांति स्थापित किया जाना जरूरी है I आशा की जाती है कि निकट भविष्य में दोनों समुदाय मिलकर शांतिपूर्वक समाधान की दिशा में अग्रसर होंगे।

डबरा ।कृषि उपज मंडी में सर्दियों में आने बाली किसानों के द्वारा धान की बिक्री के लिए अलग रास्ता का प्रावधान किया जाएगा जिससे जाम की समस्याओं से बचा जा सके। साथ ही बनाए गए नियमों का पालन हो इसके लिए हम तत्पर्य रहेंगे। डबरा एस डी ओ पी विवेक शर्मा के साथ संपादक मनोज चतुर्वेदी की विशेष चर्चा।

पूर्ण चर्चा आगामी अंक मै

अक्षुण्ण बोहरे निरीक्षक (Inspector) रैंक पर पदोन्नति प्राप्त हुई

विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 होगा विकसित मध्य प्रदेश का आधारः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 विकसित मध्य प्रदेश का आधार होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से 'विकसित मध्य प्रदेश @ 2047 विज़न डॉक्यूमेंट' तैयार किया जा रहा है। पिछले सप्ताह इस संबंध में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने राज्य के प्रमुख अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने मंत्रियों को अपने-अपने विभागों में विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी तीन माह में डॉक्यूमेंट का प्रारूप मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सहयोगियों को प्रदेश में शहरी विकास और शहरी प्लानिंग के संबंध में अपने सुझाव नगरीय विकास एवं आवास विभाग से साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरों को झुग्गी मुक्त किए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सहित अन्य घटकों में कार्य जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 9 लाख 50 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सितम्बर 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 लागू की गई,जिसमें पहले की तरह स्वयं की भूमि पर 2 लाख 50 हजार रूपए तक का अनुदान प्राप्त करना प्रमुख घटक है।

सी एम हेल्प लाइन संबंधित बैठक जनपद पंचायत मुरार, ग्वालियर की हुई

इस बैठक में निराकरण करने के निर्देश दिए। इस बैठक मुरार जनपद अध्यक्ष दिलराज किरार के उपस्थित मै हुई

पुलिस को फ्यूचर रेडी होना होगा : मुख्यमंत्री डॉ.

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दुरूपयोग और सायबर क्राइम के खतरे से समाज को बचाने रहें तैयार,प्रत्येक थाने में सायबर डेस्क, हर जिले में सायबर थाना और राज्य स्तर पर किया जाए कॉल सेंटर स्थापित, नशे के नेटवर्क को धवस्त करें : संदिग्ध हुक्काबार एवं नाइट क्लब पर बढ़ाएं निगरानी,वन्य पशुओं की गतिविधियों के संबंध में वन विभाग से सम्पर्क में रहें पुलिस कर्मी, मुख्यमंत्री ने की गृह विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दुरूपयोग और सायबर क्राइम के खतरे से समाज को बचाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस को फ्यूचर रेडी होना होगा। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अद्यतन तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रत्येक थाने में सायबर डेस्क, हर जिले में सायबर थाना और राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किया जाए। सायबर फ्रॉड और क्राइम से लोगों को बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस, सोशल मीडिया पर चलने वाली गतिविधियों और मैसेज आदि पर निगरानी रखें तथा भ्रामक, गलत खबर फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई करें। कानून-व्यवस्था के साथ अन्य भ्रामक खबरों के बारे में संबंधित विभाग को तथ्यों की जाँच करने के लिए अवगत कराया जाए, जिससे वस्तुस्थिति की पुष्टि करते हुए सही जानकारी का सोशल मीडिया पर तत्काल प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मंत्रालय में हुई गृह विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

गौ-तस्करों पर कठोर कार्यवाही की जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सघन मॉनिटरिंग की जाए। थानावार नशे से संबंधित गतिविधियों वाले संभावित क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाते हुए संदिग्ध व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही करें। संदिग्ध हुक्काबार, नाइट क्लब आदि पर भी निगरानी बढ़ाई जाए। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय कर अंतर्राज्यीय गिरोहों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। साथ ही गौ-तस्करों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करने और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों को कठोरतम दंड दिलाना सुनिश्चित किया जाए। गुम हुई बालिकाओं की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

नवीन क्रिमिनल कोड के संबंध में जागरूकता और जांच के लिए करें आवश्यक व्यवस्था

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नवीन क्रिमिनल कोड के संबंध में जागरूकता के लिए मैदानी स्तर तक सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। नवीन व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रकरण की जांच और चालान प्रस्तुत करने आवश्यकतानुसार पेन ड्राइव, टेबलेट इत्यादि पुलिस स्टॉफ को उपलब्ध कराने विभागीय स्तर पर बजट प्रावधान किया जाए। प्रत्येक संभाग में एफएसएल लेब भी स्थापित की जाए।

मार्च 2026 तक नक्सल गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त किया जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल विरोधी अभियान संबंधी बैठक में मार्च-2026 तक नक्सल गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के संभावित नक्सल क्षेत्र में सघन ऑपरेशन चलाया जाए। इसके लिए निश्चित समय सीमा में आवश्यकतानुसार हॉक-फोर्स की भर्ती की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन जिलों में वन्य पशुओं की गतिविधियों से जन जीवन प्रभावित होने या जन हानि होने की संभावना है वहां वन विभाग से समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए पुलिस सक्रिय रहे।

सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के स्थान पर भर्ती सुनिश्चित की जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार पुलिस बल और वाहनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती और वाहनों की आपूर्ति संबंधी आगामी कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में पुलिस कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस अनुपात में प्रतिवर्ष भर्ती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में यदि अधिक पुलिस बल की आवश्यकता हो तो तदानुसार भर्ती की जाए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आगामी वर्षों में पुलिस कर्मी और विभिन्न पदक्रमों पर पर्याप्त बल उपलब्ध हो और प्रदेश में काडर मैनेजमेंट व्यवस्थित बना रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय 'रूस्तमजी' पुरस्कार पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही एडीजी स्तर के अधिकारियों को नियमित रूप से संभाग स्तर पर दौरे और अपराधों की समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

पुलिसकर्मी और अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक

मुख्यमंत्री डॉ, यादव ने कहा कि बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस की साख स्थापित करना और पुलिस कर्मी और अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस परिवारों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से संवेदनशीलता के साथ आवश्यक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिसकर्मी और अधिकारी को स्वयं का आवास निर्मित करने के लिये विभाग की ओर से दी जाने वाली अनुमति और ऋण व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। पुलिस संरचना में प्रत्येक स्तर पर निश्चित समयावधि के बाद पदोन्नति की जाए। पुलिस की उपलब्धियों और प्रभावी कार्यवाहियों का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए

पुलिस बैंड का पुलिस बल के उत्साह और कौशल पर होता है सकारात्मक प्रभाव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस बैंड का पुलिस बल के उत्साह और कौशल पर सकारात्मक प्रभाव होता है। पूर्व रियासतों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में ऐतिहासिक रूप से पुलिस बैंड की परम्परा रही है। पुलिस बैंड के केडर को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य-योजना बनाई जाए। उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र के प्रबंधन के लिए मंदिर क्षेत्र को समर्पित थाना स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

निश्चित समयावधि में नागरिक सेवाओं की कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश नागरिकों को अधिसूचित सेवाएँ प्रदाय करने की कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 25 सितम्बर 2010 से लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम प्रभावशील है। वर्तमान में अधिनियम अंतर्गत 748 सेवाएँ अधिसूचित की जा चूंकि है। इन सेवाओं में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों के लिए 342 सेवाएँ ऑनलाईन प्रदाय की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन के लिए संकल्पबद्ध मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया हैं। नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए समाधान एक दिन तत्काल सेवा, सीएम हेल्पलाईन 181 कॉल सेन्टर, महिला हेल्पलाईन, सीएम जन सेवा, दिव्यांग हेल्पलाईन समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम जनोन्मुखी प्रशासन की गवाही देते है।मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने और सेवा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सुशासन की दिशा में समय-समय पर अनेक कदम उठाएँ है। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पृथक से लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया। वर्ष 2013 में राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना की गई। राज्य लोक सेवा अभिकरण में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के साथ-साथ लोक सेवा केन्द्रों की स्थाना और संचालन का सीएम हेल्पलाईन कॉल सेंटर का संचालन और सीएम डेशबोर्ड का संचालन भी शामिल है।लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से नगारिकों को एक समयावधि में सेवाएँ प्रदाय करने के लिए सभी

तहसीलों में 439 लोकसेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिनके माध्यम से विभिन्न विभागों की अधिसूचित सेवाएँ नागरिकों को प्रदाय की जा रही हो। अधिनियम के अंतर्गत विभाग की अधिसूचित सेवा "जाति प्रमाण पत्र प्रदाय" अभियान के तहत लोकसेवा केन्द्रों द्वारा प्रदेश भर के स्कूलों के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का अभियान सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान में अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा चुके है। प्रदेश में लोकसेवा गारंटी अंतर्गत अधिसूचित समस्त सेवाओं में 10 करोड़ 62 लाख आवेदनों का अब तक निराकरण किया जा चुका है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत सेवाओं की प्रदाय की गारंटी हैं। प्रत्येक सेवा को प्रदाय करने की एक समयावधि भी तय की गई है। इसमें समय पर सेवा नहीं देने पर जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। अधिकारी वर्ग प्रतिदिन 250 रूपये से लेकर अधिकतम 5000 हजार रूपये तक की जुर्माना राशि जमा करने का प्रावधान है।

समाधान एक दिन तत्काल प्रदाय सेवा

नागरिकों को केवल एक दिन की समयावधि में सेवा उपलब्ध कराने की मंशा से मध्यप्रदेश शासन ने फरवरी 2018 में "समाधान एक दिन तत्काल सेवा" व्यवस्था शुरू की। इस व्यवस्था में आवेदक द्वारा दोपहर पूर्व तक दिए गए आवेदन का निराकरण दोपहर पश्चात कर दिया जाता है। इस सेवा में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र व्हाटसअप, ई-मेल के माध्यम से भी आवेदकों को भेजे जा रहे है, जिससे आवेदक अपनी सुविधा अनुसार प्रमाण-पत्र समाधान एक दिन तत्काल सेवा व्यवस्था में अब तक दो करोड़ 63 लाख से अधिक आवेदन निराकृत किए गए है। समाधान एक दिन में दी जाने वाली 32 सेवाओं में आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, ट्रेड लाइसेंस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी चालू खसरा, बी-1 खतौनी चालू नक्शा, खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त), अभिलेखागार प्रतिलिपि, राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रतिलिपि, भू-अधिकार पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय, जिला स्तरीय रिकॉर्ड रूम से पारित आदेश/अंतरिम आदेश आदि की सत्यप्रतिलिपि इत्यादि कई सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ से मिली सराहना

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम अपनी तरह का पहला विशेष अधिनियम है जो निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है। इसे वर्ष 2012 में अधिनियम को यूएनपीएसए पुरूस्कार प्राप्त हुआ। "लोक सेवाओं के वितरण में सुधार वर्ग में इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2012 को लोक सेवा पुरूस्कार भी प्राप्त हुआ है।

वैश्विक धरोहर है बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 165 बाघ और 100 से अधिक तितलियों की दुर्लभ प्रजातियाँ हैं

उमरिया जिले का विश्व प्रसिद्ध बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व वैश्विक धरोहर है। यहाँ की जैव-विविधता, दुर्लभ वन्य-जीवों की उपलब्धता, कल्चुरी कालीन किला और हिन्दू देवताओं के प्राचीन मंदिर पूरी दुनिया में दुर्लभ हैं। टाइगर रिजर्व की स्थापना के पूर्व यहाँ का जंगल एवं पहाड़ियों के बीच निर्मित किला एवं अन्य संरचनाएँ रीवा रियासत के महाराजा की निजी सम्पत्ति हुआ करती थी। किले में राजकीय कार्यों के अलावा राज परिवार का निवास भी होता था। घनघोर जंगल राजा और महाराजाओं का निजी शिकारगाह होता था, जहाँ देश-विदेश के राजा समय-समय पर आकर आखेट करते थे।कालांतर में देश की आजादी के बाद तत्कालीन रीवा महाराजा मार्तण्ड सिंह ने सन् 1967 में किला सहित पूरा जंगल मध्यप्रदेश शासन को नेशनल पार्क स्थापित करने एवं वन्य-जीव संरक्षण के लिये दान में दिया था। इसके बाद मध्यप्रदेश शासन द्वारा बाँधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना की गयी। वर्ष 1981 के बाद यहाँ पर केन्द्र की टाइगर परियोजना शुरू की गयी। बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मौजूद जल-स्त्रोतों से यहाँ की जैव-विविधता देश-दुनिया के जंगलों की अपेक्षा उत्कृष्ट रही है। यहाँ जल-स्त्रोतों की मौजूदगी हमेशा से रही है, जिससे हरियाली बनी रहती है। पर्याप्त जल-स्त्रोत, चारागाह, सघन

वन, शाकाहारी, मांसाहारी वन्य-जीवों के लिये आवश्यक आहार और रहवास की अनुकूलता होने से यहाँ दुर्लभ से दुर्लभ वन्य-प्राणी एवं पक्षी अपना आश्रय-स्थल बनाये हुए हैं।

बाघों की सघन मौजूदगी पूरी दुनिया में बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व को एक अलग पहचान दिलाती है। टाइगर रिजर्व 1526 वर्ग किलोमीटर के कोर एवं बफर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जंगल में वर्ष 2022 की गणना अनुसार 165 से भी ज्यादा बाघों की संख्या पायी गयी थी। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व से 49 बायसन लाकर वर्ष 2012 में बसाये गये थे, जो अनुकूल परिस्थितियों में बढ़कर वर्तमान में लगभग 200 की संख्या में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व में दुनिया में विलुप्ति की कगार पर पहुँच चुके विशेष प्रजाति के बारहसिंघा भी कान्हा टाइगर रिजर्व से लाकर बाँधवगढ़ में बसाये गये हैं। वर्ष 2018 से जंगली हाथियों ने भी अपना रहवास यहाँ बनाया है। तकरीबन 70 से 80 जंगली हाथी टाइगर रिजर्व के अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न झुण्डों में विचरण कर रहे हैं।

टाइगर रिजर्व में बाघ, बायसन, जंगली हाथी के अलावा नीलगाय, भालू, तेंदुआ, चीतल और सांभर यहाँ के मुख्य वन्य-प्राणी हैं, जो पर्यटन के साथ जैव-विविधता का केन्द्र हैं। टाइगर रिजर्व बाँस एवं साल के सघन वृक्षों से घिरा हुआ है। यहाँ वन्य-जीव दर्शन के अलावा हिन्दू मान्यताओं के कई प्राचीन धार्मिक मंदिर भी हैं। इसमें बाँधवगढ़ किले के समीप स्थित भगवान राम-जानकी मंदिर आस्था का प्रमुख केन्द्र है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जन्माष्मी के पर्व पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देशभर से हिन्दू धर्मावलम्बी पूजा-दर्शन के लिये पहुँचते हैं। बाँधवगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित कबीर गुफा कबीरपंथियों की आस्था का केन्द्र है। प्रतिवर्ष अगहन पूर्णिमा के दिन यहाँ पर कबीरपंथियों का जमावड़ा होता है और कबीर गुफा में कबीर अनुयायी उनकी पूजा-पाठ करते हैं। संत शिरोमणि सेन की तपोस्थली भी बाँधवगढ़ में ही रही है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा संत सेन का मंदिर एवं समाधि-स्थल बनाने के लिये टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे हुए क्षेत्र में भूमि आरक्षित की गयी है, जिसमें निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है।बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के लिये विश्व प्रसिद्ध है। इसमें पहली बार दो दिवसीय बटरफ्लाई सर्वे कराया गया। टाइगर रिजर्व के 15 कैम्पों में 61 सदस्यों ने रिजर्व के जंगलों में पैदल सर्वे किया और सर्वे शीट पर तितलियों की जानकारी को अपडेट किया। दो दिवसीय सर्वे में तितलियों की 100 से अधिक प्रजातियाँ पायी गयीं। इनमें 5 से अधिक तितलियाँ दुर्लभ प्रजाति की हैं। कॉमन रैड आई, ब्लैक राजा, किंग क्रो और इंडियन डॉर्ट लेट जैसी तितली भी सर्वे में पायी गयी। तितलियों के सर्वे में मोबाइल एप का उपयोग नहीं किया गया। हाथ से ही सर्वे शीट में पैन से जानकारी को अपडेट किया गया।

सशक्त आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव है स्वस्थ नागरिक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तृत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तृत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की नींव स्वस्थ नागरिकों से बनती है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक, चाहे वह शहर में हो या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्नत चिकित्सा सेवाओं तक आसानी से पहुंच सके। इसी उद्देश्य से राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे ये केंद्र जिला अस्पतालों के समान उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सभी नागरिकों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्वस्थ नागरिकों से ही आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण संभव है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और हर क्षेत्र में लोग पूरी ऊर्जा से समाज और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और मैनपॉवर की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के "स्वस्थ भारत सशक्त भारत" के दृष्टिकोण के तहत चिकित्सा शिक्षा का भी तेजी से विस्तार कर रही है। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 17 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जारी है। हाल ही में सिवनी, नीमच, और मंदसौर में नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हुआ है और 8 अन्य मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 12 और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है, जिससे प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा।

30 हज़ार से अधिक चिकित्सकीय, सहायक चिकित्सकीय पदों पर होगी भर्ती

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (IPHS) के मानकों के अनुरूप राज्य में शीघ्र ही 30 हजार से अधिक चिकित्सकीय और सहायक चिकित्सकीय मैनपॉवर की भर्ती की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाय में और सुधार होगा।

आधुनिक तकनीक और सेवाओं का समावेश

मध्यप्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों में MRI, CT स्कैन, और PET CT जैसी आधुनिक उपकरणों की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 42 प्रकार की एंटी-कैंसर दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर उचित उपचार मिल सके। राज्य के सभी जिला और सिविल अस्पतालों में अब 132 प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 80 प्रकार की जांच की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में 324 हब और 1,610 स्पोक स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रतिदिन 35 हजार से अधिक जांचें जिला स्तर पर और 32 हजार से अधिक जांचें हब और स्पोक पर हो रही हैं। इसी तरह सभी जिला अस्पतालों में अब डायलिसिस, CT स्कैन और डिजिटल एक्स-रे की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश का एमवाय (महाराजा यशवंतराव) अस्पताल इन्दौर देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उन्नत सीएआर-टी थेरेपी शुरू की गई है। यह सुविधा राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने और उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा आपातकाल में जीवन रक्षक

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आपातकाल में बहुमूल्य जीवन के संरक्षण हेतु हर नागरिक तक उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। सड़कों और औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदाओं, हृदय संबंधी समस्याओं और अन्य गंभीर बीमारियों की स्थिति में यह सेवा जीवनरक्षक साबित हो रही है। एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा संस्थानों तक पहुँचाया जा रहा है। राज्य के भीतर और बाहर सड़क, औद्योगिक दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों और आयुष्मान कार्डधारकों को निःशुल्क परिवहन की सेवा प्राप्त होगी।

मेडिकल डिवाइस पार्क चिकित्सा क्षेत्र में मध्यप्रदेश को बनायेगा आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में स्थापित हो रहा देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस पार्क के माध्यम से न केवल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन होगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाया जा सकेगा। इससे प्रदेश में चिकित्सा उपकरणों की निर्भरता कम होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में भी कमी आएगी। यह मेडिकल डिवाइस पार्क मध्यप्रदेश को एक मेडिकल हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जहां चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन, शोध, और नवाचार के अवसर बढ़ेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जा सकेगा, जो इसे चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।

मुफ्त दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के शासकीय अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता में भी बड़ी वृद्धि की गई है। जिला अस्पतालों में 295 से बढ़ाकर 530 प्रकार की दवाएँ, सिविल अस्पतालों में 448, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 373 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 299 प्रकार की दवाएँ मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

मध्यप्रदेश सरकार मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। राज्य में विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ (SNCU) और बाल गहन चिकित्सा इकाइयाँ (PICU) स्थापित की गई हैं, ताकि माताओं और नवजात शिशुओं को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्राप्त हो सके। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों की समय पर पहचान कर आवश्यक चिकित्सकीय सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही सुरक्षित प्रसव के लिए बर्थ वेटिंग रूम का संचालन और किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की सुविधा प्रदान की जा रही है।

आयुष्मान भारत योजना से मिला स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना ने मध्यप्रदेश के नागरिकों को एक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र प्रदान किया है। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में अब तक 22 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और आयुष्मान कार्ड जारी करने में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इस योजना के तहत राज्य में 1,048 स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संस्थान सूचीबद्ध हैं, जिनमें 493 सार्वजनिक अस्पताल और 555 निजी अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा 1,952 प्रकार के स्वास्थ्य लाभ पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, उच्च जोखिम गर्भावस्था, किडनी की बीमारियाँ और अन्य महंगे उपचार शामिल हैं। यह चिकित्सा सेवा क्षेत्र की क्रांतिकारी योजना है, जिसके माध्यम से आज गरीब वंचित लोग उत्कृष्टउन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधारों और विकासात्मक पहलों का एक नया अध्याय लिखा है। विकसित भारत के विजन में नागरिकों के स्वास्थ्य को आवश्यक माना गया है।

पहली बार देश में यह हुआ है कि विकास को मनुष्य के स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। "विकसित भारत" के विजन को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर जो कदम उठाए हैं, वे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित कर रहे हैं।

7.50 लाख कर्मचारियों को अलग से मिलेगी एक माह की राशि, डीए के एरियर पर सामने आया बड़ा अपडेट

मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ते यानि डीए के एरियर पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई थी और इसके साथ ही एरियर देने की भी घोषणा की गई थी। डीए में बढ़ोत्तरी के साथ घोषित एरियर देने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को एक माह की राशि अलग से दी जाएगी। शेष एरियर चार समान किस्तों में प्रदान किया जाएगा। मध्यप्रदेश के सभी 7.50 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों को दिसंबर माह में एरियर की पहली किस्त मिल जाएगी।

राज्य सरकार ने दिवाली के पूर्व मध्यप्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। डीए में यह बढ़ोत्तरी 1 जनवरी 2024 से लागू की गई है। प्रदेश के कोष एवं लेखा विभाग के आयुक्त ने डीए का एरियर देने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।

राज्य सरकार ने कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त दिसंबर 2024 में देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को 4 समान किस्तों में एरियर दिया जा रहा है। एरियर की गणना 'एरियर केल्कुलेशन शीट' से की जा रही है। खास बात यह है कि कर्मचारियों, अधिकारियों को अक्टूबर का यानि एक माह का एरियर अलग से दिया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने डीए का नगद लाभ अक्टूबर 2024 से देने का ऐलान किया था पर दिवाली की वजह से वेतन पहले ही दिया जा चुका था। इसलिए अक्टूबर माह का एरियर अलग से दिया जाएगा। वहीं डीए के 9 माह के एरियर की राशि चार समान किस्तों में दी जाएगी। यह एरियर 2024 के दिसंबर माह, 2025 के जनवरी, फरवरी और मार्च माह में दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 28 अक्टूबर को प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों को डीए देने की घोषणा की। सीएम के आदेश पर अमल करते हुए कोष एवं लेखा आयुक्त ने जिला कोषालय अधिकारियों को संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। एरियर की गणना और भुगतान में कोई परेशानी पैदा न हो, इसके लिए प्रदेश के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को एरियर देने की प्रक्रिया की जानकारी देने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव तुलसी शालिग्राम विवाह में हुए शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देवउठनी ग्यारस पर मालवीय नगर युवा सदन में तुलसी शालिग्राम विवाह में शामिल हुए। उन्होंने श्री हरि और माँ तुलसी से प्रदेशवासियों के जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण बनाए रखने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माता तुलसी की मंत्रोच्चार के साथ पूजा कर धूप, सिंदूर, चंदन, पुष्प अर्पित कर नैवैद्य का भोग लगाया। इस अवसर पर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि देवउठनी ग्यारस भगवान श्री विष्णु के 4 महीने की निद्रा से जागरण का प्रतीक है। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल ग्यारस तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा की जाती है और उनके विवाह का आयोजन किया जाता है। देवउठनी ग्यारस के दिन विशेष मंत्रों का जाप कर भगवान विष्णु और माता तुलसी की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।

एमपी में कर्मचारियों की 'ई-कुंडली' बनवा रही सरकार, जानिए क्यों लिया गया फैसला

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों से जुड़ी एक और जरूरी खबर सामने आ रही है। मध्यप्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों की ई-कुंडली बनवा रही है जो कि नए साल तक बनकर तैयार होने की बात कही जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और सभी कर्मचारियों-अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड डिजिटल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी के सर्विस रिकॉर्ड डिजिटल होने के बाद कर्मचारी-अधिकारियों की एक बड़ी समस्या दूर हो जाएगी।

'ई-कुंडली' बनने से होगा फायदा

मध्यप्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड डिजिटल करने की प्रक्रिया चल रही है और नए साल से कर्मचारियों को इसकी सौगात मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की ई कुंडली तैयार होने से कर्मचारियों और विभाग दोनों को ही बड़ी राहत मिलेगी।

कर्मचारियों को जहां नियुक्ति से जुड़े तमाम दस्तावेज, उनकी पोस्टिंग, पदोन्नति, शिकायत, विभागीय जांच, सजा और वेतन-भत्तों से जुड़ी जानकारियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा तो वहीं विभाग को भी फाइलें नहीं पलटानी पड़ेंगी और फाइलों का रखरखाव नहीं करना पड़ेगा। पूरा रिकॉर्ड सामान्य प्रशासन विभाग के ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर उपलब्ध होगा जिसे आईडी और पासवर्ड के जरिए आसानी से देखा जा सकेगा।

जनजातीय समुदाय को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि जनजातीय समुदाय को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने शुक्रवार को धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा में प्रदेश के पहले शासकीय "सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फ़ॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ़ हीमोग्लोबिनोपैथीज" का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण केंद्र विंध्य क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर जनजातीय समूह के नागरिकों में रक्तजनित वंशानुगत विकारों के शोध, जांच एवं नैदानिक चिकित्सकीय परीक्षण के लिए समर्पित रहेगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि केन्द्र की स्थापना प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को एक नए आयाम पर ले जाने का प्रयास है, जिससे रक्तजनित विकारों से प्रभावित विशेष समूहों को सटीक और समर्पित चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। विंध्य क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर जनजातीय समुदायों में इन विकारों की व्यापकता को देखते हुए इस केन्द्र की आवश्यकता थी। यह केन्द्र रक्तजनित वंशानुगत विकारों का गहन अध्ययन करेगा और रोग की समय पर पहचान कर चिकित्सा सेवा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में गांधी स्मारक चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

नारी सशक्तिकरण में अग्रणी मध्यप्रदेश

नारी सशक्तिकरण के नव प्रतिमान गढ़ते मध्यप्रदेश ने सफलता की अनेकों कहानियां लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे सतत प्रयासों ने महिलाओं को स्वाबलंबी और आत्मनिर्भर बनाया है। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत किया है। साथ ही पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। उद्यमी महिलाओं को राज्य सरकार 2 प्रतिशत दर से ऋण भी उपलब्ध करा रही है। आजीविका मिशन के माध्यम से 40 लाख से अधिक महिलाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा गया है।

राज्य सरकार के वादों और इरादों में कोई अंतर नहीं है। राज्य सरकार ने माता-बहनों और बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नित नई योजनाएं चलाई हैं, जिनके परिणाम उत्साह बढ़ाने वाले हैं। इन प्रयासों के चलते ही मध्यप्रदेश में महिलाएं अब मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होकर उभरी हैं।बेटियां वरदान कहीं जाने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के मंत्र को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आत्मसात करते हुए लाड़ली बहनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए दिन-रात एक कर दिए हैं। उनके सफल प्रयासों की सफलताओं के नवांकुर आज राज्य को अलंकृत कर रहे हैं। महिलाओं को मजबूर से मजबूत बनाने का अभियान आज उनके सशक्त और आत्मनिर्भरता की कहानी उनकी जुबानी कह रहा है। देश के कई राज्यों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर मध्यप्रदेश द्वारा उठाए गए कदमों को सराहा है और अपने राज्यों में लागू भी किया है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से राज्य की लगभग एक करोड़ 29 लाख महिलाओं को मासिक 1250 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। महिला सशक्तिकरण की यह अनूठी पहल अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय होकर क्रियान्वित की जा रही है। महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों ने लाड़ली बहना योजना को मील का पत्थर मानते हुए अपनाया है।

मध्यप्रदेश की पहचान 20 वर्ष पहले तक एक कुपोषित राज्य के रूप में हुआ करती थी। अब यह बीते जमाने की बात हो गई है। मध्यप्रदेश ने कुपोषण के खिलाफ लंबी और चरणबद्ध लड़ाई लड़ते हुए कामयाबी हासिल की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -3 वर्ष (NFHS-3) 2005-06 और वर्ष 2019-21 के जारी सर्वेक्षण के तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार ने कुपोषण के खिलाफ कितनी ईमानदारी से जंग लड़ी और सफलताएं अर्जित की। वर्ष 2005-06 की बात करें तो उन दिनों 60% बच्चे अपनी उम्र के अनुसार कम वजन के होते थे, लेकिन वर्ष 2020-21 में यह अंतर घटकर 33% हो गया है। मध्यप्रदेश को कुपोषण के खिलाफ जंग में मिली इस सफलता के फलस्वरुप देश में तीसरा स्थान प्राप्त हो गया।राज्य सरकार ने गर्भस्थ महिलाओं और शिशुओं की सुरक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी बाकी नहीं रखी। आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन, रखरखाव एवं संचालन मध्यप्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहा है। इस दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की 12 हजार 670 मिनी आंगनवाडी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाडी केन्द्र के रूप में उन्नयन किए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिये पर्यवक्षको के 476 नवीन पद, 12 हजार 670 आंगनवाडी सहायिका सहित कुल 13 हजार 146 नवीन पद स्वीकृत किए गए है।

अटल बिहारी वाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। आंगनबाड़ी केदो में मंगल दिवस मनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में एम्स के सहयोग से गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल की जा रही है। माता एवं शिशु के चेहरे की मुस्कान के लिए राज्य सरकार स्वयं को न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं है। राज्य की 73.40 लाख हितग्राही महिलाएं आधार से पंजीकृत हैं। राज्य में लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है। बाल विवाह के मामलों में भी काफी कमी आई है।

"बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ" राज्य सरकार का ध्येय मंत्र रहा है और इस दिशा में बेटियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल और कॉलेज के लिए स्कूटी वितरण का कार्य किया जा रहा है जिससे उनकी शिक्षा की सुविधा में कोई कठिनाई न आए। राज्य सरकार ने बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, जेईई, जज, सीए आदि परीक्षाओं की तैयारी का खर्च उठाने का जिम्मा स्वयं ले रखा है ताकि माता-पिता को इसके बोझ तले ना दबना पड़े। कक्षा 12वीं के बाद स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर बेटियों को राज्य सरकार 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। राज्य सरकार की यही मंशा रही है कि प्रदेश की हर बेटी अपने सपने पूरा कर सके।

महिला सुरक्षा को अपनी उच्च प्राथमिकता में रखते हुए राज्य सरकार हमेशा गंभीरता से कार्य कर रही है। आपातकालीन स्थिति या किसी भी तरह के संकट में उनकी सहायता के लिए राज्य के सभी 57 जिलों में वन स्टॉप केंद्र संचालित हैं। साथ ही 181 हेल्पलाइन नंबर की सेवा प्रदाय की जा रही है। मध्यप्रदेश में महिलाओं को सफल, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं अभियानों की यह सफलता कही जाएगी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को योजना प्रारंभ से वर्ष 2022-23 तक लगातार 5 साल राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने महिला अपराधों को रोकने तथा उसे प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शौर्य दल बनाए गए हैं, जिसमें 22 लाख महिला एवं बालिकाएं सदस्य बनाई गई है।

अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण के लिये 41 ई-चेकगेट की होगी स्थापना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रदेश की सभी 7 हजार खदानों को किया जियो टैग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में अवैध परिवहन रोकने के लिये एआई आधारित 41 ई-चेकगेट की स्थापना की जा रही है। इन ई-चेकगेटों पर वेरीफोकल कैमरा, आरएफआईडी लीडर, ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रीडर की सहायता से खनिज परिवहन में संलग्न वाहनों की जाँच की जायेगी।परियोजना में पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में खनिज परिवहन के लिये महत्वपूर्ण मार्ग के 4 स्थानों पर ई-चेकगेट स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अवैध परिवहन की निगरानी के लिये राज्य स्तर पर भोपाल में कमॉण्ड एवं कंट्रोल सेंटर और जिला भोपाल एवं रायसेन में जिला कमॉण्ड सेंटर स्थापित किये गये हैं। माह दिसम्बर 2024 तक सभी 41 ई-चेकगेट की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिये उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना भी प्रारंभ की गयी है। इसके द्वारा प्रदेश की सभी 7 हजार खदानों की जियो टैग कर खदान क्षेत्र का सीमांकन किया गया है। यह परियोजना पूर्ण रूप से लागू होने पर अवैध खनन को चिन्हित कर प्रभावी रोकथाम की जा सकेगी। परियोजना के लागू होने पर स्वीकृत खदान के अंदर थ्री-डी इमेजिंग एवं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर उत्खनित खनिज की मात्रा का सटीक आंकलन किया जा सकेगा।

बहादुर बहनों का साहस और संघर्ष प्रेरणास्पद : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले के खकराचौरई गांव में भेड़िए का साहस से सामना करने वाली श्रीमती भुजालो बाई से वीडियो कॉल कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री ने भुजलो बाई के साहस की सराहना करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से एक लाख रूपए भी स्वीकृत किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहादुर बहनों का साहस और संघर्ष प्रेरणास्पद है। श्रीमती भुजलो बाई के उचित इलाज के लिए कलेक्टर छिंदवाड़ा को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक होने पर एयरलिफ्ट कर भोपाल में उपचार कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीड़िता के परिजन से भी हाल-चाल जाने, साथ ही इलाज का पूरा खर्चा उठाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हों, ईश्वर से यही प्रार्थना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल से कोटा रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री निवास से श्रीमती भुजलो बाई से वीडियो कॉल कर चर्चा की।

उल्लेखनीय है की फसल की रखवाली के दौरान शुक्रवार की सुबह छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा रेंज के अंतर्गत खकरा चौरई गांव के पास खेत में 65 वर्षीय भुजलो बाई और 55

वर्षीय दुर्गाबाई सो रही थीं, तभी श्रीमती भुजलो बाई पर भेड़िए ने हमला किया और उनके एक हाथ का अंगूठा चबा लिया। चिल्लाने की आवाज आई तो दुर्गाबाई, भुजलो को बचाने पहुंची। भेड़िए ने भुजलो बाई के हाथ और सिर पर चोट पहुंचाई। आधे घंटे तक महिलाओं और भेड़िए के बीच संघर्ष चलता रहा। इसके बाद साहसी भुजलो ने पास रखे फावड़े से वार कर भेड़िए का अंत कर दिया। भेड़िए के हमले से घायल दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बताया गया कि श्रीमती दुर्गाबाई का उपचार पूर्ण होने पर उन्हें जिला अस्पताल छिंदवाड़ा से डिस्चार्ज किया जा चुका है।

अब तक 2 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के बनाये जा चुके हैं आयुष्मान कार्ड

वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी

अब तक 2 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के बनाये जा चुके हैं आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान ऐप से स्वयं भी हितग्राही कर सकते हैं पंजीयन

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति पर समस्त संलग्न अधिकारियों, आशा कार्यकर्ता, एएनएम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुँचाने के लिए संकल्पबद्ध है।वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत योजना डॉ योगेश भरसट ने बताया कि मध्यप्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के अब तक 2 लाख 667 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। वहीं केरल में अब तक 1 लाख 76 हज़ार 167 कार्ड बनाए गए हैं।

डॉ. भरसट ने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रतिदिन लगभग 30 से 35 हज़ार वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। डॉ भरसट ने बताया कि लक्षित 34 लाख 73 हज़ार 325 आयुष्मान कार्ड 15 जनवरी तक बना लिये जाएँगे। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। आशा कार्यकर्ता, एएनएम और सीएचओ के द्वारा डोर टू डोर दस्तक दी जा रही है। विशेष कैंप आयोजित किये जा रहे हैं।

हितग्राही घर बैठे ही बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड

सीईओ डॉ भरसट ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के अंतर्गत एक नई पहल शुरू की गयी है, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए समर्पित है। योजना का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2024 को किया गया। उन्होंने बताया कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिक अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in या आयुष्मान ऐप https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beneficiaryapp के माध्यम से भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। हितग्राही स्वयं सेल्फ रजिस्ट्रेशन विकल्प का चयन कर घर बैठे ही अपना कार्ड बना सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए "वय वंदना कार्ड"

डॉ. भरसट ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को "वय वंदना कार्ड" नामक एक विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिनके परिवार पहले से आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर हैं, उन्हें इस कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त 5 लाख तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज मिलेगी। यह टॉप-अप केवल वृद्धजनों के लिए है और परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं) के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा।

पहले से रजिस्टर्ड हितग्राहियों को वय वंदना कार्ड के लिये पुनः पंजीयन करना अनिवार्य

डॉ भरसट ने बताया कि पहले से रजिस्टर्ड आयुष्मान हितग्राहियों को "वय वंदना कार्ड" के लिए पुनः पंजीकरण करना होगा। वय वंदना कार्ड प्राप्त करने पर वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉप-अप मिलेगा, जिससे कुल 10 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल सकेगा। यह अतिरिक्त टॉप-अप केवल वृद्धजनों के लिए ही होगा, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को पूर्व निर्धारित 5 लाख का कवरेज मिलेगा। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख तक की वार्षिक कवरेज प्रदान की जाएगी।

अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी को एक विकल्प का करना होगा चयन

डॉ भरसट ने बताया कि जो वरिष्ठ नागरिक केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), या आयुष्मान सीएपीएफ जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अपनी मौजूदा योजना या आयुष्मान भारत योजना में से किसी एक का चयन करना होगा। निजी स्वास्थ्य बीमा योजना या कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना में शामिल वरिष्ठ नागरिक भी आयुष्मान योजना के तहत लाभ ले सकेंगे।

ई-केवाईसी के लिये तीन माध्यम उपलब्ध

डॉ भरसट ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की पहचान के लिए योजना में आधार कार्ड को मुख्य दस्तावेज माना गया है। ऐसे नागरिक जिनके आधार कार्ड में पूर्ण जन्मतिथि न होकर जन्मवर्ष है, उन्हें 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर 70 वर्ष पूर्ण होने पर पात्र माना जायेगा। हितग्राहियों की पहचान के लिए थंब इम्प्रैशन, आईरिस स्कैन और मोबाइल ओटीपी तीन माध्यम का प्रावधान है, ताकि सहजता से हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जा सके।

किसी भी पद पर रहे, मित्रता भाव हमेशा बनाए रखना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विद्यार्थी इच्छाशक्ति मजबूत रखें, लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोटा में विद्यार्थियों के साथ साझा किए अपने अनुभव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विद्यार्थियों को अपना जुनून हमेशा कायम रखना चाहिए। इच्छाशक्ति जितनी दृढ़ होगी, लक्ष्य उतना ही आसान होगा। उन्होंने कहा कि जीवन में किसी भी पद पर पहुंचे, मित्रता का प्रेमभाव हमेशा बनाए रखना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण श्रीकृष्ण और सुदामा की दोस्ती का है। उनकी दोस्ती 11 वर्ष की उम्र में हुई थी और जब वे द्वारका के राजा बने तब भी उनकी दोस्ती ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राजस्थान के कोटा जिले में एलन शिक्षण संस्थान के समउन्नत भवन में विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे थे। प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विद्यार्थियों ने गजहार पहनाकर स्वागत किया गया।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में पहली बार विधायक बनने के साथ ही मुख्यमंत्री बने और लगातार तीन बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के बाद वे पहली बार सांसद बनें और पहली बार में ही देश के प्रधानमंत्री बनें। इसके बाद लगातार सांसद बने और प्रधानमंत्री भी। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक भी बनाई। आर्थिक दृष्टि से गुजरात देश के अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी है।

समाज सेवा के लिए छोड़ी डॉक्टरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैंने अपने शैक्षणिक काल से ही अपना लक्ष्य समाज सेवा के रूप में निर्धारित किया था। वर्ष 1982 में मेरा चयन मेडिकल कॉलेज के लिए हो गया था, परंतु समाज सेवा के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने मेडिकल में प्रवेश न लेते हुए, बीएससी की उपाधि प्राप्त की। मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहते हुए राजनीति में सक्रिय रह सका। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के तीन मूल मंत्र हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को आत्मसात करना चाहिए। पर्याप्त नींद लें, नियमित रूप से व्यायाम करें और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने बतायाकि अपने लक्ष्य पर शुरू से ही ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण 11 वर्ष की आयु में मथुरा से राजस्थान होते हुए मध्यप्रदेश के उज्जैन पधारे थे। भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी यात्रा के दौरान प्रदेश में जहां-जहां विश्राम किया या ठहरे उन स्थानों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। भगवान श्रीकृष्ण ने अपने शिक्षा काल में जिन ग्रंथों का अध्ययन किया, उन ग्रंथों का सार गीता में समाया है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विद्यार्थी निराशा को अपने आप पर हावी न होने दें। जब निराश हो जाए तो राजनेताओं की तरफ देखें, वे बार-बार चुनाव लड़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कई बार विद्यार्थी लक्ष्य प्राप्ति की दौड़ में पीछे रह जाते हैं तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, जबकि दोगनी ऊर्जा के साथ फिर प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एलन शिक्षण संस्थान मध्यप्रदेश के उज्जैन में अपने संस्थान प्रारंभ करें, जिससे मध्यप्रदेश के छात्रों को भी स्थानीय स्तर पर लाभ प्राप्त हो सकेगा।

गंभीरता से करायें निर्वाचन प्रक्रिया

निर्वाचन प्रक्रिया बहुत संवेदनशील होती है, इसे पूरी गंभीरता से करायें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अभिषेक सिंह ने यह बात आयोग में नव-नियुक्त नायब तहसीलदारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। श्री सिंह ने शासकीय सेवा के अनुभवों को भी साझा किया। उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री प्रदीप शुक्ला ने नगरीय निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया का हर कदम बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही के भी गंभीर परिणाम होते हैं। उन्होंने मतदाता सूची तैयार करने से लेकर परिणाम घोषित होने तक की जानकारी दी।

उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती संजू कुमारी ने पंचायत निर्वाचन और आयोग द्वारा किये गये आईटी नवाचार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन में पेपरलेस बूथ का सफल प्रयोग किया जा चुका है। प्रशिक्षण में नायब तहसीलदारों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। इस दौरान उप सचिव श्री मनोज मालवीय और श्री सुतेश शाक्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

संतुलित औद्योगिक विकास पर केन्द्रित होगी नर्मदापुरम् में आरआईसी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के संतुलित विकास के लिये निरंतर सभी अंचलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। अगली आरआईसी आगामी 7 दिसम्बर को नर्मदापुरम में हो रही है। नर्मदापुरम् क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्र-संस्करण इकाइयां और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग बहुतायत में हैं। नर्मदापुरम्, हरदा, और होशंगाबाद में पहले से स्थापित उद्योगों के साथ-साथ कृषि प्र-संस्करण, सोयाबीन तेल, मसाला उत्पादन और दुग्ध प्र-संस्करण जैसे उद्योग यहाँ की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र की खनिज संपदा का उपयोग कर निर्माण और अन्य उद्योगों से भी स्थानीय विकास को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

छठवीं आरआईसी का आयोजन 7 दिसंबर 2024 को नर्मदापुरम् के डिवीजनल आईटीआई में किया जाएगा। पिछली पांच रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अनुभवों से प्रेरित होकर, इस कॉन्क्लेव का नर्मदापुरम् क्षेत्र में आयोजन उद्योगों की वृद्धि, निवेश की संभावनाओं और रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है। नर्मदापुरम आरआईसी में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, MSME और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से प्रदेश में एक उद्योग-हितैषी वातावरण बना है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। नर्मदापुरम् और इसके आसपास के क्षेत्र जैसे होशंगाबाद, हरदा में एमएसएमई, कृषि आधारित उद्योग, और पर्यटन के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।

कॉन्क्लेव का उद्देश्य सभी क्षेत्रों का संतुलित और समन्वित आर्थिक विकास करना है। इस कॉन्क्लेव से नर्मदापुरम् और इसके आस-पास के क्षेत्रों में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

यह आरआईसी नर्मदापुरम् और आसपास के क्षेत्रों के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर को उद्योगों के साथ जोड़ा जाएगा। पचमढ़ी, जो न केवल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है बल्कि यहाँ की अनूठी जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन, अब निवेशकों के लिये नया आकर्षण बनेंगा। साथ ही नर्मदा नदी तट पर औद्योगिक और पर्यटन दोनों क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएँ हैं। इस कॉन्क्लेव में कृषि, MSME, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और खनिज जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

नर्मदापुरम् और पचमढ़ी, जो पहले से ही प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं, अब औद्योगिक दृष्टिकोण से भी नई ऊँचाइयों को छुएंगे। इस कॉन्क्लेव से औद्योगिक, पर्यटन और सामाजिक विकास के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑफ मेरिट में सेमी-फाइनलिस्ट सम्मान

एमएसएमई विभाग की युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑफ मेरिट में सेमी-फाइनलिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया है।यह सम्मान मध्यप्रदेश में एमएसएमई को सशक्त बनाने, उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा पारदर्शिता के क्षेत्र मे प्रदान किया गया है।उल्लेखनीय है कि योजना के तहत 16हजार 331 युवाओं को 1056 करोड़ 42 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोडने के लिये बैंक के माध्यम से रियायती व्याज दर पर कोलेटरल मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत औद्योगिक (विनिर्माण) इकाई के लिये 50 हजार से 50 लाख रुपये तक और सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 50 हजार से 25 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

योजना के प्रावधान

उद्यम स्थापना के इच्छुक आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। आवेदक न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा परिवार की आय रूपये 12 लाख से अधिक न हो। साथ ही आवेदक किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नही हो और किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए।

योजनान्तर्गत हितग्राही को 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक, वार्षिक आधार पर प्रदान किये जाने का प्रावधान है। साथ ही ऋण गारंटी शुल्क, प्रचलित दर पर, अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में जाने का भी प्रावधान है।

भगवान बिरसा मुंडा की 149वीं जयंती : एक ऐतिहासिक प्रेरणा

भारत के समृद्ध इतिहास में भगवान बिरसा मुंडा का नाम एक ऐसे वीर योद्धा और समाज-सुधारक के रूप में अंकित है, जिन्होंने अपने जीवन को जनजातीय समाज की उन्नति और उनके अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। देश में हर साल 15 नवम्बर को उनकी जयंती पर भारत में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिन न केवल उनकी शहादत और योगदान को याद करने का है, बल्कि यह जनजातीय समुदाय की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, अनवरत संघर्ष और स्वाभिमान का उत्सव भी है।

भगवान बिरसा मुंडा का जीवन और उनका संघर्ष

बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवम्बर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में एक साधारण मुंडा परिवार में हुआ था। उनका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था और उन्हें बाल्यावस्था से ही आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। सामाजिक असमानता, अत्याचार और विदेशी शासकों द्वारा जनजातियों पर निरंतर हो रहे शोषण ने बिरसा मुंडा के अंतर्मन को विद्रोह की भावना से भर दिया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लागू जमींदारी प्रथा, धर्मांतरण और जनजातियों के पारम्परिक जीवन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया।

उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व

बिरसा मुंडा जी ने "उलगुलान" नामक जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया, जो अंग्रेजी शासन और उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ था। "उलगुलान" का अर्थ है 'महान विद्रोह'। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि नीतियों, जबरन धर्मांतरण और जनजातियों की पारम्परिक जीवनशैली में दखल देने वाले कानूनों के खिलाफ आवाज उठाना था। भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस आंदोलन ने पूरे क्षेत्र में जनक्रांति की लहर पैदा कर दी और उन्हें "धरती आबा" या "धरती पिता" या धरा पितृ के रूप में सम्मानित किया जाने लगा।

भगवान बिरसा मुंडा का समाज सुधारक के रूप में योगदान

भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने तत्कालीन जनजातीय समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे अंध-विश्वास, जाति-भेद, नशाखोरी, जातीय संघर्ष और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाई। उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें एकता में रहने का संदेश दिया। बिरसा मुंडा ने "बिरसाइत" नामक एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया, जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को आचार-विचार की शुचिता, सादगी और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की स्थापना

वर्ष 2021 में केन्द्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का सम्मान करना है। इस दिन देशभर में जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर, उनकी परंपराओं और उनके गौरवशाली इतिहास को समझने और सम्मानित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह दिवस जनजातीय समाज के संघर्षों और उनके योगदान को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा का योगदान अतुलनीय है। वे न केवल अपने क्षेत्र की जनजातियों के नेता थे, बल्कि उनके संघर्ष और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नई दिशा दी। उनके "उलगुलान" आंदोलन ने अन्य जनजातीय समुदायों को भी संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी करने की प्रेरणा दी।

सड़क और पुल निर्माण में नई तकनीकों के उपयोग पर दो दिवसीय सेमिनार सम्पन्न

सड़क निर्माण में चुनौतियों, नई तकनीकों और ईपीसी अनुबंधों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से आयोजित सड़क और पुल निर्माण पर दो दिवसीय सेमिनार रविवार को सम्पन्न हुआ। समापन पूर्व द्वितीय दिवस विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। इसमें नई निर्माण तकनीकों और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंधों पर गहन चर्चा की गई।

सत्र की शुरुआत भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के महासचिव श्री एस.के. निर्मल के वक्तव्य से हुई। इसमें उन्होंने ईपीसी अनुबंधों का विस्तृत परिचय दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार ईपीसी अनुबंध सड़क निर्माण क्षेत्र में अनुशासन और समयसीमा को सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), भोपाल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री एस.के. सिंह ने ईपीसी अनुबंधों में ग्राहक की भूमिका और शेड्यूल की तैयारी पर चर्चा की। बताया गया कि कैसे अनुबंधों में समयसीमा का पालन किया जाना आवश्यक है और इसके लिए पूर्व नियोजन महत्वपूर्ण होता है।

दोपहर के सत्र में, ईपीसी अनुबंधों में अप्रूविंग इंजीनियर (एई) की भूमिका पर चर्चा की गई। इस सत्र की अध्यक्षता आईआरसी के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा पीडब्ल्यूडी के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ डॉ. महेश कुमार ने की। उनके साथ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के पूर्व महानिदेशक श्री आई.के. पांडे ने भी इस सत्र में भाग लिया। श्री पांडे ने ईपीसी अनुबंधों में उत्पन्न होने वाले विवादों और चुनौतियों पर विचार साझा किए। सत्र में ठेकेदारों के दृष्टिकोण से भी अनुबंधों में आने वाली समस्याओं और उनके अनुभवों को प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर निर्माण क्षेत्र में नई तकनीकों पर पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इस चर्चा में आईआरसी के महासचिव श्री एस.के. निर्मल, मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर-इन-चीफ श्री आर.के. मेहरा, एनएचएआई, भोपाल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री एस.के. सिंह, आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर एम.ए. रेड्डी और सीएसआईआर-सीआरआरआई, नई दिल्ली के डॉ. अभिषेक मित्तल जैसे विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। पैनल ने निर्माण में नई तकनीकों के

विकास, उनकी संभावनाओं और उनसे जुड़े चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। पैनल ने विशेष रूप से यह चर्चा की कि किस प्रकार इन तकनीकों का उपयोग करके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और गति को बेहतर किया जा सकता है।

सत्रों के बाद प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित प्रतिभागियों ने सड़क निर्माण की प्रक्रिया में आने वाली विभिन्न चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। सेमिनार के समापन समारोह में सभी प्रतिभागियों ने ईपीसी अनुबंधों और नई तकनीकों के उपयोग की महत्ता को समझा। विशेषज्ञों ने इस सेमिनार को निर्माण क्षेत्र में नई दिशा देने वाला बताया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया।

यह सेमिनार निर्माण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, इंजीनियरों और ठेकेदारों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ, जिसमें उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया। ईपीसी अनुबंधों और नई तकनीकों पर की गई गहन चर्चाओं ने निर्माण प्रक्रिया में सुधार और दक्षता को बढ़ाने के नए अवसर प्रदान किए हैं।

प्रदेश के 22 जिलों के 200 छात्रावास एवं स्कूलों की मरम्मत एवं रेन वॉटर रूफिंग के लिये प्रस्ताव

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत होंगे विकास कार्य

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि देश के सभी जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। जनजातियों के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 5 वर्ष की अवधि के लिये है, जो वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक क्रियान्वित होगा। इसमें केन्द्र सरकार के 18 मंत्रालयों/विभागों की 25 प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं/सेवाओं/सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन कर जनजातियों को सहज लाभ दिलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में प्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखंडों में स्थित 11 हजार 377 जनजातीय बहुल गांवों का सर्वांगीण विकास

किया जायेगा। इस अभियान से इन 51 जिलों में 43 जनजातीय समुदायों के 18 लाख 58 हजार 795 परिवार निवास करते हैं, जिनकी कुल 93 लाख 23 हजार 125 लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि अभियान में केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे छात्रावास, आश्रम शालाएं एवं आदर्श विद्यालय, जेएसएस आदि के उन्नयन, विस्तार के साथ इन संस्थानों छत पर सोलर सिस्टम और रेन वॉटर रूफिंग आदि की स्थापना के लिये प्रस्ताव मांगे गये हैं। देशभर की कई संस्थाओं में इस प्रकार के विकास कार्य किये जाने हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में तेजी से कार्यवाही कर केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव को वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 22 जिलों में इस प्रकार के कार्यों के लिये अधिकृत प्रस्ताव भेज दिया है।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को बालाघाट, छिंदवाड़ा, सतना, सीधी, हरदा, उज्जैन, धार, रायसेन, नर्मदापुरम, शहडोल, दतिया, इंदौर, सिवनी, रतलाम, उमरिया, बड़वानी, राजगढ़, मंडला, खरगौन, बैतूल, पन्ना एवं गुना जिले में स्थित कुल 200 छात्रावासों एवं स्कूलों की मरम्मत तथा इनमें रेन वॉटर रूफिंग की स्थापना के लिये 388 करोड़ 56 लाख रूपये के विकास कार्य प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। प्रस्ताव अनुसार बालाघाट जिले की 12 शिक्षण संस्थाओं, छिंदवाड़ा में 21, सतना में 2, सीधी में 3, हरदा में 4, उज्जैन में 2, धार में 21, रायसेन में 3, नर्मदापुरम में 4, शहडोल में 9, दतिया में 1, इंदौर में 5, सिवनी में 14, रतलाम 12, उमरिया में 8, बड़वानी में 15, राजगढ़ में 1, मंडला में 23, खरगौन में 12, बैतूल में 23 एवं पन्ना और गुना में 1-1 छात्रावास में यह विकास कार्य कराये जायेंगे।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि इसके अलावा छात्रावास अधीक्षको के आवासों में भी सभी सिविल, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिक एवं मल-जल निस्तार व्यवस्था संबंधी जरूरी कार्य कराये जायेंगे।

इंजीनियरिंग दुनिया को बेहतर बनाने की कला है - राज्यपाल श्री

मानव को शिक्षा ही समर्थ और संस्कारवान बनाती है - राज्यपाल, इंजीनियरिंग हर तरह के विकास का मूल है - उप मुख्यमंत्री,ज्ञान परंपरा को समाहित कर बनाई गई है नई शिक्षा नीति - उच्च शिक्षा मंत्री

रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि इंजीनियरिंग दुनिया को बेहतर बनाने की कला है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधोसंरचना विकास में इंजीनियरों का बहुत बड़ा योगदान है। मानव को शिक्षा ही समर्थ और संस्कारवान बनाती है। रीवा इंजीनियरिंग कालेज बहुत गौरवशाली है। यहाँ अपनी प्रतिभा, योग्यता और परिश्रम से देश का नाम ऊँचा करने वाले कई पूर्व छात्र उपस्थित हैं। इनसे मार्गदर्शन और प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी सफलता के शिखर छुएगी। हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है। आज पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ रही है। 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है। इसे विकसित बनाने में हम जहाँ भी हैं वहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर देश के विकास में योगदान दें।राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विन्ध्य की धरा सफेद बाघ की जननी, चिरहुलानाथ स्वामी और महामृत्युंजय भगवान की कृपा पात्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की 60 वर्ष की विकास गाथा सफलताओं से भरी है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि इंजीनियरिंग हर तरह के विकास का मूल है। रीवा में विकास के कई बड़े कार्य हुए हैं। इन सब में इंजीनियरों का सर्वाधिक योगदान रहा है। यह इंजीनियरिंग का ही चमत्कार है कि गुढ़ की पथरीली उजाड़ पहाड़ी में 750 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र सफलता की गाथा कह रहा है। रीवावासियों को गर्व है कि उनके सोलर प्लांट की बिजली से दिल्ली की मैट्रो ट्रेन दौड़ती है। विन्ध्य 40 मिलियन टन सीमेंट और 15 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। विन्ध्य में इंजीनियरों के परिश्रम से अधोसंरचना का जो विकास हुआ है उसमें विन्ध्य के विकास की गाड़ी अब तेजी से दौड़ रही है। रीवा में पाँच साल में सिंचाई क्षमता तीन लाख से बढ़कर नौ लाख एकड़ हो जाएगी। इंजीनियरिंग कालेज के पूर्व छात्र मिलकर कालेज के विकास का रोडमैप बनाएंगे और इसे देश के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थान के रूप में विकसित करेंगे।उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म और दर्शन की परंपरा रही है। इसी ज्ञान परंपरा को समाहित करके नई शिक्षा नीति बनाई गई है। हमारे देश में आज भी हजारों साल पुराने स्मारक स्थापत्य और विज्ञान की सफलता की कहानी कहते हुए विद्यमान हैं। भारत के एक इंजीनियर ने 13वीं शताब्दी में चीन में बीजिंग शहर और दुनिया के सबसे बड़े मंदिर कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर की डिजाइन बनाई थी। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा और अक्षय स्त्रोत है। इसीलिए हमारे देश में सूर्य की पूजा की जाती है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के संबंध में जो प्रस्ताव मिले हैं उन पर दिसम्बर 2024 में आयोजित बैठक में निर्णय लिए जाएंगे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कॉलेज की स्मारिका के प्रथम पृष्ठ का डिजिटल विमोचन किया। राज्यपाल ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में सांसद श्री जनार्दन मिश्र विधायक मनगवां इंजीनियर नरेन्द्र प्रजापति, अध्यक्ष नगर निगम श्री व्यंकटेश पाण्डेय तथा बड़ी संख्या में पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संदीप पाण्डेय ने किया।

राज्यपाल ने इंजीनियरिंग कालेज के स्वागत द्वार तथा ओपन थियेटर का किया लोकार्पण

राज्यपाल ने इंजीनियरिंग कालेज के पूर्व विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भव्य स्वागत द्वार का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने कॉलेज के प्रवेश के द्वार के समीप ही बनाए गए मुक्ताकाश ओपन थियेटर का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर बाबा अलाउदीन खान के द्वारा स्थापित मैहर बैण्ड के कलाकारों ने मोहक धुन प्रस्तुत की। इसका निर्माण 55 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। राज्यपाल श्री पटेल ने इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई भविष्य के ज्ञान-विज्ञान की झलक देने वाली टेकफेस्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए विद्यार्थियों से उनके द्वारा प्रदर्शित उपकरणों की जानकारी ली। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, सांसद श्री जनार्दन मिश्र, विधायक इंजीनियर नरेन्द्र प्रजापति तथा अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने बीहर रिवर फ्रंट का किया लोकार्पण

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने रीवा शहर के मध्य से प्रवाहित बीहर नदी के तट पर बनाये गये बीहर रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बीहर रिवर फ्रंट रीवा के लिये अनुपम सौगात है। उन्होंने अनुष्ठानिक रीति से मंगलाचरण के बीच शिला पट्टिका का अनावरण कर रिवर फ्रंट जनता को समर्पित किया। राज्यपाल श्री पटेल का का उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा के प्रसिद्ध सुपारी से निर्मित विन्हर्ता भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भेंट कर अभिनंदन किया।

राज्यपाल को रिवर फ्रंट के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में नदी के एक किनारे में 1600 मीटर लम्बाई का रिवर फ्रंट का निर्माण कराया गया है। बीहर नदी के अविरल जल प्रवाह को देखकर राज्यपाल जी अविभूत हो गये। राज्यपाल ने पचमठा आश्रम पहुंचकर माँ बीहर की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने पचमठा के ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व से राज्यपाल को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कैमोर पर्वत से निकली बीहर सलिला के तट पर स्थित रीवा पचमठा का इतिहास अति प्राचीन है। जगदगुरू शंकराचार्य जी ने धर्म दिग्विजय अभियान के दौरान यहां प्रवास किया था। आचार्य शंकर ने चारों दिशाओं में ज्योर्तिमठ, श्रृंगेरीमठ, गोवर्धनमठ तथा द्वारिकामठ की स्थापना की थी। उनकी परिकल्पना मध्यभारत में पाँचवे मठ की स्थापना की थी यह पाँचवा मठ है। पचमठा में चारों मठों की प्रतिकृति बनाकर इनका इतिहास प्रदर्शित किया गया है। राज्यपाल श्री पटेल ने पचमठा आश्रम के अतिप्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की।उल्लेखनीय है कि बीहर रिवर फ्रंट के प्रथम चरण का निर्माण म.प्र. ग्रह निर्माण मंडल एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा 25 करोड़ रूपये की लागत से किया गया है। इसके तहत नदी के वांये तट में बाबा घाट से कोतवाली घाट तक 1600 मीटर लम्बे रिवर फ्रंट में ग्रेविटी बाल, पाथवे ग्रीन टी एरिया का निर्माण किया गया है।

पर्यटकों की संतुष्टि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता-राज्य मंत्री श्री लोधी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुरुप 2047 का विज़न डॉक्यूमेंट करें तैयार

पर्यटकों और अतिथियों के रिव्यू के लिए होटलों में रखे सुझाव बॉक्स क्षेत्रीय और स्थानीय व्यंजनों को होटल के मेनू में प्रमुखता से करे शामिल पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए होटलों की संख्या और कमरों में करें वृद्धि सैर-सपाटा के आवंटन की प्रक्रिया को करें एक माह में पूर्ण हनुवंतिया को फूल-टाइम पर्यटन स्थल बनाए

अनुग्रह सहायता राशि 50 हजार से दुगनी कर एक लाख रुपए राज्य पर्यटन विकास निगम की हुई समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप 2047 का विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करें। विज़न डॉक्यूमेंट में पर्यटन गतिविधियों की विस्तार और निर्माण की योजना बनाएं, जिससे प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सभी पर्यटकों को उच्च श्रेणी का पर्यटन अनुभव भी मिले। यह निर्देश पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने पर्यटन राज्य विकास निगम में समीक्षा बैठक के दौरान दिए। राज्य मंत्री श्री लोधी ने कहा कि पर्यटकों की संतुष्टि हमारी सर्वोच्च प्राथमिका है। पर्यटकों के द्वारा दिए जा रहे रिव्यू का विशेष ध्यान दे। होटल में सुझाव के लिए बॉक्स रखें। अतिथियों की रिव्यू की मॉनिटरिंग के लिए स्टेट लेवल डैशबोर्ड बनाएं। पॉजिटिव रिव्यू को वेबसाइट पर प्रदर्शित करें । नेगेटिव रिव्यू को गंभीरता के लेकर होटल की सुविधाओं में सुधार करें। राज्य मंत्री श्री लोधी ने निर्देश दिए कि होटल में स्थानीय व्यंजनों को परोसा जाए। क्षेत्रीय और स्थानीय व्यंजनों को मेनू में प्रमुखता से शामिल करे और प्रचारित करें। नर्मदापुरम में होने वाली रीजनल इन्वेस्टर समिट में अतिथियों को स्थानीय और मिलेट व्यंजन परोसे। प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए होटलों की संख्या और कमरों में वृद्धि करें। पुराने होटलों का मूल्यांकन कर उन्हें रेनोवेट करने की योजना बनाए। कम ऑक्युपेंसी वाले होटलों और संपत्तियों के उचित निराकरण की योजना बनाए। सैर-सपाटा के आवंटन की प्रक्रिया को एक माह में पूर्ण करें। राज्य मंत्री श्री लोधी ने कहा कि हनुवंतिया प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां अधिक संख्या में होटल और रिजॉर्ट निर्माण की योजना बनाएं। इसके साथ अधिक से अधिक पर्यटन गतिविधियों का संचालन करें ताकि वर्षभर पर्यटक हनुवंतिया आ सकें। धार्मिक लोक के निर्माण और पर्यटन सुविधाओं के विकास कार्यों को प्रमुखता से समय सीमा में पूरा करे। राज्य मंत्री श्री लोधी ने निर्देश दिए कि पर्यटन निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि 50 हजार से दुगनी कर एक लाख रुपए की जाएं। राज्य मंत्री श्री लोधी को प्रेजेंटेशन के माध्यम से पर्यटन निगम की संपत्तियों, गतिविधियों, उपलब्धियों, नवाचारों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति से अवगत कराया गया। इस अवसर पर प्रबंध संचालक राज्य पर्यटन विकास निगम श्री इलैया राजा टी. सहित पर्यटन निगम के अधिकारी उपस्थित रहें।

21 बैगा बहुल एवं 12 भारिया बहुल बसाहटों के हेबिटेट राइट को मिली मान्यता

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पीवीटीजी की बसाहटों का भी संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा डिण्डोरी जिले की 7 एवं मंडला जिले की 14, कुल 21 बैगा जनजाति बहुल बसाहटों के हेबिटेट राइट को मान्यता दे दी गई है। इसी प्रकार छिंदवाड़ा जिले में 12 भारिया जनजाति बहुल बसाहटों के हेबिटेट राइट को भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। पर्यावास अधिकार (हेबिटेट राइट) मिलने से आशय यह है कि इस विशेष अधिकार से पिछड़ी जनजातियों को उनकी पारम्परिक आजीविका स्त्रोत और पारिस्थितिकीय ज्ञान को सुरक्षित रखने में भरपूर मदद मिलेगी। ये अधिकार इन पीवीटीजी समुदायों को खुद के विकास के लिए शासकीय योजनाओं और विकास नीतियों/कार्यक्रमों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाते हैं।जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि हैबिटेट राइट्स की मान्यता मिलने के बाद ये पिछड़ी जनजातियां अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है। अब वे अपने परम्परागत जंगलों में अपनी आजीविका को बेहतर तरीके से चला रही हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह धरोहर के रूप में भी सौंप सकते हैं। हेबिटेट राइट मिलने से ये जनजातियां अब न केवल अपने जल, जंगल, जमीन, जानवर का संरक्षण करने के लिए सक्षम हुए हैं, बल्कि अपनी पारम्परिक कृषि, औषधीय पौधों, जड़ी-बूटियों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के यथा आवश्यकतानुसार उपयोग को लेकर भी स्वायत्त धारणाधिकारी (स्वतंत्र) हो गई हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सुदूर वन क्षेत्रों में बसीं बैगा और भारिया जनजातियां लंबे समय से जंगलों और पहाड़ियों में अपनी परम्परागत जीवन शैली जीने की आदी हैं। पहले इन जनजातियों के पास न तो अपनी जमीन का अधिकार था, न ही जंगल पर अपना नियंत्रण। यही उनकी संस्कृति और अस्तित्व के लिए एक बड़ा अवरोध था। बैगा और भारिया जनजातियां मध्यप्रदेश की विशेष रूप से पिछड़े एवं कमजोर जनजातियों (पीवीटीजी) में आती हैं। इनकी जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करती है। इनके लिए जंगल केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह उनकी परंपराओं, रीति-रिवाजों, और पहचान का अभिन्न हिस्सा है। ये समुदाय सरकार से अपने जंगल और जीवन पर अधिकार की सुरक्षा और अपनी देशज पुरा संस्कृति की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। सरकार ने इनकी इस मांग को गंभीरता से लिया और 21 बैगा बसाहटों तथा 12 भारिया बसाहटों के पर्यावास अधिकार (हैबिटेट राइट्स) को मान्यता प्रदान कर दी। हैबिटेट राइट केवल एक कानूनी अधिकार ही नहीं है, बल्कि इन पीवीटीजी की मूल पहचान और प्राकृतिक संस्कृति को बचाने की दिशा में सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

MP में 'जामताड़ा' की तरह चल रहा था फ्रॉड का अड्डा, 17 लड़कियां ऐसे बनाती थीं शिकार, हो गया भंडाफोड़

मध्य प्रदेश की स्टेट साइबर सेल ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो 'जामताड़ा' की तरह लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे.

प्रदेश की स्टेट साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो 'जामताड़ा' की तरह लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे. ये लोग डायमंड रिसर्च कंपनी के नाम पर लोगों से इन्वेस्ट करवा कर उनको ठगते थे. गिरोह मंदसौर में कॉल सेंटर चलाकर लोगों को शिकार बनाता था. मामले में साइबर सेल ने 22 युवक-युवतियों को गिरफ्त में लेकर 40 मोबाईल और सीम बरामद की है.

राज्य साइबर को पता चला था कि मंदसौर स्थित शामगढ़ के पंजाबी कॉलोनी में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है. यहां से फर्जी डायमंड रिसर्च कंपनी बनाकर ALGO TRADING APP के माध्यम से निवेश के नाम पर हर रोज दर्जनों लोगों को ठगा जा रहा है. यह काम यहां कार्यरत दो दर्जन लड़के-लड़कियां कर रही हैं. इस सूचना पर गुरूवार को डीएसपी लीना मरोठ, निरीक्षक अमित सिंह परिहार ने सेल की टीम और पुलिस लाइन के बल के साथ उस कॉल सेंटर पर छापा मारा. टीम ने कॉल सेंटर से 4 लड़के 17 लड़कियों को गिरफ्तार कर लोगों को ठगने में उपयोग हो रहे 30 फर्जी सिम, 20 Android और 20 Keypad मोबाइल जब्त कर किया.

ऐसे फांसते थे शिकार

फर्जी कॉल सेंटर चलाने वालों ने अपनी कंपनी का नाम डायमंड रिसर्च कंपनी रखा था. यहां कार्यरत युवक-युवती ALGO TRADING करने पर 10 हजार के निवेश पर प्रतिदिन 5 से 7 प्रतिशत का मुनाफा का झांसा देते थे. वे लोगो से ठगी रकम फर्जी बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रान्सफर करवाते थे.

ऐसे हुआ पर्दाफाश

स्टेट साइबर सेल के एडीजी योगेश देशमुख ने बताया कि लंबे समय से कॉल सेंटर द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को फेक कॉल के माध्यम से ठगने की शिकायत मिली थी. तकनीकी तथ्यों के आधार पर मंदसौर में कई दिन रैकी कर साक्ष्य जुटाये. उन्होंने कहा कि वे अब पता लगा रहे हैं कि आरोपियों द्वारा अब तक कितने लोगों को ठगा गया है. जब्त मोबाइल व सिम की जांच कर पता लगा रहे हैं कि लोगों से ठगी राशि कहां और किन खातों में रखी है.

ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी

साइबर सेल ने आनलाइन ठगी से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है. यदि शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर कोई अज्ञात व्यक्ति का कॉल आपको आता है तो पहले किसी विश्वसनीय स्त्रोत/पुलिस के माध्यम से उसकी तसदीक कर लें अन्यथा आप भी इस प्रकार की ठगी का शिकार हो सकते हैं. इस तरह का कोई घटना होने पर अपने नजदीकी थाने या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें.

सोते समय आग में जलकर दंपती की मौत, दरवाजा तोड़ने पर बिस्तर पर पड़े मिले शव

भोपाल। राजधानी के मिसरोद स्थित नई बस्ती जाटखेड़ी में रहने वाले एक दंपती की संदिग्ध हालत में आग से जलकर मौत हो गई। गुरुवार सुबह घर से धुआं निकलते देख लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो उनके शव बिस्तर पर जली हुई अवस्था में मिले। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। प्रारंभिक तौर पर यह हादसा माना जा रहा है, लेकिन घटना के सही कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। पुलिस के मुताबिक सतीश बिराड़े (26) नईबस्ती जाटखेड़ी में रहता था और फूल माला बेचने का काम करता था। करीब तीन साल पहले उसकी शादी आम्रपाली बिराड़े (24) से हुई थी। सतीश के माता-पिता और अन्य परिजन भी नईबस्ती में रहते हैं। सतीश परिवार वालों के पास ही एक कमरा बनाकर रह रहा था। गुरुवार सुबह करीब साढ़े पांच मोहल्ले वालों ने सतीश के कमरे से धुआं निकलता देख परिजनों को सूचना दी।

राजगढ़ के वारिश खान ने हादसे में सात लोगों की बचाई जान, CM ने बताया MP का गौरव, 1 लाख मिलेगा इनाम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजगढ़ जिले में ब्यावरा निवासी प्लंबर वारिस खान को एबी रोड हाईवे पर कार पलटने की घटना में शिवपुरी के परिवार के सात लोगों की जान बचाने के लिए एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कॉल के माध्यम से वारिस से बात की और उसकी कुशलक्षेम पूछी। वारिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह बाइक से बीनागंज जा रहे थे। तभी सामने आ रही कार दुर्घटनावश खंती में गिर गई। उन्होंने बिना देरी कर अपने हाथों से कार के कांच तोड़े और एक-एक कर के सभी यात्रियों को बाहर निकाला।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वारिस के इस साहसी कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि वारिस आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। मुसीबत के समय में एक दूसरे की सहायता करना ही सच्ची मानवता है। आपके इस कार्य से सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आप मध्य प्रदेश के गौरव हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी कलेक्टर्स को 15 अगस्त के अवसर पर लोगों की मदद करने वाले साहसी लोगों को सम्मानित करने के निर्देश दिए।

जनजातीय गौरव दिवस, इतिहास के एक बड़े अन्याय को दूर करने का है ईमानदार प्रयास : प्रधानमंत्री श्री मोदी

भगवान बिरसा मुंडा ने मातृभूमि के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिये अपना सर्वस्व बलिदान दिया,प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश के दो जनजातीय संग्रहालय राष्ट्र को किये समर्पित,जन मन योजना और सिकलसेल उन्मूलन मिशन जनजाति कल्याण का महाभियान : राज्यपाल श्री पटेल,भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध जनजातीय समाज को किया खड़ा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनजातीय समाज आज भी हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे है,देश में चल रहा है जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को समक्ष लाने का अभियानबाणसागर बांध से शहडोल जिले के लोगों को भी मिलेगा पानी,शहडोल में बनाया जायेगा स्थाई हेलीपेड जनजातीय गौरव दिवस का राज्यस्तरीय कार्यक्रम शहडोल में हुआ आयोजित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनायी जा रही है। जनजातीय गौरव दिवस इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद जनजातीय वर्ग के योगदान को इतिहास में वह स्थान नहीं दिया गया, जिसके लिये वे हकदार थे। जनजातीय समाज वो है, जिसने राजकुमार राम को भगवान बनाया। भारत की संस्कृति और आजादी के रक्षा के लिये सैकड़ो वर्षों की लड़ाई का नेतृत्व दिया। आजादी के बाद के दशकों में जनजातीय वर्ग के अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिश की गई। इसके पीछे स्वार्थ भरी राजनीति थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के समग्र कल्याण के लिये अनेक योजनाएँ संचालित कर उनके आर्थिक और सामाजिक विकास का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार जिले के जमुई में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर 6 हजार करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इसमें जनजातीय वर्ग के बच्चों के भविष्य को संवारने वाले स्कूल और हॉस्टल, जनजातीय वर्ग की महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सुविधा, जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें, जनजातीय वर्ग की संस्कृति को समर्पित संग्रहालय एवं जनजातीय वर्ग के डेढ़ लाख परिवारों को पक्के घर के स्वीकृति पत्र वितरित किये गये हैं। साथ ही आज देव दीपावली के दिन 11 हजार से अधिक जनजातीय परिवारों को अपने घर में प्रवेश कराया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा के श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वंतत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का वर्चुअली लोकापर्ण किया।

मध्यप्रदेश के शहडोल जिला मुख्यालय पर आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल, सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण श्री रामलाल रोतेल सहित जन-प्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन कर किया। अतिथियों का स्वागत जनजातीय परंपरा अनुसार किया गया।

जनजातीय कल्याण के लिये राज्य सरकार कर रही है बेहतरीन कार्य : राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सम्पूर्ण देश में जनजातीय कल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। पीएम जन मन योजना और सिकल सैल उन्मूलन मिशन, जनजाति कल्याण का महाभियान है। इस महाभियान में राज्य सरकार द्वारा जनजाति कल्याण के बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। अनेक विभागों के माध्यम से अति पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा में लाने के कारगर प्रयास लगातार जारी है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सिकल सैल उन्मूलन मिशन का संकल्प मध्यप्रदेश की धरती से लिया जाना प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा सिकल सैल उन्मूलन की दिशा में जाँच और जागरूकता के कार्य सघन स्तर पर किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 82 लाख लोगों की सिकलसेल स्क्रीनिंग पूर्ण हो गई है। राज्यपाल श्री पटेल ने शहडोल जिले के सिकल सैल जाँच कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को सिकल सैल कार्ड वितरण का कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सिकल सैल से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय, इस रोग के प्रति जागरूकता ही है। उन्होंने कहा कि शादी के पूर्व लड़का-लड़की सिकल सैल कार्ड का मिलान जरूर करें। उन्होंने कहा कि गर्भधारण के दौरान और जन्म के बाद भी बच्चे के सिकल सैल की जाँच जरूर कराएं। राज्यपाल श्री पटेल ने सभी से आह्वान किया कि सिकल सैल की जाँच और जागरूकता हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यपाल श्री पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनका नमन किया और प्रदेश एवं देश के महान क्रांतिकारी, जनजातीय सपूतों का पुण्य स्मरण भी किया। उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जबलपुर और छिंदवाड़ा के जनजातीय संग्रहालय के लोकार्पण के प्रति आभार ज्ञापित किया।

जल, जंगल और जमीन का अधिकार जनजातीय समाज का है मूल अधिकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल, जंगल और जमीन का अधिकार जनजातीय समाज का मूल अधिकार है। इसे अंग्रेज उनसे छीनना चाहते थे। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के अत्याचार, अनाचार के खिलाफ जनजातीय समाज को खड़ा किया और अंग्रेजों के खिलाफ दो स्तरों पर लड़ाई लड़ी। एक ओर उन्होंने जनजातीय समाज के मूल अधिकार की रक्षा की और दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों द्वारा हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर हमारे जनजातीय भाइयों को ईसाई बनाने के कुत्सित प्रयासों को ध्वस्त किया। आज हम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें हृदय से स्मरण और नमन करते हैं।

समाज के हर व्यक्ति के उत्थान को सुनिश्चित करने की राह पर चल रहे पीएम मोदी के सम्मान की होड़

समाज में रह रहे हर व्यक्ति का विकास कैसे हो इसके लिए पीएम मोदी द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए पूरी दुनिया में उनके सम्मान की होड़ लगी है.

डोमिनिकल रिपब्लिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर देने का फैसला किया है. यह फैसला कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की ओर से की गई मदद के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान 19 से 21 नवंबर तक गुयाना में भारत-कैरीकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा. इसके साथ ही दुनिया के कई देश मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक और दूसरे सम्मानों से नवाज चुके हैं.

जब कोई देश किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है, तो वह उनकी वैश्विक क्षमताओं और दक्षताओं का निजी तौर पर सम्मान तो करता ही है, साथ ही उनके देश के वैश्विक दबदबे का भी सम्मान करता है. देश और विदेश में किसी नेता की पॉपुलेरिटी ऐसे ही नहीं हो जाती. उसे देश में कुशल नेतृत्व तो देना ही होता है, साथ ही वैश्विक समस्याओं से निपटने की सामूहिक रणनीति में भी अहम साझेदारी निभानी पड़ती है. इससे साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कूटनैतिक, रणनैतिक, सामरिक संघर्षों की तीव्रता कम करने में भी उन्हें अहम भूमिका निभानी पड़ती है. देश में अंत्योदय यानी अंतिम सीढ़ी पर खड़े समुदाय के विकास की बात हो या फिर विश्व बिरादरी में धाक कायम करने की बात, प्रधानमंत्री मोदी सभी मोर्चों पर एक साथ बेहद मजबूत नजर आते हैं.

भारत में अंत्योदय के विचार को जमीनी हकीकत पर उतारने के मामले में मोदी सरकार ने जम कर पसीना बहाया है. इसके सार्थक और सकारात्मक नतीजे अब साफ-साफ दिखाई देने भी लगे हैं. सिर्फ जनजातीय विकास को पैमाना बनाया जाए, तो उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से ले कर अभी तक मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं की बदौलत जनजातीय समुदाय की स्थिति में परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तीकरण और जमीन की सुरक्षा के मामले में जनजातीय समाज की हालत में मजबूती आई है.

रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक दशक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अब आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी हैं. बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है और डिजिटल माध्यमों से शिक्षा मिलने लगी है. सरकार की वजीफा योजनाओं से भी जनजातीय बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है. साल 2013-14 में जनजातीय बच्चों के स्कूलों की संख्या 123 थी. साल 2023-24 तक यह बढ़ कर 476 हो गई. इसी तरह 2013-14 में स्कूलों में 34 हजार जनजातीय बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ

था. लेकिन 2023-24 में यह संख्या बढ़ कर एक लाख, 33 हजार हो गई. 10 वर्षों में 17 हजार करोड़ रुपये का वजीफा जनजातीय बच्चों को दिया गया.

स्वास्थ्य की बात करें, तो जनजातीय इलाकों में क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाओं में काफी इजाफा हुआ है. अब मोबाइल मेडिकल यूनिटें दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच रही हैं. जनजातीय क्षेत्रों में शौचालयों की संख्या में भी खासी बढ़ोतरी हुई है. इससे लोगों में बीमारियों की समस्या कम हुई है. इलाज पर उनका खर्च भी काफी कम हो गया है. जनजातीय इलाकों में पिछले 10 साल के दौरान 1.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया. मोदी सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है. राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत अभी तक 4.6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है. सात करोड़ लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है.

जमीन की सुरक्षा के अच्छे उपायों का ही नतीजा है कि पिछले 10 साल में जनजातीय समुदाय की जमीनों पर अतिक्रमण पर प्रभावी रोक लगी है, लिहाजा विस्थापन के मामले भी कम हो रहे हैं. सरकार ने वनाधिकार अधिनियम को असरदार तरीके से लागू किया है. मोदी सरकार के कार्यकाल में अभी तक 23 लाख जनजातीय लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल चुका है. कुल 1.9 करोड़ एकड़ जमीन उन्हें मिली है. उन्होंने अपनी जमीन पर खेती करने और रोजी-रोटी कमाने के दूसरे तरीके भी अपनाए हैं.

कुल मिला कर जनजातीय समाज के लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण की बात की जाए, तो उनमें से ज्यादातर लोग वनोपज पर ही निर्भर थे. लेकिन आज राष्ट्रीय बांस मिशन, पीएम किसान और वन धन विकास केंद्रों जैसी पहलों ने जनजातीय समाज के विकास की नई राह खोली है. वन धन विकास केंद्रों का फायदा 45 लाख से ज्यादा जनजातीय लोगों को मिल चुका है, जबकि पीएम किसान योजना का फायदा 1.2 करोड़ जनजातीय लोग उठा चुके हैं.

इसी तरह मोदी सरकार ने देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का बीड़ा उठाया और करोड़ों ग्रामीण आवासों में नल से जल पहुंचा दिया है. पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत सरकार देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत से प्रयास कर रही है. राजमार्गों, पुलों, सड़कों, बंदरगाहों और दूसरे बुनियादी ढांचों का विकास तो दूर से और दूर तक नजर आता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जिंदगी की मूलभूत जरूरतों से जुड़ी सभी सुविधाओं के विकास के लिए ऐसा ही बहुत कुछ किया जा रहा है, जिसकी चर्चा आम लोगों के बीच कम ही होती है. कोविड-19 के दौरान बहुत से देशों को टीके पहुंचाए गए. इसी तरह वसुधैव कुटुंबकम् की नीति पर चलते हुए मोदी सरकार दूसरे देशों की मदद भी करती है.

ऐसे में वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा है और वे उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं. रूस ने नौ जुलाई, 2024 को पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू सम्मान से नवाजा था. इससे पहले भूटान ने 24 मार्च, 2024 को उन्हें ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग सम्मान दिया था. तेरह जुलाई, 2023 को फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था. इससे पहले मिस्र ने जून, 2023 में उन्हें ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान से नवाजा था. इसी तरह फिजी ने मई, 2023 में उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान दिया था.मई, 2023 में ही मोदी को पापुआ न्यू गिनी ने ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान से नवाजा था.साल 2023 में ही मोदी को पलाउ का सर्वोच्च सम्मान एबाकल अवॉर्ड दिया गया था.इससे दो साल पहले 2021 में मोदी को भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो सम्मान दिया गया था.साल 2020 में मोदी को अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट सम्मान मिला था.इसी तरह बहरीन ने मोदी को 2019 में किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस सम्मान दिया था.मालदीव भी साल 2019 में मोदी को ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन सम्मान दे चुका है.रूस ने उन्हें 2019 में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू सम्मान दिया था.उसी साल यानी 2019 में ही संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान से नवाजा था.साल 2018 में फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन सम्मान दिया था.अफगानिस्तान ने साल 2016 में मोदी को स्टेट

Pizza नहीं तो गोली खा! रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे बदमाश, फिर ठाय..ठाय...ठाय, आधी रात दहल गया ग्वालियर

ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बेखौफ होते बदमाशों ने एसपी ऑफिस के नजदीक एक रेस्टोरेंट के बाहर Pizza के लिए फायरिंग कर दी. खास बात यह है कि वारदात

एसपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर घटित हुई. यह पूरी घटना और बदमाशों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं. पटेल नगर बेहद पॉश और सुसंस्कृत इलाका माना जाता है. यहां शाम के वक्त अच्छी खासी चहल-पहल रहती है. बावजूद इसके कार सवार बदमाश फायरिंग कर अपना रौब दिखाकर फरार होने में कामयाब हो गए. अब पुलिस ने नथिंग बिफोर कॉफी कैफे के कर्मचारी प्रेम नरवारे की शिकायत पर 2 अज्ञात कार सवार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.पुलिस के मुताबिक घटना बुधवार आधी रात हुई है. यहां नथिंग बिफोर कॉफी कैफे, जो गोकुल अपार्टमेंट के सामने पटेल नगर में स्थित है, वहां एक कार सवार बंदूक धारी 2युवक आए और उन्होंने प्रेम नरवारे से पिज्जा मांगा. इसी को लेकर दोनों में कुछ विवाद हो गया.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

झगड़े के बाद आरोपी फायरिंग कर वहां से निकल गए. बदमाशों के जाने के बाद कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. इसमें आरोपियों के चेहरे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आर्म्स लाइसेंस के डिटेल के आधार पर बदमाशों की पहचान की कोशिश शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. विश्वविद्यालय थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज किया है. खास बात यह है कि होटल में बैठे कुछ युवक और युवती इस घटना को देखकर सहम गए थे. फिर सभी चुपचाप वहां से डरकर निकल गए. बदमाशों के जाने के बाद प्रेम नरवारे नामक युवक अपने साथी कर्मचारियों के साथ विश्वविद्यालय थाने पहुंचा और अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया.

कुख्यात वन्य-जीव तस्कर को प्रोडक्शन वारंट पर वन विभाग तमिलनाडु को सौंपा

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश ने किया था गिरफ्तार

भोपाल : प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव एसटीएसएफ मध्यप्रदेश भोपाल ने बताया कि कुख्यात वन्य जीव तस्कर एवं शिकारी पुजारी सिंह बावरिया को न्यायालय उडानमंडलम तमिलनाडु द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के आधार पर न्यायालय नर्मदापुरम मध्यप्रदेश की अनुमति के बाद तमिलनाडु के समकक्ष अधिकारियों को सौंप दिया गया हे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव एसटीएसएफ मध्यप्रदेश भोपाल ने बताया कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा वन्य-जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली से प्राप्त अलर्ट एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर 18 अगस्त, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात वन्य-जीव तस्कर आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया को बाघ एवं पेंगोलिन के अवयवों के साथ गिरफ्तार किया था। उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अन्य आरोपी पुजारी सिंह वल्द राम कुमार सिंह बावरिया निवासी होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार किया गया था। उक्त दोनों अपराधियों के विरुद्ध महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में वन्य-प्राणी बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार के संबंध में प्रकरण दर्ज है। नीलगिरी वन मण्डल तमिलनाडु दल द्वारा केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम से आरोपी पुजारी सिंह बावरिया को नीलगिरी वन मण्डल में बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार में दर्ज प्रकरण में 11 नवम्बर, 2024 को न्यायालय नर्मदापुरम की अनुमति के उपरांत एसटीएसएफ के सहयोग से तमिलनाडु भेजा गया है। आरोपी को विगत कई वर्षों से अन्य प्रदेशों के वन विभाग एवं अन्य कानून प्रवर्तन संस्थाएँ तलाश रही थीं। प्रकरण में विवेचना जारी है।प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव एसटीएसएफ मध्यप्रदेश भोपाल ने बताया कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा प्रकरण में की गयी सटीक विवेचना के आधार पर प्रकरण में शामिल आरोपी पुजारी सिंह की जमानत याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विस्तृत सुनवाई उपरांत खारिज की गयी है। आरोपी विगत 11 माह से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध है।

गाँधी सागर डेम में रेत के अवैध उत्खननकर्ताओं पर छापामार कार्रवाई

डेम से 3 बोट एवं एक पनडुब्बी जप्त

नीमच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशाअनुरूप अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ प्रदेश में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार 13 नवम्बर को नीमच जिले के गाँधी सागर डेम के राजपुरा क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। इसमें 3 बोट एवं एक पनडुब्बी जप्त की गयी एवं पानी के किनारे रेत छानने के लिये लगे हुए 3 छन्नों को भी नष्ट किया गया। कलेक्टर नीमच के निर्देश पर अवैध उत्खननकर्ताओं पर छापामार कार्रवाई करने के लिये जिला खनिज अधिकारी श्री आरिफ खान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा श्री पवन बावरिया के नेतृत्व में सहायक खनिज अधिकारी श्री गजेन्द्र डाबर, तहसीलदार रामपुरा श्री मुकेश निगम, राजस्व निरीक्षक श्री अनुराग, हल्का पटवारी, कोटवार और होमगार्ड सैनिकों के साथ राजपुरा क्षेत्र में डेम में छापामार कार्रवाई की। जिला खनिज अधिकारी नीमच ने बताया कि जप्त की गयी नाव एवं पनडुब्बी को रामपुरा ले जाकर मत्स्य केन्द्र में रखा गया है। जप्त नावों, मशीनों एवं पनडुब्बी का कोई भी मालिक सामने नहीं आया है। प्रकरण में विवेचना कर कलेक्टर नीमच द्वारा अर्थदण्ड की कार्रवाई की जायेगी।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाएँ, मधुमेह से बचें: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश के नागरिकों से मधुमेह की को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने रक्त शर्करा और रक्तचाप की नियमित जांच कराएँ, संतुलित आहार लें। अत्यधिक शर्करा का सेवन न करें और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें ताकि तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सके। उन्होंने मधुमेह की रोकथाम के प्रति सजग रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और स्वास्थ्य शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। सामूहिक प्रयास और जागरूकता से ही हम मधुमेह पर नियंत्रण पा सकते हैं और एक स्वस्थ मध्यप्रदेश का निर्माण कर सकते हैं।

नियमित जाँच करायें

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार मधुमेह एवं अन्य असंचारी रोगों के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करके दिल के दौरे, किडनी और फेफड़े के रोग, अंधत्व और अन्य गंभीर जटिलताओं को रोका जा सकता है। नागरिकों की समय पर स्क्रीनिंग, जांच की व्यवस्था की गयी है। नियमित जाँच से सही समय में समस्या का चिन्हांकन होता है, जिससे अपेक्षित सावधानियाँ एवं उपचार सहजता से किया जा सकता है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। 15 जिलों में असंचारी रोग बूथ स्थापित किए गए हैं ।

स्कूल शिक्षा की पहुँच प्रदेश के हर बच्चे तक हो, राज्य सरकार रखेगी ध्यान

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने बैठक में की विजन-@2047 पर चर्चा

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि स्कूल शिक्षा की पहुँच प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक हो। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को विकसित भारत @2047 के ड्राफ्ट पर प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा। मंत्री श्री सिंह ने बुधवार को मंत्रालय में हुई बैठक में अधिकारियों से ड्रॉफ्ट पर चर्चा की। बैठक में सचिव, स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल, आयुक्त, लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता भी मौजूद थीं।

स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नॉलॉजी

बैठक में बताया गया कि विजन-2047 के ड्राफ्ट में यह बिन्दु प्रमुख रूप से डाला गया है कि सभी बच्चो को बगैर भेदभाव के सामान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाये। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि विजन-@2047 ड्राफ्ट में हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स की चर्चा करते स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिये स्कूलों में नवीन टेक्नॉलॉजी के संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिये जरूरी है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा व्यवहारिक तरीके से दिये जाने की व्यवस्था हों। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सरकारी क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आगामी आवश्यकता को देखते हुए शिक्षकों के पाठ्यक्रम तैयार किये जायें।

सीएम राईज स्कूल परियोजना

बैठक में सीएम राईज स्कूल परियोजना के पहले चरण में निर्माणाधीन 275 स्कूलों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सीएम राईज स्कूल में उपलब्ध कराये गये संसाधनों का शत्-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीएम राईज स्कूल परियोजना विश्वस्तरीय स्कूल व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। बैठक में सचिव, स्कूल शिक्षा डॉ. गोयल ने बताया कि मार्च 2025 तक 122 सीएम राईज स्कूल प्रारंभ हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सीएम राईज स्कूल परियोजना की आगामी आवश्यकता को देखते हुए लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीएम राईज स्कूल परिधि में आने वाले बच्चों को प्राथमिकता से प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि अक्टूबर 2024 में 2 सीएम राईज स्कूलों का उदघाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सीमाओं को देखते हुए सीएम राईज स्कूल परियोजना में बदलाव भी किये जा रहे है। इसका मकसद स्कूल की संख्या बढ़ाकर अधिक से अधिक बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करना है।

पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन

बैठक में पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी श्री विनय निगम ने बताया कि वर्ष 2025-26 शैक्षणिक सत्र में स्कूलों के सत्र के प्रारंभ में ही पाठ्य पुस्तके पहुँचायें जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि पाठ्य-पुस्तक निगम स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं में अधिक से अधिक भागीदारी निभा सकें।

मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है सड़कों का नेटवर्क

मध्यप्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की अभूतपूर्व गति से राज्य एक नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की डबल इंजन सरकार से प्रदेश में सड़कों के व्यापक विस्तार और विकास को नया आयाम मिल रहा है। वृहद स्तर पर चल रही सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य केवल सड़कों और राजमार्गों का निर्माण ही नहीं, बल्कि राज्य के हर नागरिक के जीवन को सरल और समृद्ध बनाना है। केन्द्र द्वारा लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं से मध्यप्रदेश में स्थायी आधारभूत संरचना विकसित होगी।

मध्यप्रदेश को इस वर्ष जनवरी माह में 10 हजार 405 करोड़ रुपये लागत की 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात मिली। भोपाल और जबलपुर में आयोजित कार्यक्रमों में इन परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। भोपाल में 8,038 करोड़ रुपये की लागत से 498 किलोमीटर लंबी 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और जबलपुर में 2,367 करोड़ रुपये की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं का शिलान्यास हो चुका है।

इन परियोजनाओं में एनएच-46 का छह-लेन विस्तार, एनएच-146बी का चार-लेन विस्तार और कई दो-लेन सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।

नवीन स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से न केवल प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कटनी के कोयला उद्योग, बुधनी के टेक्सटाइल और वुड क्राफ्ट उद्योगों को भी लाभ होगा। इसके साथ ही खजुराहो, ओरछा जैसे पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी आसान होगी और पेंच टाइगर कॉरिडोर तक पहुँचने में सहूलियत मिलेगी। मध्यप्रदेश के इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ व्यावसायिक और नागरिक यातायात में भी सुगमता आएगी, जिससे प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी योगदान मिलेगा।प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। इसमें 4,613 करोड़ रुपये की लागत से 88 किलोमीटर लंबे इस हाई-स्पीड कॉरिडोर को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मोड पर विकसित किया जाएगा, जो आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा के समय को लगभग 50% तक कम कर देगा। यह परियोजना न केवल मौजूदा 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की यातायात क्षमता को दोगुना करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगी, जिससे पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।इस हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश को व्यापक स्तर पर मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मंजूर की गई इस परियोजना से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स की दक्षता में सुधार, भीड़भाड़ में कमी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। यह 6-लेन ग्रीनफील्ड हाई-वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए, आगरा जिले के गांव देवरी से शुरू होकर ग्वालियर जिले के गांव सुसरा तक जाएगा। इस परियोजना में NH - 44 के मौजूदा आगरा-ग्वालियर खंड पर ओवरले और अन्य सड़क सुधार कार्य भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 50,655 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत से 936 किलोमीटर की लंबाई में फैली 8 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं में यह कॉरिडोर भी शामिल है, जो देश के परिवहन ढांचे को सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

मध्यप्रदेश को सड़क विकास की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिली है, जिसमें भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए 3589.4 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना में भोपाल से विदिशा, विदिशा से ग्यारसपुर, सताईघाट से चौका और चौका से कैमाहा तक के मार्ग को चौड़ा और सुदृढ़ किया जाएगा। इस परियोजना से यातायात सुगमता में सुधार होगा, यात्रा के समय में कमी आएगी, सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। इससे अपग्रेडेशन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मंडला से नैनपुर के बीच 46 किलोमीटर लंबे मार्ग को भी 592 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड करने की स्वीकृति भी दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने से मंडला और नैनपुर के बीच यातायात अधिक सुरक्षित और कुशल बनेगा, जिससे स्थानीय जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा।

प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में यह परियोजनाएं एक महत्वपूर्ण कदम हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र के तहत बुंदेलखंड विकास पथ की घोषणा की थी, जो राज्य की राजधानी भोपाल को बुंदेलखंड के सागर और छतरपुर जिलों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण 4-लेन सड़क परियोजना है। इस परियोजना को केंद्र सरकार की भी स्वीकृति मिल गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पहले से इस मार्ग को 4-लेन में विस्तारित करने का काम चल रहा था। अब भोपाल से सागर होते हुए छतरपुर और उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक इसे 4-लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड के क्षेत्रों में व्यापार और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और मध्यप्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा।

मध्यप्रदेश को 20 हजार करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति के रूप में एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है, जिससे राज्य की आधारभूत संरचना को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भोपाल में इस महात्वाकांक्षी योजना की घोषणा की, जिसमें 27 परियोजनाओं को प्रदेश में यातायात सुधार और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत 1,228 कि.मी. लंबी सड़कों का विकास किया जाएगा, जिसमें से 612 कि.मी. का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा और 616 कि.मी. का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के लिए किये जा रहे प्रयास मील का पत्थर साबित होंगे। इससे न केवल यातायात की सुविधा और सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि यह प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में भी सहायक होगी। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजनाएँ राज्य में आधारभूत संरचना विकास को नई गति देंगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से मध्यप्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा और यह राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में योगदान देगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उज्जैन महाकाल मंदिर रोप-वे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाला रोप-वे प्रोजेक्ट मोनोकेबल डिटेचेबल गोंडोला तकनीक पर आधारित है, जो 1.762 किमी लंबा है। इससे प्रतिदिन करीब 64 हजार श्रद्धालुओं को यात्रा का लाभ मिलेगा।इस प्रोजेक्ट के तहत यात्रा का समय वर्तमान में 25-30 मिनट से घटाकर केवल 7 मिनट हो जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को तीव्र और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस रोप-वे में 3 स्टेशन और 13 टॉवर बनाए जाएंगे, जो महाकाल मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक साबित होंगे। उज्जैन महाकाल मंदिर तक पहुंचने में लगने वाले समय में 75% की कमी आना इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी विशेषता है, जो भक्तों के लिए यात्रा को और भी सुगम बनाएगी।

पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा से जच्चा-बच्चा का जीवन हुआ संरक्षित

आपात स्थिति में जीवन संरक्षण में एयर एम्बुलेंस सेवा हो रही है कारगर

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सरकार हर नागरिक को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चिकित्सा अधोसंरचना और चिकित्सकीय उन्नत तकनीक की व्यवस्था के साथ मैन पॉवर उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 'पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा' आपातकाल में नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल है। आपात स्थिति में समय से उचित चिकित्सकीय सेवा की उपलब्धता से कई जिंदगियों का बचाव किया जा रहा है।

छतरपुर के ग्राम खेरो की निवासी गर्भवती महिला श्रीमती रानी पटेरिया (पत्नी श्री उमेश पटेरिया) को पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सुविधा से आपात स्थिति में उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर जच्चा- बच्चा का जीवन सुरक्षित किया गया। उल्लेखनीय है कि श्रीमती रानी पटेरिया को रविवार 10 नवंबर को जिला अस्पताल छतरपुर में भर्ती किया गया। महिला की स्थिति "फुल टर्म प्रेगनेंसी विद प्रिवियस एल एस सी एस" के कारण हाई रिस्क श्रेणी में थी। डॉ. निधी खरे द्वारा सिजेरियन ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के पश्चात महिला को पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग की समस्या उत्पन्न हो गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ ने ब्लीडिंग रोकने के लिए आवश्यक उपचार किया तथा हिसटेक्टोमी की गई। महिला को 4 यूनिट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया और उसे निरंतर ऑब्जर्वेशन में रखा गया।

निःशुल्क मिली सुविधा

ऑब्जर्वेशन के दौरान महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ ने सीएमएचओ डॉ. आर.पी. गुप्ता से विचार-विमर्श किया। जिला अस्पताल की टीम, सिविल सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सीएमएचओ द्वारा महिला को हायर सेंटर रेफर करने का निर्णय लिया गया। चूंकि महिला आयुष्मान कार्ड धारक थी, अतः उसे आयुष्मान योजना के अंतर्गत चिरायू हॉस्पिटल, भोपाल में रेफर किया गया।

चिरायू हॉस्पिटल में बेड उपलब्धता की पुष्टि के पश्चात, kelsa.io पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया। सीएमएचओ और सिविल सर्जन की देखरेख में महिला को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से खजुराहो एयरपोर्ट लाया गया और एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। भोपाल एयरपोर्ट पर महिला को 108 एम्बुलेंस द्वारा चिरायू हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ शाम 7:30 बजे महिला को भर्ती कर लिया गया। वर्तमान में, चिरायू हॉस्पिटल में महिला की स्थिति स्थिर और सामान्य है।

पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या चिन्हित विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता निर्मित होने पर कठिन भौगोलिक परिस्थिति में प्रदेशए के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केन्द्रों तक एयर लिफ्ट किये जाने की सेवा प्रदाय की जाती है।

पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा सड़कों एवं औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदा में गंभीर पीड़ित घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार के लिये हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हृदय सम्बंधित अथवा अन्य विभिन्न गंभीर बीमारियों जिसमें रोगी/पीड़ित को तत्काल इलाज की आवश्यकता होने की स्थिति में मरीजों को अच्छे एवं उच्चतम चिकित्सा संस्थानों में त्वरित उपचार के लिये हवाई परिवहन सुविधा प्रदाय की जाती है।

पात्रता

सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में पीड़ित को राज्य के अंदर एवं बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में निशुल्क परिवहन किया जाता है। आयुष्मान कार्डधारी के उपचार के लिये राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान सम्बद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु निशुल्क परिवहन की व्यवस्था है। अन्य हितग्राही जो कि आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं, उनके उपचार के लिए राज्य के अंदर स्थित शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन जबकि राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में अनुबंधित दर पर सशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध है।

ग्वालियर शहर के बीचों बीच वह बावड़ी जहां हुआ करते थे चमत्कार, एक बार नहाने से खत्म हो जाते थे रोग

ग्वालियर. शहर के बीचों-बीच कैला सागर नामक एक बावड़ी है. यह बावड़ी शहर के बीचों बीच महल गांव में स्थित है. पुराने जमाने की यह बावड़ी 2007 रूपये में बनवाई गई थी. इसे बनवाने का भी मुख्य उद्देश्य है ग्वालियर शहर की देवी छोटी करौली माता के इतिहास से जुड़ा हुआ है इससे जुड़े हुए कई किस्से हैं जब यहां पर चमत्कार हुए थे

एक बार जब माता के वार्षिक उत्सव में हो गया था घी खत्म

यह बात उसे जमाने की है जब ग्वालियर के छोटी करौली माता मंदिर पर महंत हीरालाल जी महाराज यहां पर साल में एक बार देवी का वार्षिक उत्सव मनाया करते थे. तब यहां पर कई सारे चमत्कार हुआ करते थे. उस जमाने में जमीन का वाटर लेवल अच्छा हुआ करता था. इस वजह से इस बावड़ी के अंदर पानी रहा करता था. वर्तमान में जमीन का वाटर लेवल कम हो जाने के कारण बावड़ी में पानी नहीं है.उस जमाने में जब एक बार वार्षिक उत्सव वाले दिन माता का प्रसाद बन रहा था लेकिन, प्रसाद बनाने के लिए घी खत्म हो गया था. ऐसे में महंत हीरालाल ने यह आदेश दिया इस बावड़ी के पानी को लेकर उसमें प्रसाद बनाया जाए. उसके बाद में यहां पर प्रसाद जब पानी में डालकर बनाया गया तो उसने घी का काम किया. उसके बाद में महंत हीरालाल ने सुबह उठकर बाजार से उतना ही घी लाकर इस बावड़ी में डालने के लिए कहा था. ऐसे कई चमत्कार इस बावड़ी के बारे में सुनने में आते हैं इसके अलावा कई प्रकार के रोग इस बावड़ी में नहाने के बाद में समाप्त हो जाया करते थे.

200 से 300 वर्ष पूर्व हुआ था इस बावड़ी का निर्माण

इस बावड़ी का नाम कैला सागर है. इसका निर्माण छोटी करौली माता मंदिर के निर्माण के साथ में ही कराया गया था. इस मंदिर के निर्माण के समय मात्र 2007 रूपये में इस बावड़ी को बनवाया गया था. उस जमाने में लोग यहां पर आकर इस बावड़ी में नहाया करते थे. उसके बाद में छोटी करौली माता के दर्शन किया करते थे. इस बावड़ी के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि इसके मध्य में एक मंदिर है जिस मंदिर का निर्माण छोटी करौली माता मंदिर के साथ में ही कराया गया था.

नदी में कर रही थी छठ पूजा, तभी तैरता आ गया 'सबसे जहरीला सांप'

हाल ही में महापर्व छठ का समापन हुआ है. बिहार ही नहीं, पूरे देश में त्योहार की धूम रही. 4 दिनों चलने वाले इस त्योहार को पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, मगर औरतें पूरे उत्साह के साथ इसे पूरा करती हैं. नदी में खड़े होकर उन्हें सूर्य की उपासना करनी पड़ती है. हाल ही में एक महिला बिहार में नदी में खड़े होकर छठ पूजा कर रही थी. तभी अचानक पानी में एक जहरीला सांप (Krait Snake in Chhath Puja near woman viral video) आ गया, जिसे देखकर महिला ने जो किया वो देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा. इंस्टाग्राम अकाउंट @flirting.lines पर अक्सर अजब-गजब वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें एक महिला नदी में खड़ी होकर छठ की पूजा (Krait snake in water during Chhath Puja) करती दिखाई दे रही है. कई अन्य औरतें भी वहां खड़ी होकर पूजा कर रही हैं. अचानक वहां पर एक सांप नदी में तैरता हुआ आ जाता है. सांप उस महिला के इतने करीब से गुजरता है कि अगर वो काट लेता, तो महिला की जान पर बन आती.

हिमालय की चोटी पर देवी का अनोखा मंदिर, पूरी सर्दी दर्शनों की मनाही, जो गया.. फिर लौटा नहीं! जानें रहस्य

मंडीः हिमालय पर एक अनोखा देवी मंदिर है. यह मंदिर सर्दियों में बंद कर दिया जाता है, यहां सिर्फ गर्मी में ही दर्शन करने की इजाजत है. सर्दियों में इस मंदिर के बंद होने के पीछे बर्फबारी मूल कारण है, लेकिन एक वजह और भी है, जिसकी वजह से प्रशासन यहां लोगों को जाने नहीं देता. यह वजह एक रहस्य है, जो आज तक अनसुलझी है. कहते हैं, सर्दियों के दौरान कई लोग इस मंदिर में दर्शन करने आए, फिर उनका पता ही नहीं चला. मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी यानी शिकारी चोटी और शिकारी माता का मंदिर है. सर्दी शुरू होने के बाद यहां कोई इंसान या ट्रैकर नहीं जा सकेगा. सर्दी शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है और कभी भी बर्फबारी हो सकती है. इसलिए प्रशासन ने यहां लोगों के जाने पर रोक लगा दी है. बता दें कि ये रोक हर बार लगाई जाती है. सर्दी में ठंड बढ़ने, बर्फबारी के अलावा इस मंदिर में जाने पर रोक की एक अन्य वजह भी है.

कपाट बंद, पुजारी ने भी छोड़ा मंदिर

हर बार सर्दी के ठीक पहले इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. यहां के पुजारी भी इस सर्दी के समय विपरीत परिस्थितियों के कारण यहां नहीं रहते. वहीं, अब एसडीएम मंडी ने भी आदेश जारी कर दिया कि कोई भी आदमी या ट्रैकर गर्मियों तक शिकारी माता मंदिर में नहीं जाएगा. यह फैसला जनता के हित को देखते हुए हर बार सर्दियों लिया जाता है.

कई लोग लापता, नहीं मिले

शिकारी माता मंदिर की ऊंची चोटी पर है. स्थानीय लोगों ने बताया, कई लोग प्रशासन के आदेश को नहीं मानते हुए सर्दी में शिकारी देवी मंदिर दर्शन करने पहुंच गए थे. बाद में उनमें से कुछ लोग लापता हो गए. कई लोगों की जान चली गई, जो लापता हुए उनका आजतक पता ही नहीं चला.

सफलता के लिए पढ़ाई के साथ कम्युनिकेशन स्किल भी जरूरी-कलेक्टर श्रीमती चौहान

डबरा में श्रीमती चौहान ने किया ई-लायब्रेरी का शुभारंभ व लायब्रेरी हॉल का भूमिपूजन

ग्वालियर। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की डबरा शाखा द्वारा निःशुल्क डिजिटल लायब्रेरी स्थापित की गई है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने गुरुवार को इस लायब्रेरी का शुभारंभ किया। साथ ही लायब्रेरी के लिये नवीन व अत्याधुनिक बनाने के लिए एक नए हॉल का भूमिपूजन भी उन्होंने इस अवसर पर किया। लायब्रेरी के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर श्रीतमी चौहान ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सफलता के लिये कड़ी मेहनत के साथ-साथ संप्रेषण दक्षता (कम्युनिकेशन स्किल) भी बेहतर होना जरूरी है। इसलिए सभी विद्यार्थी कड़ी मेहनत करें। साथ ही अपनी बात खुलकर रखने के लिए कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ाएं। डबरा में रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा शुरू की गई ई-लायब्रेरी में लगभग डेढ़ दर्जन कम्प्यूटर उपलब्ध हैं। खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को यहां पर निःशुल्क रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। ई-लायब्रेरी के उदघाटन अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने 7 कम्प्यूटर लायब्रेरी को दान में दिए। यह ई-लायब्रेरी प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेगी। ई-लायब्रेरी के शुभारंभ अवसर पर एसडीएम श्री दिव्यांशु चौधरी व रेडक्रॉस सोसायटी की डबरा शाखा के सचिव श्री दीपक भार्गव सहित सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

किसानों की सुविधा के लिए डबरा मंडी में टोकन व्यवस्था लागू होगी

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने डबरा मंडी के निरीक्षण के दौरान दिए निर्देश

ग्वालियर-चंबल संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडियों में से एक डबरा मंडी में किसानों की सुविधा के लिये टोकन व्यवस्था लागू होगी, जिससे किसान सुविधाजनक तरीके से अपनी धान की उपज बेच सकेंगे। साथ ही किसानों का श्रम व समय बचेगा। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश एसडीएम डबरा व कृषि उपज मंडी समिति के सचिव को दिए हैं। उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिससे किसानों को उपज बेचने के लिये अपनी बारी का कम से कम इंतजार करना पड़े। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने गुरुवार को कृषि उपज मंडी डबरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जानकारी दी गई कि डबरा मंडी में प्रतिदिन 1500 ट्रॉली उपज की खरीदी की व्यवस्था है। वर्तमान में यहाँ पर धान का सीजन होने की वजह से औसतन दो से ढ़ाई हजार धान की ट्रॉली प्रतिदिन पहुँच रही है। इससे किसानों को अपनी बारी का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने इस समस्या को ध्यान में रखकर यहाँ पर टोकन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। धान खरीदी की व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर कलेक्टर श्रीमती चौहान ने मंडी के आढ़तियों व किसानों से चर्चा की। इसके बाद मंडी प्रबंधन को निर्देश दिए कि प्रातःकाल मंडी के गेट पर ही किसानों को टोकन दे दिया जाए। जिस पर स्पष्ट लिखा हो कि उनकी ट्रॉली की खरीदी का कौन सा नम्बर है। कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी में खरीदी की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी इस मौके पर दिए। साथ ही कहा कि मंडी परिसर में किसानों के लिये पेयजल, छाया व अन्य बुनियादी सुविधायें पुख्ता रहें।

एक किसान द्वारा धान खरीदी के बाद तय रेट से कम भुगतान दिए जाने की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर कलेक्टर श्रीमती चौहान ने नाराजगी जताई। उन्होंने एसडीएम डबरा को इस शिकायत की जांच कर दोषी खरीददार के खिलाफ कार्रवाई करने और किसान को उसकी उपज के पूरे दाम दिलाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डबरा एसडीएम श्री दिव्यांशु चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उनके साथ थे।

स्कूली बच्चों के आधार पंजीयन एवं आधार अपडेट करने के लिये स्कूलों में लगेंगे शिविर

ग्वालियर-जिले के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आधार पंजीयन एवं अनिवार्य बायोमैट्रिक मोबाइल अपडेट करने के लिये विशेष शिविर लगने जा रहे हैं। इन शिविरों का आयोजन 16 से 23 नवम्बर तक किया जायेगा। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिविरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आधार शिविर के आयोजन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी व जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक को समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है। आधार पंजीयन व आधार अपडेट करने के लिये यह शिविर डबरा में संत कंवरराम हायर सेकेण्ड्री स्कूल व शासकीय गर्ल्स हायर सेकेण्ड्री स्कूल, भितरवार में दाताबंदी छोड़ अकादमी व शासकीय गर्ल्स हायर सेकेण्ड्री स्कूल आंतरी, घाटीगाँव में सेंट मार्क पब्लिक हाईस्कूल मोहना व शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल घाटीगाँव एवं ग्वालियर शहर में गौरीशंकर हाईस्कूल विनयनगर, सीएम राइज स्कूल पद्मा, नवयुग चिल्ड्रन स्कूल रामनगर, नागाजी पब्लिक हाईस्कूल हजीरा, आरएस कॉन्वेंट हायर सेकेण्ड्री सुभाषनगर लोहामंडी, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल दीनदयालनगर एवं सीएम राइज स्कूल हजीरा में आयोजित किए जायेंगे।

जीर्ण-शीर्ण भवन का कायाकल्प कर बनाया आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने किया सिमिरियाताल के इस आंगनबाड़ी केन्द्र का शुभारंभ

ग्वालियर। जिस जीर्ण-शीर्ण भवन में कुछ समय पहले तक गंदगी के अंबार लगे रहते थे और परिसर को जंगली झाड़ियों ने घेर रखा था। उस भवन की दीवारें अब सुंदर-सुंदर रंगों से बने मनोरम चित्रों के माध्यम से बनी शिक्षाप्रद कहानियों से शोभायमान है। इसी तरह भवन के फर्श भी बच्चों में लोकप्रिय सांप-सीढ़ी जैसे ज्ञानवर्धक इनडोर गेम आकर्षक रंगों से सज गए हैं। यहाँ बात हो रही है ग्वालियर जिले के सिमरियाताल के एक आंगनबाड़ी केन्द्र की। एक पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन का कायाकल्प कर जिसे आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र का रूप दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने गुरुवार को सजे-धजे इस आंनगबाड़ी केन्द्र का शुभारंभ किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं डबरा एसडीएम श्री दिव्यांशु चौधरी के प्रयासों से सीएसआर मद से पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन का जीर्णोद्धार कर उसे आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में तब्दील किया गया है। कुछ माह पहले सिमिरियाताल से होकर गुजर रहे एसडीएम श्री चौधरी की नजर गाँव में स्थित एक जीर्ण-शीर्ण भवन पर पड़ी थी। तभी उन्होंने इस भवन के कायाकल्प कर यहाँ पर आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का बीड़ा उठाया था, जो अब फलीभूत हो गया है। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जैसे ही फीता काटकर इस आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र का शुभारंभ किया तो आंगनबाड़ी केन्द्र से जुड़े बच्चे और उनकी मातायें खुशी से झूम उठीं। एक आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र में जिन सुविधाओं की उम्मीद की जाती है वे सभी सुविधायें इस केन्द्र में उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही बच्चों की रुचि के अनुरूप सम्पूर्ण आंगनबाड़ी भवन को सुंदर-सुंदर रंगों से बने प्रेरणादायक चित्रों के माध्यम से सजाया-संवारा गया है। साथ ही यहाँ पर पोषण वाटिका भी स्थापित की गई है। आंगनबाड़ी केन्द्र के शुभारंभ के बाद श्रीमती चौहान ने यहाँ की पोषण वाटिका में पौधा भी रोपा। साथ ही बच्चों को पोषण आहार कराया। आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र के शुभारंभ अवसर पर एसडीएम डबरा श्री दिव्यांशु चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री धीरेन्द्र सिंह जादौन, बाल विकास परियोजना अधिकारी डबरा श्रीमती बबीता धाकड़ व श्री अमित यादव तथा पर्यवेक्षक श्रीमती उर्मिला राजपूत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं ग्रामीणजन व आंगनबाड़ी के बच्चे मौजूद थे।

इंदौर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ई-कॉमर्स के क्षेत्र में डिजिटली सक्षम बनाने की दिशा में बड़ा कदम

एनआरएलएम और फ्लिपकार्ट ने मिलकर स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों को किया प्रशिक्षित,सांसद श्री शंकर लालवानी के मुख्य आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम

इन्दौर । भारत सरकार के लोकप्रिय अभियान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत इंदौर में महिला स्व—सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में अभिनव पहल की गई है। भारत के घरेलू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट की टीम की द्वारा महिलाओं को डिजिटली सक्षम बनाने की तकनीकी के बारे में प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम में सांसद श्री शंकर लालवानी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर फ्लिपकार्ट के मुख्य कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी श्री रजनीश कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। कलेक्टर कार्यालय के देवी अहिल्याबाई होल्कर सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद श्री शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारे देश की आधी आबादी आत्मनिर्भर बने। इसके लिए उन्हें डिजिटली तौर पर मजबूत होना होगा। श्री लालवानी ने फ्लिपकार्ट की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से निश्चित तौर पर महिलाएं मजबूत होगी और आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में सहभागी बनेगी। इस अवसर पर फ्लिपकार्ट के मुख्य कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी श्री रजनीश कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान में जोड़ना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मिशन है कि कैसे गांव और शहर के लोगों को डिजिटल क्रांति से जोड़े। इसके लिए सरकार ने खासतौर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर जोर दिया है, जो एक बड़ी वर्कफोर्स हैं। इसके लिए सरकार महिलाओं को घर बैठे रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है। साथ ही इन महिलाओं के प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से साझेदारी की है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बनाए गए प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ईकॉमर्स वेबसाइट है। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट के माध्यम से हमारा लक्ष्य है महिला उद्यमियों को विशेषज्ञता, संसाधनों और उनकी उद्यमशीलता की सफलता को बढ़ावा देने के माध्यम से राष्ट्रव्यापी बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। उन्होंने बताया कि किस तरह से देश भर में 18 लाख से अधिक स्व—सहायता समूह की महिलाओं के उत्पाद फ्लिपकार्ट के माध्यम बिक्री किए जा रहे हैं।कार्यशाला का संचालन जिला परियोजना प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत इंदौर श्री हिमांशु शुक्ला द्वारा किया गया।

मीटर परीक्षण प्रयोगशाला को मिला एनएबीएल सर्टिफिकेट

पोलोग्राउंड स्थित क्षेत्रीय मीटर प्रयोगशाला को नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फार टेस्टिंग कालिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) से वर्ष 2024 से लेकर वर्ष 2028 तक मीटर परीक्षण मान्यता मिल गई है। इस मान्यता से गुणवत्तापूर्ण परीक्षण के साथ ही स्मार्ट मीटर परियोजना के प्रभावी संचालन में मदद मिलेगी। वर्ष 2028 तक मीटर परीक्षण की राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिलने पर मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने मीटर टेस्टिंग टीम को बधाई दी एवं कंपनी हित में उत्तरोत्तर कार्य करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता श्री रवि मिश्रा, संयुक्त सचिव श्री संजय मालवीय, अधीक्षण यंत्री मीटर परीक्षण श्रीमती सुषमा गंगराड़े, मीटर परीक्षण शाखा के श्री आशीष वासनिक, श्री एस.एच. कुरैशी आदि मौजूद थे।

जनजातीय वर्ग के डेढ सौ से अधिक युवाओं को स्व-रोजगार के लिए मिलेगा 10 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण

इच्छुक युवाओं से मंगाये गए आवेदन

इंदौर जिले के जनजातीय वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए 10 हजार रुपये से 50 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। जिले में इस वर्ष 150 से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि यह ऋण राज्य शासन द्वारा संचालित भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत दिया जाएगा। इन योजनाओं के तहत इच्छुक युवाओं से आवेदन मंगाए गए है।

मप्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के प्रभारी अधिकारी श्री अजय सक्सेना ने बताया कि 'भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना' में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को वित्तीय सहायता के लिए लाभ नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना में केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को परियोजना सीमा पात्रता एवं वित्तीय सहायता आदि संबंधित प्रावधान होंगे। परियोजना सीमा उद्योग (विनिर्माण) ईकाई के लिये एक लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक तथा सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।(आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था इत्यादि का डिफाल्टर ना हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार का हितग्राही न हो। वित्तीय सहायता-ब्याज अनुदान (अ)- योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही को बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक (जो भी कम हो) की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा त्रैमासिक दिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। योजनांतर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही को 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑन लाईन/ ऑफ लाईन ट्रेनिंग माड्यूल के माध्यम से प्राप्त दिया जाएगा। पात्र परियोजनाएँ उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिये पात्र है। पात्र बैंक पब्लिक, प्रायवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो सीजीटीएमएसई में पंजीकृत हैं, उक्त योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा विकसित "समस्त पोर्टल" के माध्यम से किया जायेगा।

योजना में हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित निगम द्वारा वहन की जाती है। इसका क्रियान्वयन 'समस्त पोर्टल' से किया जा रहा है।

"टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना' के तहत युवाओं को 10 हजार रुपये से लेकर एक रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। बैंक ऋण पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं बैंक गारंटी सरकार द्वारा दिया जाने का प्रावधान है। इन दोनों योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्ति के लिए "समस्त पोर्टल" https://samast.mponline.gov.in पर लॉग-इन कर या सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तक होना चाहिए। आवेदक का आयकरदाता और बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

इंदौर में होगी ईएजी ग्रुप की 41वीं बैठक

अतिरिक्त सचिव भारत सरकार श्री विवेक अग्रवाल ने ली तैयारियों संबंधी बैठक

इन्दौर । वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन 41वीं यूरेशियन की बैठक 25 नवम्बर से 29 नवम्बर के बीच इंदौर में होगी। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस बैठक की तैयारी के लिए भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री विवेक अग्रवाल आज इंदौर आए और बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत में यह बैठक लगभग 16 वर्षों के बाद आयोजित हो रही है। इस प्रतिष्ठा पूर्ण आयोजन में सभी तैयारियां मानकों के अनुरूप की जाए। उन्होंने बताया कि यह बैठक मुख्य रूप से मनी लांड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ रणनीति बनाने के उद्देश्य से हो रही है। बैठक में संभागायुक्त श्री दीपक सिंह, कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं आयोजन से जुड़े सभी अधिकारी उपस्थित थे।कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बैठक में अब तक की गई तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट इंदौर में आगमन के समय प्रदेश की सांस्कृतिक झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। सभी अतिथियों का भारतीय परंपरा के अनुरूप स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट में इसके लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री आर. पी. अहिरवार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सभी अतिथियों के लिए शहर के विभिन्न होटल्स में आवास व्यवस्था की गई है। यहाँ पर उनके लिए मनी एक्सचेंज काउंटर और स्वास्थ्य चेकअप सुविधाएँ भी सुनिश्चित की गई है।

संभागायुक्त श्री दीपक सिंह के मार्गदर्शन में इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज एवं धार जिले के मांडव भ्रमण सहित इंदौर के प्रमुख पर्यटक स्थलों मे डेलीगेट्स के भ्रमण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। आयुक्त नगर निगम श्री शिवम वर्मा ने बैठक में बताया कि इस आयोजन की स्मृति को चिरस्थायी स्वरूप देने के लिए आयोजन स्थल के निकट ही वृक्षारोपण के लिए स्थान चयनित किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने बताया के आयोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रदर्शित करते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन भी प्रस्तावित है। साथ ही वहाँ पर मृगनयनी के माध्यम से के वस्त्रों की एक प्रदर्शनी का काउंटर भी लगाया जाएगा। श्री विवेक अग्रवाल ने दिल्ली से आए अन्य अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

विभिन्न अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी

सफल आयोजन के लिये कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। आयोजन संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी अपर आयुक्त नगर निगम श्री दिव्यांक सिंह को, विमानतल पर व्यवस्था के दायित्व सीईओ आईडीए श्री रामप्रकाश अहिरवार, कार्यक्रम स्थल व्यवस्था अपर कलेक्टर श्रीमती ज्योति शर्मा, डेलीगेट्स के होटल में रूकने संबंधी व्यवस्था अपर आयुक्त नगर निगम श्री रोहित सिसोनिया, स्वल्पाहार एवं भोजन संबंधी व्यवस्था अपर कलेक्टर श्री गौरव बेनल, बीसीसी सेंटर पर कन्ट्रोल रूप व्यवस्था उपायुक्त भू-अभिलेख श्री श्यामेन्द्र जायसवाल, आगन्तुकों की भ्रमण व्यवस्था अपर आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा, डेली कॉलेज संबंधी भ्रमण व्यवस्था क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रिंकेश वैश्य, मांडव भ्रमण संबंधी व्यवस्था सीजीएम श्री प्रकाश चौहान, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था अपर संचालक एनवीडीए श्री शैलेन्द्र सोलंकी, अति विशिष्ट एवं प्रतिनिधियों के लिए परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर श्री रोशन राय, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्धार्थ जैन को सौंपी गई है। आयोजन के दौरान कार्यक्रम स्थल और अन्य शहर की संपूर्ण यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य डीसीपी ट्रैफिक श्री अरविंद तिवारी, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अधीक्षक यंत्री एमपीईबी श्री मनोज शर्मा, अतिथियों द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण की व्यवस्था अपर आयुक्त नगर निगम श्री अभय राजनगांवकर को दायित्व सौंपे गए है। उक्त दल प्रभारी के साथ अन्य अधिकारियों को भी आवश्यक जिम्मेदारी दी गई है।

SDM थप्पड़कांड में गिरफ्तार नरेश मीणा का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड, इतने मामले पहले से ही दर्ज

राजस्थान की देवली-उनियारा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश कुमार मीणा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और उन्हें राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वह बुधवार की रात मौके से फरार हो गए थे, लेकिन भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में समरवता गांव से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इसकी पुष्टि खुद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की है.

टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने बुधवार को एक मतदान केंद्र पर SDM अमित चौधरी के साथ मारपीट की थी. सरकारी अधिकारी पर ड्यूटी के वक्त मारपीट करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है. नरेश मीणा के ऊपर यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी उनके खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं.

2002-2010 के बीच इतने केस

नरेश मीणा के खिलाफ सबसे पहले 2002 में केस दर्ज किया गया था. यह जयपुर में मारपीट का मामला था. 2004 में हाइवे जाम करने के मामले में आपराधिक केस दर्ज हुआ था. 2004 में ही राजकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट का केस हुआ था. 2005 में चोरी के आरोप में केस किया गया था तो 2006 में मारपीट के आरोप में केस हुआ था.

उनपर निजी संपत्ति की तोड़फोड़ और मारपीट का मामला 2009 में दर्ज किया गया था. 2010 में ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने का केस किया गया था. इसी साल उनपर 5 लोगों के साथ मारपीट करने और प्रताड़ित करके छोड़ने का केस किया गया था. इसके अलावा जुए का एक मामला दर्ज

हुआ था.

2010 से 2020 के बीच इन मामलों में आरोपी

2012 में हथियार बरामद किए जाने पर नरेश मीणा पर केस किया गया था. यह मामला जयपुर में दर्ज है. 2014 और 2017 में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. 2020 में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कोरोना संक्रमण का फैलाव करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस किया गया था.

2023-2024 के केस

2023 में सरकारी काम में बाधा पैदा करने, रेल मार्ग को अवरूद्ध करने और उपद्रव की स्थिति पैदा करने का आरोप है और थाने में केस भी दर्ज है. 2023 में ही भड़काऊ भाषण देकर उपद्रव पैदा करने का आरोप है. विधानसभा चुनाव में सरकारी काम में बाधा डालने और सरपंच के साथ मारपीट करने का केस किया गया है तो 2024 में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में आपराधिक केस दर्ज है.

आरोपी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद भारी बवाल, समर्थकों ने की आगजनी

टोंक जिले के समरवता गांव से नरेश मीणा को गिरफ्तारी किया गया है. उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर से बवाल शुरू हो गया है. उनके समर्थकों ने आगजनी की है. टोंक जिले के देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीना पर बुधवार को मतदान केंद्र पर एसडीएम अमित चौधरी के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है. निर्दलीय प्रत्याशी की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों की ओर से समरावता गांव के बाहर स्टेट हाईवे पर आग लगाने के बाद पुलिस मौके पर समर्थकों को तितर-बितर करने पहुंची. इसके बाद पुलिस ने अवरुद्ध की गई सड़क को खाली कराया.

नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर क्या बोली पुलिस?

नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर टोंक एसपी विकास सांगवान ने कहा कि हमने उनसे कहा कि कानून को हाथ में न लें और अपने आपको समर्पित कर दें. उनका मन नहीं था, लेकिन उन्हें पुलिस के आगे झुकना पड़ा. उनपर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. उनपर कई पुराने मामले भी दर्ज हैं, जिसकी रिपोर्ट मंगवाई गई है. 50-60 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी लोग जो भी इसमें शामिल होंगे, उन्हें पकड़ा जाएगा.

नरेश मीणा की भी आई थी प्रतिक्रिया

गिरफ्तारी से पहले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की भी प्रतिक्रिया आई थी. उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है. बड़े-बड़े लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन मैं यहीं बैठा हूं. मिर्ची बम की वजह से मैं बेहोश हो गया था, मैं कही फरार नहीं हुआ था. पथराव के बाद मैं वहां से भागा नहीं बल्कि मिर्ची बम की वजह से बेहोश हुआ तो लोग मुझे उठाकर गांव में ले आए थे. मीणा ने आगे कहा कि विधायक बनने से ही सब कुछ थोड़ी हो जाता है. मैं गांव में ही पैदा हुआ हूं, एक आदमी को जाति प्रमाण पत्र बवनाने के लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं, बिना चक्कर काटे कोई काम नहीं होते. उन्होंने आगे कहा, "एसडीएम की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मैं उसे पीटता. उनके तौर-तरीकों को सुधारने का यही एक इलाज है. हमने सुबह से कुछ नहीं किया, हम उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हमारे लिए खाने का इंतजाम नहीं किया गया.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्यप्रदेश पुलिस का अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर कड़ा प्रहार

प्रदेशव्यापी विशेष अभियान के पहले दिन ही 10 करोड़ से अधिक कीमत के अवैध मादक पदार्थ जब्त आठ घंटे के अंदर ही सात सौ किलोग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ जब्त भोपाल में क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 8.4 किलो चरस

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मंशानुसार मध्यप्रदेश पुलिस अवैध नशे के कारोबार को नेस्तनाबूद करने के लिए निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में डीजीपी श्री सुधीर सक्सेना के निर्देश पर मध्यप्रदेश पुलिस ने आज 14 नवम्बर को सुबह 8 बजे से अवैध मादक पदार्थों के कारोबार की रोकथाम के लिए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पहले ही दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सुबह से शाम तक कार्रवाही कर मात्र आठ घंटो में 10 करोड़ रूपए से अधिक की कीमत के सात सौ किलोग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं।

भोपाल, खरगौन, सिवनी, छिंदवाड़ा और नीमच में हुई बड़ी कार्रवाही

प्रदेशव्यापी अभियान के पहले दिन पुलिस ने 43 स्थानों पर अवैध मादक पदार्थ जब्त करने में सफलता पाई है। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने 8.4 किलोग्राम चरस, खरगोन जिले के चैनपुर में 478 किलोग्राम गांजा, सिवनी जिले के धनौरा में 80 किलोग्राम गांजा, छिंदवाड़ा जिले के कोतवाली थाना में 42.100 किलोग्राम गांजा तथा नीमच के रतनगढ़ थाना में 60 किलोग्राम डोडाचूरा जब्त हुआ है। साथ ही 18 आरोपियों सहित 6 कार एवं एक ट्रक भी पुलिस ने जब्त किए हैं। इस प्रकार प्रदेश में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाही कर 37.58 ग्राम स्मैक, 649 ग्राम ब्राउन शुगर, 60 किलो डोडा चूरा, 61 ग्राम एमडी सहित 56 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध मादक पदार्थों के परिवहन में प्रयुक्त 11

वाहनों को भी जब्त किया है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा कई संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर अवैध मादक पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में मादक पदार्थों के उत्पादन और वितरण में शामिल आपराधिक तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य न केवल अवैध मादक पदार्थों पर रोक लगाना है, बल्कि जनता में इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। इस पहल के माध्यम से सरकार राज्य को अवैध नशामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें हर संभव प्रयास कर रही है।

मंगल पर क्यों इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं एलन मस्क, कौन करेगा यूज़, क्या है प्लान?

एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के जरिए मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह इंटरनेट सुविधा देने का प्लान पेश किया है. नासा को दिए प्लान में उन्होंने प्रस्ताव किया है कि जिस तरह पृथ्वी की कक्षा में हजारों सैटेलाइट स्थापित कर उन्होंने स्टारलिंक नेटवर्क तैयार किया है, उसी तरह वे मंगल पर भी मार्सलिंक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं.

आप किसी जगह पर यात्रा के लिए जा रहे हैं तो वहां कौन कौन सी सुविधाओं के होने की उम्मीद करेंगे? पीने के लिए साफ पानी, आपके खाने लायक भोजन, और भी बहुत कुछ. पर इस सूची में इंटरनेट आप कहां रखेंगे. शीर्ष 10 में या शीर्ष 5 में. पर मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें इंसानों के लिए वहां तैयार की जाने वाली सुविधाओं में इंटरनेट भी है और एलन मस्क मंगल ग्रह पर बिलकुल वैसी ही सुविधा देने की तैयारी में हैं जैसी वे पृथ्वी पर स्टारलिंक के जरिए दे रहे हैं. जी हां, आपने सही सुना है. जिस तरह अमेरिका और दुनिया के कई देशों में एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधाएं दे रहा है, वैसी ही सुविधाओं से लिए उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने मंगल ग्रह पर देने के लिए प्रस्ताव पेश किया है.

नासा को दिया प्रस्ताव

यह इंटरनेट भविष्य में ग्रह पर जाने वाले अभियानों के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करने का काम करेगा. मार्सलिंक नाम के इस प्रस्ताव हाल ही में नासा की अगुआई में हुए मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एनालिसिस ग्रुप की मीटिंग में दिया गया था. इसमें स्पेस एक्स ने मंगल ग्रह की कक्षा में स्पेसएक्स के सैटेलाइट स्थापित किए जाएगे जिससे वहां डेटा एक्सचेंज के लिए इस तरह का सिस्टम तैनात किया जाएगा.

एलन मस्क की महत्वाकांक्षा योजना का हिस्सा

यह प्रस्ताव स्पेस एक्स के मंगल ग्रह पर अन्वेषण अभियानों का समर्थन करने और इंसानी बस्ती बसाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है. स्पेसफ्लाइट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मार्सलिंक नेटवर्क अभी पृथ्वी पर चल रहे स्टारलिंक सिस्टम की तरह काम करेगा जिसके तहत अभी पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित कर पूरे ग्रह को इंटरनेट सुविधा दी जा रही है.

क्या होगा ऐसे नेटवर्क का काम?

फिलहाल स्टारलिंक के हजारों सैटेलाइट दुनिया के 102 देशों के ऊपर स्थापित किए जा चुके हैं. मस्क इसी तरह का नेटवर्क मंगल ग्रह पर स्थापित करना चाहते हैं. मार्सलिंक के बनने से ना केवल मंगल की सतह पर संचार सुविधाएं तेज होंगी, बल्कि मंगल और पृथ्वी के बीच भी संचार बेहतर हो सकेगा. इससे नासा के मंगल ग्रह के अन्वेषण और अध्ययन के लिए जाने वाले अभियानों के लिए भी काफी मददगार साबित होगा.

और भी आए ऐसे प्रस्ताव

इस तरह का प्रस्ताव केवल स्पेसएक्स ने ही नहीं दिए थे. नासा ने ब्लू ओरिजन और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों के भी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया. ब्लू ओरिजिन कंपनी ने ब्लू रिंग ऑर्बिटल टग विचार दिया जिसका उपयोग आंकड़े भेजने और स्पेस में ही क्लाउड कम्प्यूटिंग प्रोसेसिंग के लिए किया जा सकेगा. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह परियोजना पैंटागन के प्रायोजित डार्क स्काई1 मिशन के लिए उपयोग में लाया जाना है जिसकी प्रक्षेपण तारीख तय नहीं हुई है.

पृथ्वी की ही तरह डीप स्पेस नेटवर्क भी

वहीं लॉकहीड मार्टिन ने प्रस्ताव दिया कि MAVEN अंतरिक्षयान का ही उपयोग किया जाए जो साल 2013 में मंगल के वायुमंडल के अध्ययन के लिए भेजा गया था. लॉकहीड का प्रस्ताव है कि मेविन यान के ही संचार कक्षा में ले जा कर नासा के पृथ्वी पर बने डीप स्पेस नेटवर्क से तरह काम करेगा.

नासा की निजी क्षेत्र से भागीदारी

नासा अब मंगल के अन्वेषण अभियानों के लिए निजी क्षेत्र की परियोजनाओं पर ज्यादा जोर देकर व्यवसायिक साझेदारियों पर विचार कर रहा है. एजेंसी ऐसी कंपनियों पर भागीदारी करना चाहती है जो भविष्य के मानव अभियानों के लिए जरूरी तकनीकी संसाधन मुहैया करा सकें. नासा लेसर आधारित तकनीकों पर भी काम कर रही है जो गहरे अंतरिक्ष में ज्यादा तेज और कारगर संचार उपलब्ध करा सकती हैं. गौर तलब है कि अभी तक नासा और अन्य निजी

कंपनियां भी मंगल ग्रह की लंबी यात्रा को इंसानों के लिए सुगम और संभव बनाने के लिए आने वाली सारी चुनौतियों के समाधान नहीं निकाल पाई हैं. इनमें तेजी से मंगल ग्रह पर इंसान को लाने और वापस लाने का सिस्टम, इंसान को लंबे समय तक वहां रह पाने, मंगल ग्रह पर ऑक्सजीन, ईंधन आदि शामिल है. इन सभी पर गहन प्रयोग चल रहे हैं.

ट्रंप के 'वफ़ादार' और भारतीय मूल के काश पटेल का नाम इतनी चर्चा में क्यों है?

20 जनवरी, 2025 को ट्रंप का राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके बाद वो आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद की शक्तियां हासिल कर पाएंगे.अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति करीब 4 हजार राजनीतिक नियुक्तियां करता है, जिसमें कई महीनों का वक़्त लगता है.

पहली आधिकारिक नियुक्ति के रूप में ट्रंप ने सुसन समरॉल वाइल्स (सूजी वाइल्स) को अपना चीफ़ ऑफ स्टाफ़ बनाया है. ट्रंप के इस चुनावी अभियान में सुसन सह अध्यक्ष थीं. इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी सीमाओं की जिम्मेदारी के लिए टोम होमन, संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के लिए एलिस स्टेफनिक और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी प्रमुख के लिए ली जेल्डिन को चुना है.कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे ट्रंप प्रशासन में बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं.इन नामों में कई भारतीय मूल के भी हैं. विवेक रामास्वामी के अलावा एक बड़ा नाम कश्यप प्रमोद पटेल उर्फ़ काश पटेल का भी है.

44 साल के पटेल को डोनाल्ड ट्रंप के सबसे वफ़ादार लोगों में गिना जाता है.

मिल सकती है अहम ज़िम्मेदारी

मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि ट्रंप प्रशासन में काश पटेल को अमेरिका की खुफ़िया एजेंसी सीआईए का प्रमुख बनाया जा सकता है.

सीआईए यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी वैश्विक मुद्दों और अलग-अलग देशों के बारे में खुफ़िया जानकारी इकट्ठा करती है जिसे राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और दूसरी संस्थाओं के साथ साझा किया जाता है. ये खुफ़िया जानकारियां अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय लेने में मदद करती हैं.इसमें आतंकवाद से लड़ना, परमाणु और गैर परंपरागत हथियारों के विस्तार को रोकना, विदेशी जासूसों से देश की रक्षा करना और दूसरे देशों की जासूसी करना भी शामिल है.

अमेरिका के वर्जीनिया में सीआईए का मुख्यालय है. इस एजेंसी का निदेशक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनते हैं जिसके लिए सीनेट की मंज़ूरी ज़रूरी होती है. सीआईए के निदेशक राष्ट्रीय खुफ़िया निदेशक को रिपोर्ट करते हैं.

इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक काश पटेल अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मिलर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम कर चुके हैं. इससे पहले पटेल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में राष्ट्रपति के डिप्टी असिस्टेंट और आतंकवाद निरोधक विभाग के वरिष्ठ निदेशक रहे हैं. रक्षा विभाग के मुताबिक ट्रंप कार्यकाल के दौरान पटेल ने कई बड़े अभियानों में अहम भूमिका निभाई है. उनके रहते हुए ही आईएसआईएस के मुखिया अल बगदादी, अल क़ायदा के कासिम अल रिमी को मारने के अलावा अमेरिकी बंधकों की सुरक्षित वापसी हुई थी. वे नेशनल इंटेलिजेंस के कार्यवाहक निदेशक के प्रिंसिपल डिप्टी भी रहे हैं. इस भूमिका में वे 17 खुफ़िया एजेंसियों के संचालन की देखरेख करते थे और हर रोज राष्ट्रपति को ब्रीफ़िंग देते थे. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने से पहले पटेल ने खुफ़िया मामलों पर स्थायी चयन समिति के लिए वरिष्ठ वकील के तौर पर काम किया था.

यहां उन्होंने 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर रूसी अभियान की जांच का नेतृत्व किया था.

काश पटेल ने इंटेलिजेंस कम्युनिटी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के लिए संवेदनशील कार्यक्रमों की देखरेख की है.उन्होंने दुनिया भर में इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म को अरबों डॉलर फंड करने वाले क़ानून को बनाने में भी मदद की है. खुफ़िया मामलों पर स्थायी चयन समिति के लिए काम करने से पहले पटेल ने अमेरिका के न्याय विभाग में आतंकवाद अभियोजक के रूप में काम किया.उन्होंने अपना करियर एक वकील के रूप में शुरू किया, जहां उन्होंने हत्या, ड्रग्स से लेकर पेचीदा वित्तीय अपराधों के मामले अदालतों में लड़े.

काश पटेल का निजी जीवन

काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था और उनके पिता एक एविएशन कंपनी में काम करते थे. पटेल न्यूयॉर्क के मूल निवासी हैं. उन्होंने रिचमंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क वाप आकर कानून की डिग्री हासिल की. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून में ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से सर्टिफिकेट भी लिया है. वे आइस हॉकी खेलना बहुत पसंद है.काश पटेल त्रिशूल नाम से एक कंपनी चलाते हैं. साल 2023 में इस कंपनी ने ट्रंप की वेबसाइट ट्रूथ सोशल से कंसल्टिंग फीस के रूप में करीब एक करोड़ रुपये लिए थे.त्रिशुल ने ट्रंप समर्थक सेव अमेरिका इकाई को भी परामर्श देने का काम किया है और यहां से भी पिछले दो सालों में एक करोड़ रुपये से ज्यादा लिए हैं.

भारत समर्थक रहीं निकी हेली को ट्रंप ने सरकार में जगह नहीं देने की घोषणा क्यों की?

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रहीं निकी हेली को अपनी नई सरकार में शामिल नहीं करने की घोषणा की है.निकी हेली के माता-पिता अजित सिंह रंधावा और राज कौर रंधावा भारतीय मूल के थे. निकी हेली के माता-पिता अमृतसर के थे. निकी हेली खुलकर भारत का समर्थन करती रही हैं. वहीं माइक पॉम्पियो भी चीन के ख़िलाफ़ मुखर होकर बोलते रहे हैं. लेकिन ट्रंप ने दोनों को अपनी सरकार में नहीं रखने का फ़ैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पिछली सरकार के दौरान भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए कुछ अहम घोषणाएं की थीं. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'ट्रूथ' पर लिखा है, मैं पूर्व राजदूत निकी हेली या पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को अगली सरकार में शामलि होने के लिए आमंत्रित नहीं करूंगा. ट्रंप का कहना है , "मुझे पहले उनके साथ काम करने का मौक़ा मिला है और मैंने उनके कामकाज की प्रशंसा की है. देश की सेवा के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ." निकी हेली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए लिखा है, "मुझे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का पक्ष रखने पर गर्व है. मैं उन्हें और उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों को अगले चार साल में अमेरिका को एक मज़बूत और सुरक्षित देश बनाने में सफलता की कामना करती हूँ."

भारत के समर्थन में निकी हेली ने क्या कहा था?

डोनल्ड ट्रंप ने निकी हेली को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत बनाया था. निकी हेली ने अक्टूबर 2021 में अमेरिकी पत्रिका 'फॉरन पॉलिसी' में रिपब्लिकन सांसद माइक वॉल्ट्ज़ के साथ एक लेख लिखा था. इस लेख में निकी हेली ने कहा था कि चीन मध्य और दक्षिण एशिया में और पाँव पसारे, उससे पहले भारत-अमेरिका को साथ मिलकर उसे रोक देना चाहिए.

इस लेख में निकी हेली ने कहा था, "अफ़ग़ानिस्तान से विनाशकारी वापसी के बाद हमने देखा कि ब्रिटिश संसद में वहाँ के मंत्रियों ने बाइडन की खुलकर आलोचना की. फ़्रांस ने असाधारण क़दम उठाते हुए अपने राजदूतों को बुला लिया. हमने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन निर्माण के मामले में जर्मनी के सामने घुटने टेक अपने पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों को अलग कर दिया."

हेली ने कहा था, "अपने दोस्तों को अपमानित करने और दुश्मनों को नज़रअंदाज़ करने के बजाय अमेरिका को उन रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनसे दुनिया भर में हमारी स्थिति मज़बूत हो."निकी हेली कहती हैं, "इसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए. अब समय आ गया है कि हम एक गठबंधन बनाया जाए. 10 लाख सैनिक, परमाणु शक्ति संपन्न, नौ सेना की बढ़ती ताक़त, अंतरिक्ष कार्यक्रम में अव्वल और अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य संबंधों के आज़माए हुए अतीत के साथ भारत एक मज़बूत सहयोगी बन सकता है. भारत के साथ सहयोग से दोनों देशों को वैश्विक ताक़त बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ लाकर अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान में आतंकी ख़तरा और चीन का काउंटर कर सकता है.

'महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर फिर EC पहुंची कांग्रेस, पीएम मोदी- अमित शाह पर लगाए ये आरोप

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और भाजपा और उसके नेताओं के खिलाफ उनके निर्लज्ज चुनावी उल्लंघनों की जांच करने के लिए कहा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि लेटर में कहा गया है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री ने महाराष्ट्र और झारखंड में विभाजनकारी, झूठे और दुर्भावनापूर्ण भाषण दिए हैं.

चिट्ठी में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस प्रमुख नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों, जैसे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी के खिलाफ आरोप लगाए. मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विरोधी हैं.

'पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी लगाए आरोप'

चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाए और दावा किया

कि कांग्रेस एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के हितों के खिलाफ है. झारखंड में भाजपा के अभियान में जो एक आम कहानी बन गई है, उसमें अमित शाह ने INC पर ST, SC और OBC समुदायों के सदस्यों से आरक्षण छीनने और उन्हें एक विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को देने की योजना बनाने का भी आरोप लगाया है.

'अमित शाह ने अपने भाषण में किए झूठे वादे'

अमित शाह की ओर से दिए गए बयान केवल धर्म और जाति के आधार पर मतदाताओं को भड़काने के इरादे से दिए गए हैं. वोटों को एकजुट करने और सांप्रदायिक असुरक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए. शाह ने अपने अभियान भाषण के माध्यम से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिष्ठा को खराब करने, धर्म और जाति के आधार पर दुश्मनी भड़काने और आम जनता को गुमराह करने के लिए झूठे दावे किए हैं.

BJP के वीडियो पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस की शिकायत के अनुसार, झारखंड में भाजपा के फेसबुक हैंडल ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जैसे दिखने वाले कलाकार थे. उक्त वीडियो में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर झूठे और अवैध आरोप लगाए गए थे और कांग्रेस पर "आदिवासी विरोधी" का ठप्पा लगाया गया था.

'अमित शाह का भाषण विभाजनकारी चुनावी अभियान का हिस्सा'

कांग्रेस के लेटर में कहा गया कि वास्तव में हमारा मानना है कि शाह का भाषण और उनके बयान भी झारखंड चुनाव के लिए इस विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण चुनावी अभियान का हिस्सा हैं. कांग्रेस उस बात पर कड़ी आपत्ति

83 सीटें बिगाड़ सकती हैं महायुति का खेल

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 158 निर्वाचन क्षेत्र तय करेंगे कि राज्य की सत्ता की चाबी महायुति के पास जाएगी या महाविकास अघाड़ी के पास. इन 158 निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी बनाम कांग्रेस, शिंदे की शिवसेना बनाम, ठाकरे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी बनाम शरद पवार की एनसीपी है. लेकिन, आरएसएस को चिंता बीजेपी की नहीं, बल्कि उन 83 सीटों की है, जहां शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार का शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार से मुकाबला है.

ये 83 सीटें तय करेंगी कि राज्य में बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है या नहीं, असली शिवसेना शिंदे की है या ठाकरे की और असली राष्ट्रवादी अजित पवार है या शरद पवार.

2019 के बाद बदले समीकरण

2019 के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो महायुति और महा विकास अघाड़ी में दो पार्टियां थीं, जो मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी और एनसीपी शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी. लेकिन, 2019 के बाद बदले समीकरण में महायुति और महा विकास अघाड़ी में तीन-तीन पार्टियों का गठबंधन बन गया. इसलिए 2024 के विधानसभा चुनाव में सीधी लड़ाई का समीकरण बन गया है.

कहां किसके बीच होगी सीधी टक्कर

विदर्भ की 35, मराठवाड़ा की 10, पश्चिमी महाराष्ट्र की 12, मुंबई की 8, उत्तरी महाराष्ट्र की 6 और कोंकण की 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है.

महाराष्ट्र में अगर महायुति जीती तो एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे CM? नया होगा नाम!

महाराष्ट्र में चुनावी माहौल अपने शबाब पर है. महा विकास अघाड़ी और महायुति के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी बीच बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने महायुति गठबंधन के एक बार फिर से सत्ता में आने का दावा किया. इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर टिप्पणी की. तावड़े ने कहा कि पार्टी में तय हुआ है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर चर्चा होगी.

बीजेपी नेता ने एक मराठी अखबार को दिए इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पर कहा कि महायुति में संख्या बल पर मुख्यमंत्री पद तय होने जैसी कोई बात नहीं है, हम चुनाव के बाद इस पर फैसला करेंगे. संख्या बल पर ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार में हमारे विधायक ज्यादा हैं, लेकिन हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है. उन्होंने कहा कि हमें महाराष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बनाना होगा. उन्होंने कहा कि सरप्राइज नाम हो सकता है.

'महायुति को 160 सीटें मिलेंगी'

वहीं एक अन्य सवाल पर तावड़े ने कहा कि मनसे के साथ कुछ सीटों पर सहमति बनी थी. लेकिन, बाद में शिवसेना ने माहिम सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया. अब बीजेपी राज्य में 95 से 110 सीटें जीतेंगी. वहीं अजित पवार की एनसीपी 25 से 30 सीटें और शिवसेना

शिंदे 40-45 सीटों पर जीत दर्ज करेगी. महायुति को 160 सीटें मिलेंगी.

उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने एक समुदाय का मुद्दा उठाया था. जिसकी वजह से छोटे-छोटे समुदाय उनके खिलाफ हो गए. इसलिए हम जीत गए. हरियाणा में हमारी सरकार आई, वैसे ही महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार आएगी.

इससे पहले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी प्रतिक्रिया आई थी. उन्होंने कहा कि यह चुनाव एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों के नेतृत्व में हो रहा है और पार्टी हाईकमान और चुनाव के बाद चुने हुए प्रतिनिधि अपने नेता का चयन करेंगे.पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा.

डिजिटल अरेस्ट में एमपी पुलिस की गजब परफॉर्मेंस, CM मोहन यादव ने कर दी तारीफ, लिया बड़ा फैसला

देश में बीते कुछ समय से साइबर अपराध की घटनाओं में बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। इसमें 'डिजिटल अरेस्ट' की घटनाएं बड़ी संख्या में बढ़ती जा रही है। अब भोपाल ने पुलिस ने एक कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट से बचाया है और उसका करोड़ों रुपये का नुकसान होने से बचा लिया है। पुलिस अधिकारियों ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी साझा की है। साइबर अपराधियों ने शनिवार को कारोबारी को फोन कर के खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) का अधिकारी बताया था।कैसे किया डिजिटल अरेस्ट?

दरअसल, भोपाल के अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक ओबेरॉय को शनिवार को एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया। शख्स ने कारोबारी से कहा कि उनके आधार कार्ड की मदद से कई बैंक अकाउंट खोले गए हैं और उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए सिम कार्ड खरीदने के वास्ते भी किया गया है। साइबर अपराधियों ने ओबेरॉय को स्काइप वीडियो कॉलिंग ऐप डाउनलोड कर उन्हें एक कमरे में रहने को कहा।

पुलिस ने ऐसे बचाया

जब कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट किया गया उसी वक्त उसने मध्यप्रदेश साइबर पुलिस को सूचित कर दिया। डिजिटल अरेस्ट के दौरान ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने जब फर्जी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अपनी पहचान बताने के लिए कहा तो अपराधियों ने वीडियो कॉल काट दी। पुलिस के मुताबिक, अपराधियों को कारोबारी के बैंक खातों की जानकारी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने कोई रकम ट्रांसफर नहीं की।

क्या होता है डिजिटल अरेस्ट?

डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधियों की ओर से ठगी के लिए लाया गया नया तरीका है। इस मामले में ठग खुद को कानूनी एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। फिर लोगों को ऑडियो या वीडियो कॉल करके डराते हैं और उन्हें उनके घर में डिजिटल तौर पर बंधक बना लेते हैं। इसके बाद पीड़ित से उनके बैंक अकाउंट आदि की जानकारी लेकर उनसे ठगी की जाती है।

खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 6 फीसदी के पार, खाद्य महंगाई दर रही 10.87 फीसदी

खाने-पीने की चीजों के दामों में तेज बढ़ोतरी के चलते अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर 6 फीसदी को पार करते हुए 6.21 फीसदी पर जा पहुंची है. सितंबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 5.49 फीसदी रही थी. अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) आरबीआई (Reserve Bank Of India) के टोलरेंस बैंड 6 फीसदी के भी पार जा पहुंची है. अक्टूबर महीने में खाद्य महंगाई दर में भी तेज उछाल देखने को मिला है और ये डबल डिजिट को पार करते हुए 10.87 फीसदी पर जा पहुंची है.

डबल डिजिट में खाद्य महंगाई दर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अक्टूबर 2024 में रिटेल इंफ्लेशन रेट 6.21 फीसदी पर जा पहुंची है. एक साल पहले अक्टूबर 2023 में खुदरा महंगाई दर 4.23 फीसदी रही थी. ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 6.68 फीसदी और शहरी इलाकों में 5.62 फीसदी रही है. मंत्रालय ने बताया कि खुदरा महंगाई दर में ये तेज उछाल, सब्जियों, फलों, ऑयल और फैट्स की कीमतों में तेज उछाल के चलते देखने को मिला है. अक्टूबर 2024 में खाद्य महंगाई दर डबल डिजिट में चला गया है और ये 10.87 फीसदी रही है जो सितंबर में 9.24 फीसदी रही थी. ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 10.69 फीसदी तो शहरी इलाकों में 11.09 फीसदी रही है.

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ये हैं बेस्ट जगहें, राजा-रानी जैसा होता है एहसास, शादी करने दुनिया भर से आते हैं लोग

उदयपुर. राजस्थान का उदयपुर शहर अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है और अब यह एक बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है. उदयपुर में लग्जरी होटल्स और शानदार महलों में शादी के आयोजन के लिए हर साल न केवल भारत बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं. यहां के रॉयल वेडिंग न केवल एक शानदार अनुभव देती है, बल्कि एक राजा-रानी जैसा एहसास भी कराती है.

उदयपुर के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन

1. **सिटी पैलेस उदयपुरः** सिटी पैलेस उदयपुर में रॉयल वेडिंग का आयोजन एक राजसी अनुभव है. यहां एक दिन का किराया करीब 25 लाख रुपए से शुरू होता है, जो कि आपके बजट के हिसाब से समायोजित किया जा सकता है.

2. **ताज लेक पैलेसः** पिछोला झील के बीच स्थित यह शानदार पैलेस दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है. ताज महल पैलेस के एक दिन का किराया करीब 35 लाख रुपए से शुरू होता है, और यहां का संगमरमर का महल वर्ल्ड वेडिंग को अविस्मरणीय बनाता है.

3. **द लीला पैलेसः** पिछोला झील के किनारे स्थित द लीला पैलेस होटल, अपनी शानदार शीश महल और लग्जरी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है. परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जैसी मशहूर

हस्तियों ने अपनी शादी के लिए इस होटल को चुना. यहां का एक दिन का किराया करीब 30 लाख रुपए से शुरू होता है.

4. **ताज अरावली होटलः** यह होटल अपने भव्य सेटअप और लग्जरी सुविधाओं के लिए खास पहचान रखता है. आमिर खान की बेटी की शादी समेत कई मशहूर सेलिब्रिटीज की शादियां यहां हुई है. एक दिन का किराया करीब 20 लाख रुपए से शुरू होता है.

5. **राफेल्स होटलः** उदयसागर झील के किनारे स्थित यह होटल क्रिकेटर्स समेत कई बड़े सेलिब्रिटीज की पसंदीदा शादी स्थल है. हार्दिक पांड्या ने भी अपनी शादी के लिए इस होटल को चुना था यहां का किराया भी करीब 30 लाख रुपए से शुरू होता है.

16 दिसंबर को दक्षिण भारत दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी ट्रेन, इन तीर्थस्थलों का कर सकेंगे भ्रमण

तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. ट्रेन 16 दिसंबर को इंदौर से रवाना होगी.

मध्यप्रदेश के इंदौर से भारत गौरव पर्यटन यात्रा के तहत 16 दिसंबर को दक्षिण भारत दर्शन यात्रा शुरू हो रही है. यह यात्रा दस दिन की होगी और दक्षिण भारत के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का पर्यटक भ्रमण कर सकेगे.

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. इसके तहत ट्रेन 16 दिसंबर को इंदौर शहर से "दक्षिण दर्शन यात्रा" के लिए रवाना होगी.

यह ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल स्टेशनों से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगे. यह यात्रा नौ रात और 10 दिन की है. इस यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी एवं त्रिवेंद्रम के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा.आईआरसीटीसी की ओर से पेश सर्व समावेशी टूर में भारत गौरव ट्रेन के विशेष एलएचबी रेक में आरामदायक रेल यात्रा, ऑन-बोर्ड और ऑफ-बोर्ड भोजन, सड़क परिवहन और लग्जरी बसों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा, यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आवास की व्यवस्था, यात्रा में टूर एस्कॉर्ट्स, यात्रा बीमा, ऑन-बोर्ड सुरक्षा और हाउसकीपिंग की सेवा शामिल है.

बताया गया है कि इस यात्रा में शामिल होने वालों के लिए आईआरसीटीसी ने भोपाल के अलावा जबलपुर व इंदौर के रेलवे स्टेशन के कार्यालय पर विशेष प्रबंध किए है. राज्य के बड़े हिस्से के लोग बड़ी संख्या में दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं. इसी को ध्यान में रखकर इस यात्रा को प्राथमिकता दी गई है. पर्यटन में दिलचस्पी रखने वालों को ध्यान में रखकर ही यह यात्रा शुरू की जा रही है.भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का मकसद संस्कृति और धार्मिक विरासत को देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच बढ़ावा देना है. ट्रेन में इकॉनमी और डीलक्स दोनों तरह की सुविधाएं हैं. भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए देश के कई ऐतिहासिक मंदिरों और तीर्थ स्थलों का दर्शन कराया जाता है.

भारत में घरेलू और धार्मिक पर्यटन छू रहा आसमान, टूरिज्म क्षेत्र में नई संभावनाएं

भारत के कोने-कोने में ऐसे कई रिलीजियस डेस्टिनेशन्स हैं, जिनके इतिहास की एक अलग ही कहानी है. यहां हर उम्र के लोगों के देखने और घूमने के लिए बहुत कुछ है. भारत में कुछ तीर्थ स्थल ऐसे भी हैं, जो विदेशों से आने वाले लोगों को भी अपनी ओर खींचते हैं. अगर आप या आपका परिवार धार्मिक स्थलों पर जाने को इच्छुक है तो यह सबसे अच्छा समय साबित हो सकता है. भारत में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं, जो प्रकृति की सुंदरता से घिरे हुए हैं और वहां जिंदगी में एक बार तो आपको जरूर जाना चाहिए. यहां हम भारत के 6 तीर्थ स्थलों की एक लिस्ट लेकर आए हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ जाने का प्लान बना सकते हैं.

1. वैष्णो देवी मंदिर

जम्मू और कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी का मंदिर भारत के सबसे ज्यादा पसंदीदा तीर्थ स्थलों में शामिल हैं. ये मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है. वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है. वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरों बाबा के मंदिर में भी दर्शन करना जरूरी माना जाता है. चढ़ाई के अलावा आप घोड़ा, खच्चर और पालकी का विकल्प भी चुन सकते हैं. वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से भीड़ जुटती है. कई विदेशी पर्यटक भी यहां दर्शन के लिए आते हैं. अगर आपने कभी वैष्णो देवी मंदिर का रुख नहीं किया है तो आप यहां दर्शन के लिए जाने का प्लान

2. जगन्नाथ मंदिर

ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है. ये मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है. जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल मंदिर से आयोजित होने वाली एक प्रसिद्ध यात्रा है. इसमें तीनों देवताओं (जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र) को शहर भर में एक रथ पर ले जाया जाता है.

3. स्वर्ण मंदिर

पंजाब के स्वर्ण मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता. हर कोई इसकी खूबसूरती से वाकिफ है. स्वर्ण मंदिर सिखों के लिए सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है. ये मंदिर दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. इस मंदिर को हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है. गोल्डन टेम्पल पंजाब के अमृतसर में स्थित है. आप कभी यहां आएं तो मंदिर की रसोई में सिखों द्वारा तैयार किए गए लंगर का स्वाद जरूर चखें.

4. सबरीमाला मंदिर

केरल का सबरीमाला मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है. हर साल 30 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं. यह केरल के सभी मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर है और केरल के हलचल भरे कोच्चि शहर के पास स्थित है. ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है.

ये है भगवान भोलेनाथ की विशाल प्रतिमाएं, दर्शन करने के लिए दुनियाभर से जाते हैं लोग

हिंदू धर्म में भगवान शिव प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं. ऐसे कई भक्त हैं जो भगवान शिव की पूजा में लीन रहते हैं. भक्तों के लिए भगवान शिव काफी पूजनीय माने गए हैं. ऐसे में अधिकतर लोग भगवान शिव के मंदिर और बड़े-बड़े शिवालयों का दर्शन करने जाते हैं.

अगर आप भी भारत में मौजूद भगवान शिव के विशाल प्रतिमाओं का दर्शन करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको उन सभी जगह के बारे में बताएंगे, जहां पर भगवान शिव की बड़ी-बड़ी प्रतिमाएं मौजूद है. आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में.

भगवान शिव की बड़ी-बड़ी प्रतिमाएं

अगर आप भी दुनिया भर में मौजूद विशाल शिव प्रतिमाओं का दर्शन करना चाहते हैं, तो भारत के राजस्थान राज्य के नाथद्वारा में 'विश्वास स्वरूपम' दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमाओं में से एक है. इस प्रतिमा का दर्शन करने के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं. जानकारी के मुताबिक यह प्रतिमा 369 फीट ऊंची और 51 बीघा की पहाड़ी पर मौजूद है.

आदियोगी शिव प्रतिमा

इसके अलावा तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित आदियोगी शिव प्रतिमा सभी विशाल शिव प्रतिमाओं में से एक है. जानकारी के मुताबिक इस सतगुरु जग्गी वासुदेव ने डिजाइन किया है और इसकी ऊंचाई 112 फिट है. यही नहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रतिमा स्टील की बनाई हुई है. आदियोगी कि इस शिव प्रतिमा का दर्शन करने लोग दूर-दूर से यहां आते हैं.

कर्नाटक में विशाल शिव प्रतिमा

दुनिया भर की विशाल शिव प्रतिमाओं में से एक शिव प्रतिमा कर्नाटक के मुरुंदेश्वर क्षेत्र में बनी हुई है. इस शिव प्रतिमा की ऊंचाई 123 फिट है. यह प्रतिमा कंडुक गिरी पर्वत पर बनी हुई है. यही नहीं अरब सागर के तट पर बनी यह शिव प्रतिमा वाकई में देखने लायक है. यहां विदेश से भी लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं.

हर की पौड़ी पर शिव प्रतिमा

उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्थित एक विशाल शिव प्रतिमा बनी हुई है. यह प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है, जिसकी ऊंचाई 100 फीट के करीब है. गंगा किनारे पर बनी इस शिव प्रतिमा का दर्शन करने यहां कई भक्त रोजाना आते हैं.

गुजरात में मौजुद है शिव प्रतिमा

इसके अलावा भारत के गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में 111 फीट ऊंचाई पर बनी शिव प्रतिमा पर सोने का लेप चढ़ाया गया है. जानकारी के मुताबिक यह एक खूबसूरत शिव प्रतिमा है, जिसे बनाने में 12 करोड़ के लगभग पैसे लगे हैं. भारत में मौजूद इन सभी विशाल प्रतिमाओं का दर्शन आप कर सकते हैं.

गूगल में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों के लिए है पेड इंटर्नशिप का मौका

12 से 14 हफ्ते की इंटर्नशिप के दौरान गूगल इंजीनियरिंग के युवाओं को वेतन भी देगा.

गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काम करना कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हर युवा का सपना होता है. अब ये मौका युवाओं के सामने है. गूगल ने जनवरी 2025 में शुरू होने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे हैं. खास बात ये है कि इस पेड इंटर्नशिप में युवाओं को 12 से 14 हफ्ते के दौरान गूगल पैसे भी देगा. आइये जानते हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में...

Career At Google: पीएचडी स्टूडेंट्स कर सकते हैं आवेदन

PhD स्टूडेंट्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में हैं, वो इसके लिए गूगल की वेबसाइट google.com/about/careers पर 28 फरवरी 2025 तक जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इंटर्नशिप के दौरान अभ्यर्थी को बेंगलुरु या हैदराबाद में काम करने का मौका मिलेगा. इस दौरान सभी को गूगल के चैलेंजिंग टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा.

Career At Google: मिलेगा इन जिम्मेदारियों को निभाने का मौका

गूगल में इंटर्नशिप के दौरान कई तरह की जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिल सकता है. इनमें अपनी टीम की प्राथमिकताएं तय करने के अलावा रणनीति को तैयार कर लागू करने और विभिन्न टीमों के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. हर इंटर्न की क्षमता का आंकलन कर उन्हें एक जिम्मेदारी दी जाएगी जिसे पूरा कर वह कंपनी के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग कर सकेंगे. लोगों से मिलकर फीडबैक और कोचिंग भी लेंगे. मिड टर्म टेक्निकल विजन को विकसित करने के साथ ही टीम को ध्यान में रखते हुए एक रोडमैप तैयार करेंगे.

Career At Google: ये न्यूनतम पात्रता पूरी करनी है जरूरी

आवेदन करने वाले के लिए बैचलर डिग्री या उसके बराबर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना आवश्यक है. इसके अलावा Python, C, C++, Java, JavaScript जैसे किसी एक या उससे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आठ साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हो या फिर लीडरशिप रोल में दो साल से तीन साल का एक्सपीरियंस, स्टेट ऑफ आर्ट जेन एआई टेक्नीक्स जैसे LLMs, Multi-Modal, Large Vision Models में पांच साल का एक्सपीरियंस या फिर model deployment, model evaluation, data processing, debugging, fine tuning जैसे एमएल इंफ्रास्ट्रक्चर का पांच साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है.

आपके पास भी है ये डिग्री तो पा सकते हैं 12 लाख की सरकारी नौकरी, कर दें अप्लाई

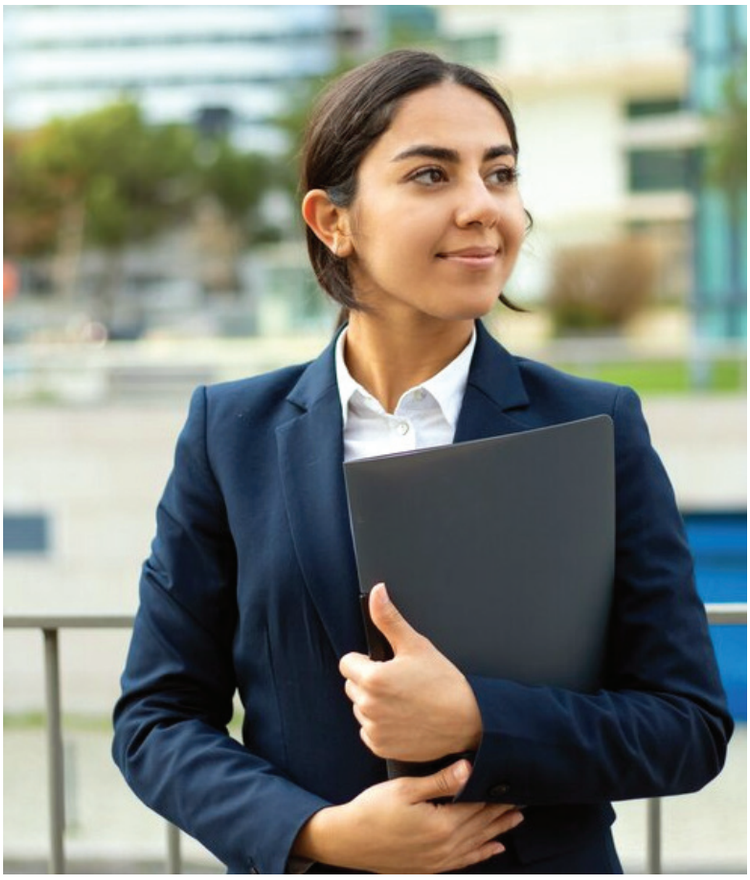

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 800 से अधिक पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन पदों के लिए आज आवेदन की लास्ट डेट थी, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था, उनके लिए सोने पर सुहागा यह है कि कॉर्पोरेशन ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब अभ्यर्थी 19 नवंबर तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

किन पदों पर वैकेंसी

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) में डिप्लोमा/असिस्टेंट/जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन पदों की कुल संख्या 802 है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है, जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है अप्लाई

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL)में निकली भर्तियों के लिए आवेदन करने उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा/इलेक्ट्रिकल पॉवर/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/पावर सिस्टम इंजीनियरिंग/पावर इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए. शर्त यह भी है कि आवेदकों के अंक 70 फीसदी से कम नहीं होने चाहिए. इसी तरह डिप्लोमा ट्रेनी सिविल डीटीसी के पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग में 70 प्रतिशत अंकों के डिप्लोमा अनिवार्य है. जूनियर ऑफिसर ट्रेनी JOT HR के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो 60 फीसदी अंकों के साथ बीबीए/बीबीएम/बीबीएससी पास हों. जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के लिए इंटर CA/इंटर CMA एग्जाम पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. असिस्टेंट ट्रेनी के पद के लिए बीकॉम की डिग्री होना अनिवार्य है. इन सभी पदों पर आवेदन करने वालों की अधिकतम उम्र 27 वर्ष होनी चाहिए. एसटी एससी वर्ग के उम्मीदवारों को आयुसीमा में 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी, वहीं विकलांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी.

कितनी मिलेगी सैलेरी

डीटीई, डीटीसी और जेओटी एचआर आदि पदों के लिए सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को 24000-3%-108000 का पे स्केल मिलेगा. कुल मिलाकर शुरूआत में सालाना पैकेज 11.9 लाख का होगा. इसी तरह असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का पे स्केल 21500-3%-74000 का होगा. इस पद के लिए सालाना पैकेज 10.3 लाख होगा.

कैसे होगा सेलेक्शन

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL)में निकली इन भर्तियों के लिए सेलेक्शन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा. सभी पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे. उस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों का फाइनल सेलेक्शन होगा.

गेल इंडिया लिमिटेड ने सीनियर इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, 11 दिसंबर तक करें आवेदन

गेल इंडिया लिमिटेड (Gail India Limited) ने सीनियर इंजीनियर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट gailonline.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर, 2024 है। अंतिम तिथि बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

गेल इंडिया लिमिटेड (Gail India Limited) की ओर से जारी सूचना के अनुसार, कुल 261 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें, सीनियर ऑफिसर के 130 और सीनियर इंजीनियर के 98 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वैकेंसी से जुड़ी अन्य डिटेल्स, जैसे भर्ती से जुड़ी अहम तारीखें, फीस और आवेदन करने का तरीका सहित अन्य डिटेल्स नीचे दी जा रही है।

गेल इंडिया लिमिटेड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत- 12 नवंबर, 2025

गेल इंडिया लिमिटेड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की

अंतिम तिथि - 11 दिसंबर, 2024

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले यूआर/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को 200 रुपये का शुल्क देना होगा। यह फीस नॉन-रिफंडेबल होगी। आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। बिना फीस सबमिट किए हुए कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही, एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही किया जाएगा। अभ्यर्थी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, वॉलेट और यूपीआई द्वारा फीस सबमिट कर सकते हैं।

सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट https://www.gailonline.com/CRApplyingGail पर जाना होगा। अब, आपको उम्मीदवार को पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें। विज्ञापन संख्या चुनें और फिर वह पद चुनें जिसके लिए आप उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं। आवेदन पत्र भरें, यहां पूछी गई डिटेल्स जैसे- व्यक्तिगत विवरण, योग्यता और अनुभव विवरण आदि एंटर करें। फीस का भुगतान करें (अगर लागू हो) फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार उसे अच्छी तरह से क्रास चेक कर लें। सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद फॉर्म सबमिट करें। अब भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए रख लें।

सीबीएसई ने की सिलेबस में कटौती, आंतरिक मूल्यांकन में होगा बदलाव

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आगामी 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 15% तक की कटौती की घोषणा की है. यह कदम छात्रों को गहन अध्ययन करने का अवसर देने और रटने की आदत को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है. इस महत्वपूर्ण घोषणा को इंदौर में आयोजित प्रिंसिपल समिट के दौरान बोर्ड के अधिकारियों ने साझा किया.

सिलेबस में 15% तक की कटौती

सीबीएसई के भोपाल क्षेत्रीय अधिकारी, विकास कुमार अग्रवाल ने बताया कि सिलेबस में की गई कटौती बोर्ड के नए शैक्षिक ढांचे के अनुरूप है. इसका उद्देश्य छात्रों को अत्यधिक विषय-वस्तु के बोझ से मुक्त करना है, ताकि वे अधिक प्रभावी तरीके से विषयों का गहन अध्ययन कर सकें. इस बदलाव के जरिए छात्रों को किताबों की सीमाओं से बाहर निकलकर विषयों के विभिन्न पहलुओं पर सोचने और समझने का अवसर मिलेगा.

आंतरिक मूल्यांकन में बढ़ोतरी

इस बार बोर्ड परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन का वेटेज 40% कर दिया गया है, जो अब छात्रों के अंतिम ग्रेड का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा. शेष 60% अंक परंपरागत रूप से अंतिम बोर्ड परीक्षा पर आधारित होंगे. आंतरिक मूल्यांकन में प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, और आवधिक परीक्षण शामिल होंगे. इससे छात्रों को निरंतर मूल्यांकन के जरिए अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का बेहतर मौका मिलेगा. विकास अग्रवाल ने कहा कि यह बदलाव छात्रों को उनकी वास्तविक समझ और कौशल को अधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित करने

कौशल आधारित प्रश्नों पर जोर

सीबीएसई अब अपनी परीक्षा प्रणाली में कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दे रहा है. 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्नपत्र का लगभग 50% हिस्सा सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों, समस्याओं और व्यावहारिक स्थितियों पर आधारित होगा. यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा देना है.एक्सपर्ट्स के अनुसार इन बदलावों से यह साफ है कि सीबीएसई शिक्षा प्रणाली में रटने की बजाय समझ और कौशल आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा दे रहा है, जिससे छात्र न केवल परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे, बल्कि वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना भी कर सकेंगे.

MPPSC ने घोषित की SET की डेट, इस तारीख से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (MP SET) 2024 की डेट जारी कर दी है. यह परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य में सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है. योग्य उम्मीदवार 6 दिसंबर 2024 से अपनी एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे.

MP SET Exam 2024: परीक्षा की डेट और डिटेल्स

MP SET 2024 परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी और इसके माध्यम से उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्र घोषित किया जाएगा. इस वर्ष की परीक्षा 36 विभिन्न विषयों में आयोजित की जाएगी.

MP SET Exam 2024: किस लिए होती है परीक्षा

MP SET परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें और समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. ये एग्जाम सहायक प्रोफेसर के पद के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों

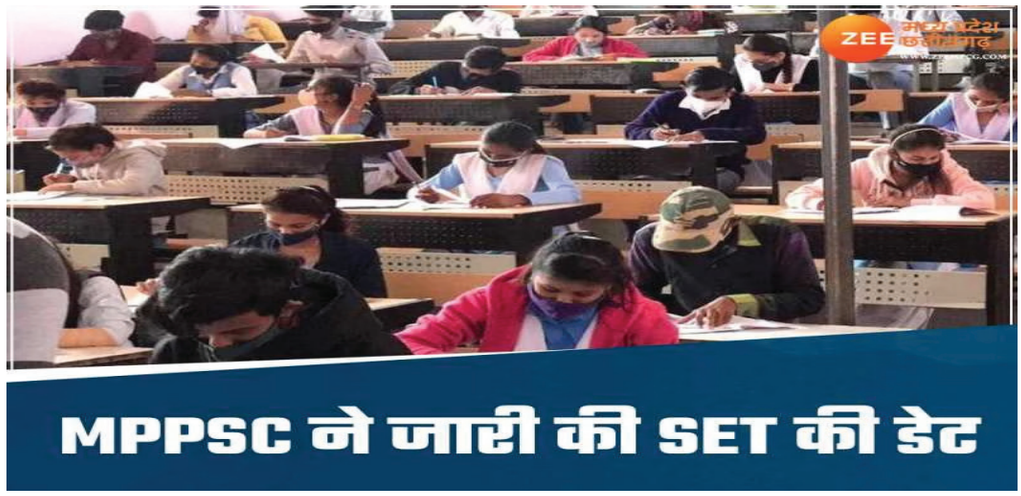

और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का मौका मिलता है.

MP SET Exam 2024: इस पैटर्न पर होगा एग्जाम

MP SET 2024 दो पेपरों में आयोजित किया जाएगा.

पेपर 1: सामान्य पेपर (शिक्षण और अनुसंधान योग्यता) – यह 1 घंटे का होगा और इसमें 100 अंक होंगे.पेपर 2: चयनित विषय – यह 2 घंटे का होगा और इसमें 200 अंक होंगे.इन दोनों पेपरों में उम्मीदवारों के शिक्षण के लिए आवश्यक योग्यता और उनके चयनित विषय की समझ का मूल्यांकन किया जाएगा.

ये है भारत की सबसे महंगी डिग्री, पाने के लिए खर्च करने पड़ते हैं करोड़ों रुपये

भारत में सबसे महंगी डिग्री की सूची में मेडिकल, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग क्षेत्र की पढ़ाई मानी जाती है. इन क्षेत्रों में लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं.

आम तौर पर लोग सबसे महंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या शहरों के बारे में बात करते हैं. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे महंगी डिग्री के बारे में. जिसे पाने के लिए किसी भी सामान्य व्यक्ति को करोड़ों खर्च करने पड़ सकते हैं. आइये जानते हैं इस सबसे महंगी डिग्री के बारे में...

सबसे महंगी है मेडिकल की पढ़ाई

भारत में सबसे महंगी पढ़ाई मेडिकल क्षेत्र की मानी जाती है. इसे महंगी डिग्री की लिस्ट में सबसे ऊपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सरकारी कॉलेज को छोड़ दें तो एमबीबीएस की डिग्री पाने के लिए ही करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. वहीं, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की फीस तो उससे भी ज्यादा होती है.

एमबीए में लग जाते हैं तीस से चालीस लाख

मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए की पढ़ाई को भी सबसे महंगी डिग्रियों की लिस्ट में शामिल किया जाता है. कारण, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए करने में कम से कम 20 से 40 लाख रुपये लग जाते हैं. वहीं, प्राइवेट कॉलेजों में इससे भी ज्यादा फीस चुकानी पड़ सकती है. इसमें अगर हॉस्टल व अन्य खर्च जोड़ दिए जाएं तो यह आंकड़ा पचास लाख को भी पार कर जाता है.

इंजीनियरिंग की डिग्री

इंजीनियरिंग भारत की सबसे ज्यादा डिमांड और ट्रेंड में रहने वाली डिग्रियों में से एक है। इंजीनियरिंग में तमाम ब्रांच होती है और इन ब्रांच के अनुसार ही फीस भी बढ़ती जाती है. मसलन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग करने में 20 से 40 लाख रुपये लग जाते हैं. जबकि कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग भी खासी महंगी है. हालांकि यह कॉलेज पर निर्भर करता है. इसके अलावा मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में भी लाखों का खर्च आता है.

इन कोर्सेज में भी खर्च कम नहीं

मेडिकल, मैनेजमेंट और तकनीक के क्षेत्र के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें डिग्री पाना आसान नहीं है. लॉ, बीफार्मा और होटल मैनेजमेंट जैसे तमाम कोर्स हैं, जिसे करने में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं.

मिस्टर इंडिया हैं स्विगी के सीईओ! किसी-किसी को ही आते हैं नजर

स्विगी के IPO लिस्टिंग पर CEO श्रीहर्ष माजेटी ने सबको चौंकाते हुए कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई. उन्होंने स्विगी के सफर को "चमत्कार" बताते हुए बताया कि यह विचार उन्हें IIM कोलकाता में एक प्रोजेक्ट के दौरान आया था. उन्होंने कंपनी की सफलता का श्रेय नेतृत्व दल को दिया.

नई दिल्ली. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर स्विगी के IPO लिस्टिंग के अवसर पर कंपनी के CEO श्रीहर्ष माजेटी ने पहुंचकर सभी को चौंका दिया. माजेटी, आमतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहते हैं. इस खास मौके पर स्विगी की लीडरशिप टीम और डिलीवरी पार्टनर्स के साथ मंच साझा किया. उनके साथ डिलीवरी पार्टनर्स जिगर खान और नम्रता भी उपस्थित थे. माजेटी की यह उपस्थिति स्विगी के सफर में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में दर्ज हो गई है.

लिस्टिंग समारोह में माजेटी ने स्विगी की शुरुआत के बारे में बताते हुए कंपनी की यात्रा को "चमत्कार" करार दिया. उन्होंने कहा कि स्विगी का विचार सबसे पहले उन्हें इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोलकाता में एक कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान आया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस विचार को भुला दिया था. कुछ समय बाद उन्होंने उसी विचार को नए रूप में फिर से अपनाया, जो आज एक विशाल कंपनी का रूप ले चुकी है. माजेटी ने स्विगी की सफलता का श्रेय अपने नेतृत्व दल को दिया और उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि कंपनी को मौजूदा मुकाम तक पहुंचाने में टीम के सामूहिक प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

स्विगी का यह आईपीओ ऐसे समय में आया है जब भारत में डिलीवरी सेक्टर में तीव्र प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. स्विगी अब सीधे Zomato और Zepto जैसे प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला कर रही है. Zomato के CEO दीपिंदर गोयल जहां सोशल मीडिया और सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, वहीं माजेटी आमतौर पर सार्वजनिकता से दूर रहते हैं.इसके अलावा, स्विगी के IPO के साथ एक बड़ा Employee Stock Option Plan (ESOP) भी घोषित किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है. इस ESOP योजना के तहत कंपनी के लगभग 500 कर्मचारियों को करोड़पति बनने का अवसर मिलेगा. यह योजना भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक नई मिसाल पेश करती है, जहां कर्मचारियों को इतने बड़े पैमाने पर लाभ कमाने का मौका मिलना दुर्लभ है. इस आईपीओ के माध्यम से स्विगी ने अपने लंबे समय से साथ दे रहे कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और आभार प्रकट किया है, जो कंपनी की इस शानदार यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहे हैं.

कक्षा-6 से 8 तक के स्कूलों में माह में कम से कम एक शनिवार को होगा बैगलेस-डे

बैगलेस-डे में विभिन्न गतिविधियों के साथ बच्चों का बढ़ाया जायेगा कौशल

प्रदेश में कक्षा-6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों का समग्र विकास हो, इसके लिये बैगलेस-डे के दिन बच्चों को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने का निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है। इस दिन बच्चों के बीच पढ़ाई के अलावा विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं व्यावहारिक गतिविधियाँ की जायेंगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला शिक्षाधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी किये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में यह प्रावधान रखा गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 21वीं सदी के कौशल से परिचित हो सकें, इसके लिये कक्षा-6 से 8 तक के स्कूल के बच्चों के लिये प्रत्येक माह में न्यूनतम एक शनिवार को बस्ते-विहीन दिवस का आयोजन हो। इन दिवसों में विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल की जानकारी दी जाये।

बैगलेस-डे के लिये शाला के प्राचार्य एवं शिक्षकों को चर्चा कर गतिविधियों का कैलेण्डर तैयार करने के लिये भी कहा गया है। गतिविधियों की जानकारी "एचडी जिओ टैगी फोटोग्रॉफ" राज्य शिक्षा केन्द्र के ई-मेल आईडी rsk.curriculum@gmail.com पर भेजने के लिये कहा गया है। बैगलेस-डे का उद्देश्य विद्यार्थियों को सफल, नवाचारी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना है। इसी के साथ विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साक्ष्य आधारित सोच और रचनात्मकता का विकास करना है। विद्यार्थियों में संवाद, विचार अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य एवं पोषण, खेल सहयोग की भावना एवं नेतृत्व गुण के साथ भारतीय ज्ञान परम्परा और पर्यावरणीय चेतना का विकास करना प्रमुख है।

बैगलेस-डे में होने वाली गतिविधियाँ

राज्य शिक्षा केन्द्र ने बैगलेस-डे में होने वाली गतिविधियों के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ऑर्ट और क्रॉफ्ट में बच्चों के बीच में ड्राइंग, पेंटिंग, मिट्टी के खिलौनों का निर्माण, मुखौटे, डॉल-मेकिंग और अनुपयोगी सामग्री से वस्तुओं का निर्माण प्रमुख है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में बच्चों के बीच लोकगीत-नृत्य, लघु नाटिका, कविता पाठ, कहानी लेखन गतिविधियाँ की जायें। बच्चों को खेती की आधुनिक पद्धतियों की जानकारी हो सके, इसके लिये पॉलीफॉर्मिंग, ऑर्गेनिक फॉर्मिंग, औषधीय पौधों की जानकारियाँ और खेती में उपयोग होने वाले आधुनिक उपकरणों की जानकारी दी जाये। साथ ही स्थल भ्रमण भी कराया जाये। बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों, लघु उद्योग व्यवसाय, जिनमें मधुमक्खी-पालन, मुर्गी एवं मछली-पालन इत्यादि की जानकारी दी जाये। बच्चों को स्थानीय बैंक, पुलिस थाना, अस्पताल और अनाज मण्डी का भ्रमण कराया जाये। बच्चों को हथकरघा, खिलौने निर्माण जैसी इकाइयों का भ्रमण कराया जाये। इसी के साथ बच्चों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की जानकारी देने के साथ खेल गतिविधियाँ भी करायी जायें।

वास्तु अनुसार घर पर लगाएं ये पौधे, नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर और पॉल्यूशन भी होगा कम

पेड़-पौधों का संबंध प्रकृति और शुद्ध वातावरण से है. इसी के साथ कुछ पेड़-पौधे ऐसे भी होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ाते हैं और अच्छी स्वास्थ्य, धन और समृद्धि से भी जुड़े होते हैं. वास्तु शास्त्र में ऐसे ही पौधों के बारे में बतलाया गया है जो आपके घर की हवा को शुद्ध करने के साथ ही कई लाभ भी प्रदान करते हैं.

इस समय बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अगर आप भी अपने घर का माहौल सकारात्मक और शुद्ध बनाना चाहते हैं तो आज ही इन्हें अपने घर पर लगाएं और शुद्ध हवा का आनंद ले. आइये जानते हैं इन पौधों के बारे में.

मनी प्लांट (Money Plant)-

मनी प्लांट का पौधा दिखने में खूबसूरत होता है. इसलिए ज्यादातर घरों में इसे लगाया जाता है. यह पौधा आसानी में मिट्टी या केवल पानी में भी लग जाता है. मनी प्लांट का संबंध शुक्र ग्रह से होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार यह पौधा घर की सुख-समृद्धि को बढ़ाता है. वहीं मनी प्लांट से ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे पॉल्यूशन कम होता है.

तुलसी (Tulsi)-

तुलसी के पौधे को वास्तु शास्त्र और हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. साथ ही इसमें आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं. बढ़ते पॉल्यूशन के कारण यदि गले में खराश या कफ आदि की समस्या में तुलसी पत्ते का सेवन अच्छा होता है. भाग्य, स्वास्थ्य और सेहत के लिए तुलसी का पौधा लाभकारी और गुणकारी होता है. आप इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं.

स्नेक प्लांट (Snake Plant):

स्नेक प्लांट की खासियत है कि यह पौधा रात के समय भी आक्सीजन देता हैं. साथ ही यह फार्मल्डिहाइड, जाइलीन, ट्राईक्लोरोएथिलिन, बेनजेन और ट्रिक्लोरो जैसे हानिकारक गैस को सोख कर वातावरण को शुद्ध करता है. वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण, पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा में स्नैक प्लांट लगाना शुभ होता है.

बैम्बू (Bamboo Plant)-

बैम्बू या बांस का पौधा भी वातावरण को शुद्ध करता है. इसे अच्छा वायु शोधक माना जाता है. क्योंकि अन्य पौधों की अपेक्षा यह 30 प्रतिशत अधिक ऑक्सीजन देता है और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे पूर्व दिशा की ओर लगाने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है.

मुँह और दाँतों के महत्व

मुँह और दाँतों के लिए आवश्यक खनिज तत्व और विटामिन्स के बारे में बताने वाला यह लेख आपको मुँह और दाँतों के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

Dr. हिमांशु मल्ल

मुँह और दाँतों के लिए आवश्यक खनिज तत्व और विटामिन्स के बारे में बताने वाला यह लेख आपको मुँह और दाँतों के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

मुँह और दाँतों के महत्व

मुँह और दाँतों का स्वास्थ्य सम्पूर्ण शारीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक स्वस्थ मुँह और दाँतें अच्छे खाने पचाने में सहायक होते हैं और साथ ही एक अच्छे चेहरे का भी संकेत होते हैं। इसके लिए उचित खनिज तत्वों और विटामिन्स का सेवन अत्यंत आवश्यक होता है।

मुँह और दाँतों के लिए समग्र पोषण

मुँह और दाँतों के स्वास्थ्य के लिए समग्र पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ और उचित आहार से विभिन्न खनिज तत्वों और विटामिन्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत आवश्यक है। नियमित दंत चिकित्साएँ, उचित मुँह संवेदनशीलता की देखभाल, और स्वस्थ आदतें भी दाँतों के लिए अत्यंत जरुरी हैं।

इस लेख से हम यह समझ सकते हैं कि अपने दाँतों और मुँह की देखभाल में उचित आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपरोक्त खनिज तत्वों और विटामिन्स के सेवन से हम अपने दाँतों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रख सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की मुँह की समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए, अपने खानपान में इन आवश्यक तत्वों को शामिल करना स्वास्थ्यपूर्ण और सुरक्षित जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम□हो सकता है।

दाँतों के लिए अन्य आवश्यक खनिज तत्व

1. **कैल्शियम**: यह दाँतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, जो उनकी मजबूती और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम के बिना दाँतों का ढीलापन हो सकता है और उनमें कैविटी भी हो सकती है। दूध, दही, पनीर, मसूर, बादाम, और तिल जैसे आहार में कैल्शियम पाया जाता है।

2. **फ्लोराइड**: यह भी दाँतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दाँतों को कैरीएस (caries) से बचाने में मदद करता है। फ्लोराइड विशेष रुप से पानी में पाया जाता है और कई दाँतों की मानक सेवा में जोड़ा जाता है।

3. **फॉस्फेट**: यह भी दाँतों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यह उनकी मजबूती बनाए रखने में मदद करता है। फॉस्फेट दूध, दही, मीट, मछली, अंडे, और अनाजों में पाया जाता है।

4. **मैग्नीशियम**: यह दाँतों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कैल्शियम को अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है। अधिकांश मैग्नीशियम हरे सब्जियों, दाल, दाने, और अंडे में पाया जाता है।

5. **फ्लोराइड**: जैसे कि पहले उल्लिखित, यह दाँतों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कैरीएस को रोकता है और दाँतों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

कहीं आपका प्यार आपको इमोशनली डैमेज तो नहीं कर रहा?

सच ही तो है, जब अपनों से ही दर्द मिले, तो इसकी सुनवाई आख़िर कोई करे, तो कहां करे? प्यार एक ख़ूबसूरत एहसास है, लेकिन जब यही प्यार भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने लगे, तो इमोशनली डैमेज होते देर नहीं लगती.

जी हां, अब ऐसा अक्सर ही देखने को मिल रहा है कि प्यार भरे रिश्ते में इमोशंस कम और इमोशनल अत्याचार अधिक होने लगा है. प्यार व रिश्तों को लेकर हाल ही में हुए एक सर्वे में यह बात खुलकर सामने आई कि अब प्यार में जुड़ाव कम और शोषण अधिक पैठ जमाने लगे हैं.

अब वो प्यार न रहा रिंकी और सुमेश में बेइंतहा प्यार था और दोनों ने लव मैरिज की थी. लेकिन धीरे-धीरे रिंकी को यह एहसास होने लगा कि सुमेश की नज़रों में उसकी एहमियत दिन-ब-दिन कम होती जा रही है. अब वो उसे पहले जैसा न ही प्यार करता है और न ही समय देता है.

ऑफिस से आने के बाद प्यार भरी दो बातें करने की बजाय सुमेश अपनी ऑफिस की सारी भड़ास पत्नी पर उड़ेल देता है. अब वो उसके लिए स्ट्रेस रिलीज़ करने का सॉफ्ट टार्गेट बन गई थी.

पहले रिंकी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी. लेकिन जल्द ही उसे महसूस होने लगा कि यह तो सुमेश की रोज़ की आदत बन गई है. अपनी कमियों, असफलताओं और तनाव को उस पर निकालकर कहीं न कहीं वो ख़ुद तो रिलैक्स हो जाता है, पर उसे इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है. एकबारगी देखें, तो धीरे-धीरे भावनाओं का यही खिलवाड़ रिश्तों में दूरियों की वजह बन जाता है.

कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा? आपका पार्टनर फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला आपके साथ ऐसा तो नहीं कर रहे?

डॉ. माधवी सेठ, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और आए दिन इस तरह के केसेस की काउंसलिंग करती रहती हैं, का कहना है कि कपल्स को इमोशनली डैमेज होने से ख़ुद को बचाना बेहद ज़रूरी है और यह उसकी ज़िम्मेदारी भी है.

अक्सर देखा जाता है कि पत्नी कहती है कि मुझे यहां पहुंचा दो, मैं वहां अकेली नहीं जा सकती या फिर तुम्हारे बगैर यह काम तो मैं कर ही नहीं सकती अब बेचारे पति को न चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है, भले ही वो दिल से न चाहता हो, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग के कारण उसे पत्नी का साथ देना ही पड़ता है. यह हुआ इमोशनली डैमेज करने का दूसरा पहलू. इसमें कई तरह के नुक़सान साथी को झेलने पड़ते हैं, जैसे- जीवनसाथी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचना, उसे उचित मान-सम्मान न मिलना, मानसिक रूप से आहत होना, दबाव महसूस करना, कभी-कभी घुटन, टेंशन और डिप्रेशन भी पैर जमाने लगते हैं.

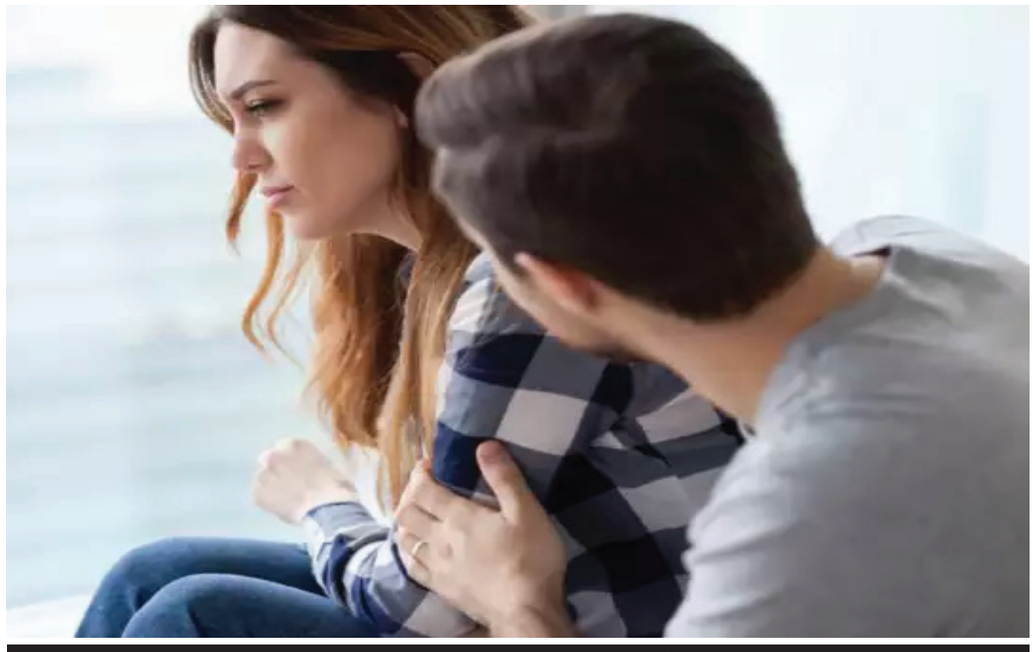

इमोशनल अलर्ट

1. हर वक़्त ज़रुरत से ज़्यादा भावनाओं में न बहें.
2. पार्टनर के इमोशंस के साथ-साथ अपने इमोशंस को भी महत्व दें.
3. रिश्तों में होने वाले मेंटल टॉर्चर यानी इमोशनल डंपिंग से बचे.
4. ताने मारना, कोसना, बार-बार बेमतलब ग़लत ठहराना जैसे इमोशनल अत्याचार को बढ़ावा न दें. इसी से रिश्तों में भावनात्मक शोषण की शुरुआत होती है.
5. एक-दूसरे की बातों को अनदेखा न करें, बल्कि तवज्जो दें.
6. केवल अपनी ही बातें न मनवाते रहें, साथी की आपबीती को जानने में भी दिलचस्पी दिखाएं.
7. छोटी-छोटी बातों पर ईगो के कारण लड़ाई-झगड़े न करें. इससे इमोशनली डैमेज होने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता. क्यों न कुछ तुम कहो, कुछ हम सुनें, कुछ तुम झुको कुछ हम संभलें... वाला फॉर्मूला अपनाएं.
8. जज़्बात को नियंत्रण में रखने के लिए योग-प्राणायाम, मेडिटेशन करें.

भावनाओं के बगैर ज़िंदगी बेमानी है

डॉ. माधवी कहती हैं कि ज़िंदगी में इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी बेमानी है. हम सभी को कोई न कोई इमोशन तो होता ही है. रोमांस भी एक तरह का इमोशन ही है. लेकिन कोई भी चीज़ जब अपनी सीमा के बाहर यानी हद के बाहर चली जाए, तो ग़लत ही है. इससे प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं, फिर चाहे वो इमोशंस ही क्यों न हों.

इमोशनल फूल

इमोशनली डैमेज होने का एक उदाहरण कुछ ऐसा भी. साक्षी और विनोद का एक-दूसरे से गहरा जुड़ाव और दोस्ती थी. जब विनोद ने वैलेंटाइन पर साक्षी को प्रपोज़ किया, तो वो हैरान रह गई. गुलाबी शाम, प्यार भरी धुन के साथ फिल्मी अंदाज़ में प्रपोज़ करना सब कुछ इतना ख़ूबसूरत और रोमांटिक था कि भावनाओं में बहकर रोमांचित होते हुए साक्षी ने हां कह दी. एक के बाद एक घटनाएं तेज़ी से होती गईं. तब बिना कुछ सोचे-समझे इमोशंस के उस बहाव में वह बहती चली गई. लेकिन शादी होने पर काफ़ी समय बाद यह एहसास हुआ कि फ़ैसला लेने में जल्दबाज़ी हो गई. माना अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ज़िंदगीभर का साथ निभाने के लिए कुछ रुकना और जानना-समझना भी बहुत ज़रूरी था. अब विनोद द्वारा बात-बात पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, अपनी बात ज़बर्दस्ती मनवाना, इमोशनली ब्लैकमेल करना साक्षी को यह एहसास कराता है कि वो कितनी इमोशनल फूल थी. यदि उस समय थोड़ा संभल जाती या रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले रिश्ते को थोड़ा समय देती, तो शायद उसकी ज़िंदगी कुछ और होती. साक्षी वाली ग़लतियां कई लड़कियां करती हैं. वो भावनाओं में बहकर ग़लत फ़ैसले कर लेती हैं.

इमोशंस को मिसयूज़ न करें

जब हमारी भावनाएं अपने चरम पर होती हैं, तब अमूमन हम ग़लत निर्णय ले लेते हैं. इसलिए इमोशंस को सही तरीक़े से यूज़ करना ज़रूरी है. उस पर लगाम लगाना ज़रूरी है और यह बहुत कुछ हम पर निर्भर करता है. इमोशंस यूज़ करें, पर मिसयूज़ कभी न करें.

ख़ामोशी भी ख़तरनाक

कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिन्हें कोई इमोशन ही नहीं होता. प्रायः आपने किसी न किसी को यह कहते हुए सुना होगा कि अरे भई इसे तो कोई इमोशन ही नहीं है. ये भावनाओं को व्यक्त ही नहीं करते. यह भी ठीक नहीं है. इस तरह के शख़्स अलग तरीक़े से भावनात्मक रूप से आहत करते हैं. कभी-कभी इनकी ख़ामोशी ही इनका मेंटल टॉर्चर करने का हथियार बन जाता है.

इमोशनल डंपिंग से बचें

जब जीवनसाथी बेवजह ग़ुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, मारपीट करते हैं, तब उनके इस तरह के व्यवहार को एक्सपर्ट्स इमोशनल डंपिंग का नाम देते हैं. कई बार इसके कारण ही रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और रिश्ते टूटते भी हैं. इसलिए जब कभी इस तरह की बातें लगातार होते हुए देखें, तो पार्टनर के शांत होने पर उनसे इसके बारे में बात करें. उन्हें प्यार से समझाएं. ज़रूरत होने पर मैरिज काउंसलर, मनोचिकित्सक व मनोवैज्ञानिक की भी मदद ली जा सकती है. कई बार काउंसलिंग से भी रिश्ते संभल जाते हैं. ध्यान रहे, रिश्तों की मज़बूती एक-दूसरे को समझने में है, न कि दुखी करने में.

कुछ इमोशनल डैमेज ऐसे भी

टीनएज में ही राज पढ़ने के लिए विदेश चला गया था. जब दस साल बाद वापस लौटा, तब उसकी बड़ी इच्छा हुई अपनी नैनि से मिलने की, जिन्होंने बचपन से टीनएज तक उसकी अच्छी तरह से देखभाल की थी. बड़े उत्साह से वो उन्हें मिलने गया. लेकिन नैनि राज से उस गर्मजोशी से नहीं मिलीं, जिसकी अपेक्षा उसने की थी. उनके उदासीन व्यवहार ने उसे इमोशनली इस कदर हर्ट किया कि उससे उबरने में लंबा समय लग गया. कहां राज ने सोचा था कि नैनि आंटी उसे देखकर ख़ुशी से झूम उठेंगी.कहेंगी- कितना लंबा और बड़ा हो गया है स्नेह-दुलार करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी न होने पर राज का दिल टूट ही गया. इस तरह के इमोशनल डैमेज से उबरने में वक़्त लगता है.क्या आप जानते हैं कि हमारे मन में तक़रीबन सौ से अधिक इमोशंस होते हैं, जिनमें से बहुत कम का ही हम इस्तेमाल करते हैं. मैं ग़ुस्सा हूं या फिर आज मैं बहुत ख़ुश हूं।

वेट लॉस कर रहे हैं, तो खाएं ये हेल्दी स्नैक्स

अगर आप वेट लॉस डायट फॉलो कर रहे हैं, तो अपनी डायट में ऐसे हेल्दी स्नैक्स शामिल करें, जो वजन घटाने में आपकी मदद करें. यहां बताए गए इन स्नैक्स को अपने वेट लॉस डायट कर सकते हैं

1 बेक्ड/बॉयल्ड स्वीट पोटैटोः

वेट लॉस कर रहे हैं, तो अपनी डायट में शकरकंध को शामिल करें. इसमें बीटा कैरोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता हैं और इसे बेक्ड या उबाल कर खाने से अधिक समय तक भूख नहीं लगती है

2. स्प्राउट्स वेजिटेबल सलादः

पौष्टिकता से भरपूर इस सलाद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और खाने पर संतुष्टि का एहसास होता है.

3. मिक्स नट्सः

सामान मात्रा में काजू-बादाम-अखरोट-अंजीर-मुनक्का खाने से भूख की क्रेविंग शांत होती है और जल्दी भूख भी नहीं लगती है. वजन घटाने के दौरान मिक्स नट्स शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

4. अंडे का सफ़ेद वाला भागः

अंडे की सफेदी में प्रोटीन बहुत अधिक होता है. वेट लॉस के दौरान 2-3 अंडे का सफ़ेद वाला भाग खाने से पेट काफी समय तक भरा रहता है. इसे स्नैक्स के तौर पर किसी भी वक्त खाया जा सकता है.

5. दहीः

गुड प्रोबायोटिक होने के कारंण पेट संबधी सभी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है. कैल्शियम और प्रोटीन युक्त कम फैट वाला दही वजन कम करने में सहायक होता है, इसलिए डाइट में इस हेल्दी स्नैक्स को शामिल करें.

6. मिक्स सीडः

मगज़, काले और सफ़ेद तिल, सनफ्लॉवर सीड, अलसी के बीज हेल्दी स्नैक्स है. इनमें फाइबर, विटामिन ई, फैटी एसिड, मैग्नीशियम और जिंक होते हैं, जो भूख को शांत करते हैं.

7. मखानाः खाने में स्वादिष्ट मखाने को वेट लॉस के लिए सबसे बेहतरीन स्नैक्स माना गया है. ग्लूटिन फ्री और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से युक्त मखाना पॉपकॉर्न जैसा क्रंची अहसास देता है.

8. भुना हुआ चनाः प्रोटीन और फाइबर का प्रमुख स्त्रोत होने के साथ-साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे हेल्दी स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं. वेट लॉस के लिए यह परफेक्ट ऑप्शन है. इससे न सिर्फ भूख मिटती है, खाने के बाद काफी देर तक पेट भरा रहता है.

9. मूंगफलीः स्नैक के तौर पर मूंगफली भी खा सकते हैं, इसमें पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, आयरन और सेलेनियम काफी मात्रा में होता है. आप इसे शाम या सुबह किसी भी वक्त खा सकती हैं.

कब खाएं?	क्या खाएं?	क्यों खाएं?
नाश्ता	ओट्स या पोहा और ग्रीन टी	यह एक संतुलित आहार है, जो फाइबर से भरपूर है। ग्रीन टी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं।
दोपहर का भोजन	ब्राउन राइस/रोटी, दाल और सब्जियां, और सलाद।	यह प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्त्रोत है।
शाम का नाश्ता	ग्रीन टी और फल	यह दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं और ताजगी भी प्रदान करते हैं।
रात का भोजन	ग्रिल्ड पनीर या चिकन, सब्जियां और सलाद।	यह हाई प्रोटीन डाइट है। इसके सेवन से शरीर की

मोटापा से बचने के लिए किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए?

मोटापा से बचने के लिए डाइट के साथ कुछ चीजों से बचने की सलाह हमेशा ही दी जाती है जैसे कि –

कोल्ड ड्रिंक और जूस में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसको पीने से वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। समोसे और पकौड़े जैसे तले हुए भोजन से दूरी बनाएं क्योंकि इससे भी वजन बढ़ने की संभावना लगातार बनी रहती है।

पैक्ड फूड जैसे कि बिस्कुट और चिप्स को लंबे समय तक रखने के लिए इनमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जो वजन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। फास्ट फूड जैसे कि बर्गर और पिज़्ज़ा में सोडियम और अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिसके कारण वजन बढ़ता है।

वजन घटाने वाले कौन-कौन से व्यायाम और योग करना चाहिए

वजन घटाने के लिए सही डाइट के साथ-साथ व्यायाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप रोजाना ऊपर बताए गए डाइट का पालन करते हैं, तो नीचे बताए गए व्यायाम और योग को अपनी जीवनशैली में जोड़ने से आपको बहुत लाभ मिलेगा –

कार्डियो एक्सरसाइज, वॉल्किंग,सूर्य नमस्कार बोट पोज़,प्लैंक पोज़,साइकिल चलाना

स्विमिंग ,वीरभद्रासन,त्रिकोणासन , वजन घटाने के लिए कुछ कारगर उपाय,नीचे दिए गए उपायों की मदद से वजन को आसानी से कम किया जा सकता है – दिन में कम से कम 4-5 लीटर पानी पीएं। हर कुछ समय में कुछ हल्का-फुल्का खाना खाएं।सोने से पहले कुछ भी खाने से बचें।तनाव कम करें और मेडिटेशन और योगासन करें। वजन कम करने के लिए डाइट्स वजन कम करने के लिए डाइट के विभिन्न चार्ट पहले से ही मौजूद है, जिनको आप भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि –

केटो डाइटः वर्तमान में कुछ सेलिब्रिटी इस प्रकार के डाइट का पालन करती हैं जिसमें कम कार्बोहाइड्रेट और अधिक प्रोटीन एवं फैट का सेवन किया जाता है।

लो कार्ब डाइटः अधिकतर जिम वाले लोग इस प्रकार के डाइट का पालन करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है।

सर्दियों में अमृत है ये छोटा सा खट्टा फल, आंखों की रोशनी करेगा तेज, घटाएगा पेट की चर्बी ! वो भी चंद दिनों में

आंवला सर्दी के मौसम में लोग बड़े पैमाने पर खाते हैं. आंवला, जो गुणों का खजाना है, को 'अमृत फल' कहा जाता है क्योंकि आंवला शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है. ये सेहत और सुंदरता दोनों को बढ़ाने में मदद करता है. इसके अलावा, आंवला आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत फायदेमंद है. तो आज हम जानेंगे आंवला खाने के फायदे और इसके आयुर्वेदिक लाभ.

आंवला आयुर्वेद में बहुत फायदेमंद है

इस बारे में दर्शन पटेल ने कहा कि आयुर्वेद में आंवला को 'आमलकी' कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अमृततुल्य. आयुर्वेदिक महर्षियों ने आंवला के बारे में कहा था कि 'आमलकी व्याय प्रथनाम', यानी आंवला उम्र को कायम रखता है और बुढ़ापे को दूर रखता है, युवावस्था को बनाए रखते हुए. आंवला में एक ऐसा पोषक तत्व होता है जिसे रोजाना खाया जा सकता है. यह तीखा होता है, जिसमें मुख्य रूप से आमलरस और खट्टा रस होता है. हालांकि, आंवला का स्वाद खट्टा होता है, यह पित्त को बढ़ाने की बजाय सभी तीन दोषों को संतुलित करता है. इसके अलावा, आंवला का ठंडक प्रभाव गैस और अम्लता की समस्या से परेशान लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है.

चेहरे पर मुंहासे हटाने में उपयोगी

उन्होंने आगे कहा कि आंवला में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जो इम्यूनिटी और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है. इसके अलावा, आंवला पाउडर का उपयोग उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो मुंहासों से परेशान हैं. त्वचा के साथ-साथ आंवला बालों से जुड़ी समस्याओं जैसे बालों का झड़ना, सफेद बाल, डैंड्रफ आदि के लिए भी बहुत उपयोगी है. आंवला की खासियत यह है कि यह सूरज की रोशनी या जलने पर अपने पोषक तत्वों को खोता नहीं है. इसके अलावा, यह आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. जो लोग चश्मा पहनते हैं, आंवला खाने से उनकी नजर में वृद्धि होती है.

आंवला डायबिटीज को भी ठीक करता है

दर्शन पटेल ने आगे बताया कि आंवला डायबिटीज को भी ठीक करता है. खासकर प्री-डायबिटिक कंडीशन को आंवला, हल्दी और शहद मिलाकर लिया जाए तो वह ठीक हो जाती है. इसके अलावा, यह डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स जैसे हाथ-पैर जलना, किडनी की समस्याएं भी ठीक करने में मदद करता है. आंवला में इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटीऑक्सीडेंट जैसी गुण होते हैं. इसके अलावा, आंवला आयरन, कैल्शियम, फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. आंवला का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है जैसे आंवला जूस, फर्मेंटेड आंवला, च्यवनप्राश, आंवला कैंडी, आंवला सिरप, माउथवाश, मर्मलेड आदि बनाकर.

कच्चे और सूखे आंवले का सेवन भी फायदेमंद है

महत्वपूर्ण बात यह है कि आंवला उम्र बढ़ने से रोकता है. इसके अलावा, यह दांतों को मजबूत करता है, आंखों में चमक लाता है और शरीर में शुक्राणु वृद्धि को बढ़ाता है. हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, नपुंसकता, मर्दानगी, मसल्स डिजीज, त्वचा रोग, लीवर और किडनी की समस्या, रक्त रोग, टीबी, मूत्र रोग और हड्डियों की समस्या में विशेष रूप से मदद करता है. वजन घटाने के लिए, डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आंवला को सुखाकर धूप में खाया जाए, तो यह कई बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है. इसके अन्य फायदे नीचे बताए गए हैं.

1. **इम्यूनिटी बढ़ेगी:** सूखा आंवला विटामिन C से भरपूर होता है, जो संक्रमण से बचाव में मदद करता है. कोरोना वायरस महामारी के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया था. तो बदलते मौसम में सूखा आंवला हमें कई बीमारियों से बचा सकता है.

2. **पाचन शक्ति सुधरेगी:** हम अक्सर तैलीय और मसालेदार चीजें (Oily and spicy foods) ज्यादा खाते हैं, जिससे हमें गैस, एसिडिटी, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं होती हैं. ऐसे में, अगर आप सूखा आंवला पानी में उबालकर खाते हैं, तो सभी पेट की समस्याएं दूर हो जाती हैं.

3. **नजर सुधरेगी:** आंवला में विटामिन A और C भरपूर होते हैं, जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद हैं. यह दृष्टि सुधारने और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्याओं के खतरे को कम करने में मदद करता है.

4. **बदबूदार सांस से छुटकारा:** कभी-कभी सांसों की बदबू दांतों और मुंह की सफाई ठीक से न करने के कारण होती है. ऐसी स्थिति में आप सूखा आंवला चबा सकते हैं, जो एक प्राकृतिक माउथफ्रेशनर की तरह काम करता है.

हृदय संबंधी समस्याओं से राहत आंवले का पाउडर हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है।

नए साल में मिलेगी सौगात, खत्म हो सकती है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21-22 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक होगी जिसमें जीएसटी काउंसिल और बजट को लेकर चर्चा की जाएगी.

नए साल 2025 में लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) और हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की सौगात मिल सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 21-22 दिसंबर 2024 को राजस्थान में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है.

दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में एक दिन वित्त मंत्री, वित्त वर्ष 2025-26 से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों से बजट को लेकर उनके सुझाव और सिफारिशें लेंगी और एक दिन जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होगी जिसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया जा सकता है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) आने वाली बैठक में टर्म इंश्योरेंस प्लान पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को पूरी तरह खत्म करने पर मुहर लग सकती है. वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए और अन्य लोग जो 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं उसपर जीएसटी को खत्म किया जा सकता है. पीटीआई ने एक अधिकारी से हवाले से बताया कि जीएसटी काउंसिल कुछ प्रोडेक्ट्स सर्विसेज पर जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के साथ कुछ आईटम्स पर जीएसटी रेट्स को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर सकता है.हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी पर विचार करने के लिए जो मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है उसमें टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने और सीनियर सिटीजंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी से मुक्त करने पर सहमति बन गई है. इसके अलावा इंडीविजुअल्स की ओर से 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर प्रीमियम के भुगतान पर जीएसटी को खत्म करने का भी प्रस्ताव है. हालांकि 5 लाख रुपये से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगता रहेगा. सितंबर 2024 में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें मंत्रियों के समूह को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था. जीएसटी रेट को युक्तिसंगत बनाने के लिए जो मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है उसने पैक्ड पीने का पानी, साइकिल, एक्सरसाइज नोटबुक्स, लग्जरी हाथों की घड़ी और जूतों पर जीएसटी रेट्स में बदलाव करने का सुझाव दिया है. जीएसटी रेट में इस बदलाव से सरकार को 22000 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा. जीओएम ने 20 लीटर वाले पैक्ड पीने के पानी पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी, 10000 रुपये से कम के साइकिल पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है. एक्सरसाइज नोटबुक्स पर भी जीएसटी रेट को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव है. जबकि 15000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले जूतों पर जीएसटी रेट को बढ़ाकर 18 फीसदी से 28 फीसदी, और 25000 रुपये से ज्यादा कीमत वाली घड़ी पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है.

सोना दस दिन में 5000 रुपये सस्ता, चांदी 10,000 रुपये से ज्यादा फिसली

सोने और चांदी के दाम जहां धनतेरस और दिवाली तक ऊंचाई के नए-नए रिकॉर्ड बना रहे थे वहीं पिछले 10 दिनों में दोनों कीमती मेटल्स के रेट लगातार सस्ते हुए हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि केवल 10 दिनो में सोना अपने ऊपरी स्तर से 6 फीसदी सस्ता हो चुका है और इसमें 4750 रुपये की कटौती हो चुकी है. वहीं चांदी ने तो रिकॉर्ड गिरावट दिखाते हुए 10 दिन में 10,000 रुपये के सस्ते दाम दिखा दिए हैं. चांदी 1 लाख रुपये के पार जा पहुंची थी लेकिन इसमें अब 90 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक का भाव देखा जा रहा है. सोना जो 79,700 पर जा पहुंचा था वो 74,950 के करीब के रेट पर है.

अमेरिका से जुड़ा है गोल्ड-सिल्वर की गिरावट का कनेक्शन

4 नवंबर को अमेरिका में चुनाव और वहां डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से बिटकॉइन के दाम तो लगातार कुलांचे भर रहे हैं वहीं सेफ ऐसेट सोना और चांदी के रेट लगातार गिर रहे हैं. रुपये की सिलसिलेवार गिरावट और डॉलर की तेजी के साथ कदमताल बिठाते हुए सोना-चांदी अपनी चाल धीमी कर चुके हैं. डॉलर इंडेक्स आज 106 के पार जा चुका है.

देश में सोना सस्ता होने का फायदा मिलेगा शादियों के सीजन में

भारत में इस समय सोना सस्ता होने का फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो कि शादी के सीजन में खरीदारी करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं. ये सोना खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका है. डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारतीयों को राजनीतिक या कूटनीतिक रूप से कोई कनेक्शन दिखे ना दिखे, कीमती मेटल्स के खरीदारी के लिए जरूर फायदा दिख रहा है. ट्रंप की जीत से डॉलर को मिल रही मजबूती ने रुपये पर दबाव डाला है और सोने के रेट लगातार नीचे आए हैं. इस बार के निर्यात और आयात आंकड़ों में भी सोने और चांदी का आयात क्रमशः घटा है.

एसआईपी (SIP) निवेश क्या हैः यह कैसे काम करता है?

सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) एक वित्तीय योजना है जो निवेशकों को सावधानीपूर्ण और सूचित तरीके से निवेश करने का एक मौका प्रदान करती है। आप इसमे एक छोटी रकम को नियमित अंतराल के लिए निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिल सकती हैं। SIP के माध्यम से निवेश करने से आपको बाज़ार की अस्थिरता या उतार-चढ़ाव से बचने का मौका मिलता है, क्योंकि वह नियमित निवेश में बदलते बाज़ार की स्थिति से निरंतर बदलती रहती है। इससे आपकी वित्तीय स्थिति में स्थिरता बनी रहती है और संवेदनशीलता की दिशा में मदद मिलती है।

म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या है ?

SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति एक निश्चित फंड योजना का चयन करता है और समय-समय पर छोटी राशि में निवेश करता है। इस प्रणाली की विशेषता यहाँ पर है कि यह वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए नियमित रूप से निवेश करने की स्वीकृति देती है, जिससे उच्च रिटर्न की संभावना बनी रहती है। म्यूचुअल फंड निवेश का एक बेहद सरल तरीका है। आप इसमे नियमित अंतराल पर निवेश करके अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं ।

एसआईपी कैसे काम करता है ? (SIP Kaise kam karta hai)

SIP एक तरीका है जिससे आप म्युचूअल फंड में नियमित रूप से कम धन राशि के साथ भी निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह उन निवेशकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनकी आय कम हो या जो नियमित रूप से निवेश करना चाहते हैं।

इस प्रक्रिया में, पहले आप अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं। फिर आप अपने निवेश के लिए निवेश करने की राशि और निवेश के अंतराल का चयन करते हैं। आपके द्वारा चुने गए समय पर आपके द्वारा तय की गई राशि आपके खाते से काट ली जाएगी और स्वचालित रूप से फंड में निवेश कर दी जाएगी।

इसकी मदद से आप मात्र 500 रुपए से भी म्युचूअल फंड में निवेश कर सकते हैं, इसीलिए पिछले कुछ समय से इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी है और बहुत लोग इसे करने लगे हैं।

वैसे तो एसआईपी में निवेश करके आप अपने लिए बचत और ग्रोथ दोनों ही करते हैं परंतु इसके अलावा भी एसआईपी करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लाभ नीचे दिए गए हैं:

SIP में निवेश करके आप कम्पाउन्डिंग का लाभ उठा सकते हैं। जितने ज्यादा समय तक आप निवेश करते हैं, उतना ही आपको रिटर्न भी मिलता है। यह आपको निवेश में फ़्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। अगर आप एसआईपी करते हैं और आपकी चलती एसआईपी के दौरान बाज़ार में कोई गिरावट आए तो आप तुरंत इसको रोक सकते हैं या बंद कर सकते हैं। एसआईपी करके आप आयकर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।इसमें आप निवेश का अंतराल अपनी सहूलियत के अनुसार चुन सकते हैं जैसे आप सालाना निवेश करना चाहते हैं या हर महीने। आप एसआईपी करने के लिए अपने पेमेंट्स को ऑटोमेट भी कर सकते हैं जिससे पैसे हर महीने अपने आप आपके बैंक से निवेश हो जाते हैं। इससे आपका समय भी बचत है। SIP के माध्यम से निवेश करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। SIP वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक योग्य और सबसे सुविधाजनक तरीका है। सिस्टमेटिक निवेश के द्वारा, आप अपने बजट के अनुसार निवेश कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं।

एसआईपी के लिए डॉक्युमेंट्स

एसआईपी (Systematic Investment Plan) शुरू करते समय, आपके पास निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होने चाहिए:

पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता डिटेल्स

फ़ॉर्म 16 या सैलरी स्लिप,फ़ॉर्म 26AS

बैंक डिटेल्स, फ़ॉर्म 80C/80D की प्रमाणित प्रतियाँ, एसआईपी (SIP) में निवेश क्यों करना चाहिए ??

आपको एसआईपी में निवेश अवश्य करना चाहिए क्यूंकि इसकी मदद से आप को बचत और नियमित निवेश की आदत पढ़ जाती है और आपको वित्तीय तौर पर सुरक्षा मिलती है। जब आप हर महीने थोड़े थोड़े करके निवेश करते हैं तो कम्पाउन्डिंग के कारण आप

एक अच्छी राशि जमा कर लेते हैं जिससे आप अपने किसी वित्तीय लक्ष्य जैसे घर खरीदना, आसानी से पूरा कर सकते हैं। साथ में आप रिटायरमेंट के बाद के लिए भी पैसे जोड़ पाते हैं।

एसआईपी में क्योंकि आप एक साथ ज्यादा पैसे न डालकर छोटी छोटी किश्तों में निवेश कर पाते हैं तो इससे आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ता, इन सब कारणों कि वजह से आपको एसआईपी में ज़रूर निवेश करना चाहिए।

एसआईपी निवेश कैसे शुरू करें?

एसआईपी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जब आपको उद्देश्य पता हो तो आप अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको हर महीने कितनी राशि निवेश करने की आवश्यकता है। उसके बाद, सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं का पालन करें:

अपने दस्तावेज़ तैयार रखें, केवाईसी पूरा करें,एसआईपी के लिए पंजीकरण करें,सही योजना का चयन करें,निवेश राशि तय करें

SIP की तारीख चुनें, फ़ॉर्म जमा करें

एसआईपी में निवेश करने के लिए आप नीचे दिए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

पहले अपने लिए सही म्युचूअल फंड का चयन करें जिसके लिए बेहतर होगा आप थोड़ी रिसर्च करें। आपको म्युचूअल फंड निवेश के लिए अकाउंट खोलना होगा जो कि आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। कोटक की वेबसाइट या ऐप से आवेदन करना आसान प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म में अपनी जानकारी भरें और ज़रूरी दसतावेज़ अपलोड करें, फिर आपकी डिटेल्स और दस्तावेज़ वेरिफ़ाई होने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसमें आपने जो फंड चुना है उसकी SIP आप, प्लान की राशि, और समय चुनने के बाद ऑटोमैटिक पेमेंट सेट करके कर सकते हैं और फिर हर महीने आपके अकाउंट से निवेश होता रहेगा। निवेश करने के बाद आपको अपने SIP की ग्रोथ को हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए।

एसआईपी के प्रकार (वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर)

आप अपने वित्तीय लक्ष्यों और आवश्यकताओं के हिसाब से SIP के निम्नलिखित प्रकारों में से किसी भी प्रकार की SIP का चयन कर सकते हैं:

मासिक SIP: इसमें आप मासिक यानी हर महीने में निवेश कर सकते हैं।

तिमाही SIP: इसमें आप हर तीन महीने के अंतराल पर निवेश कर सकते हैं।

चयनित तिमाही SIP: इसमें आप अपनी पसंदीदा तिमाही पर निवेश कर सकते हैं।

वार्षिक SIP: इसमें आप हर वर्ष में एक बार निवेश कर सकते हैं।

एसआईपी के प्रकार

एसआईपी के प्रकार समझकर आप अपने लिए सही एसआईपी आसानी से थोड़ी रिसर्च करके चुन सकते हैं। इसके 7 प्रकार होते हैं:

रेगुलर एसआईपी: इसमें आप एक नियमित एसआईपी में निवेश राशि और फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। इसमें आप फिक्स्ड राशि निवेश करते हैं और नियमित अवधि में स्वचालित रूप से वह चलती है।

फ्लेक्सिबल एसआईपी: इसमें आप अपनी वित्तीय परिस्थिति और बाज़ार की स्थिति के अनुसार निवेश राशि बदल सकते हैं। इसको फ्लेक्स एसआईपी या फ्लेक्सी एसआईपी भी कहा जाता है।

टॉप - अप एसआईपी: SIP का यह प्रकार आपको अधिक निवेश की अनुमति देता है। आपके करेंट प्लान के दौरान ही, जब आपके पास निवेश के लिए अधिक पैसा उपलब्ध हो, तो आप अपनी निवेश राशि बढ़ा सकते हैं।

स्टेप – अप एसआईपी: आप इसमें पूर्व निर्धारित अंतराल पर एसआईपी का उपयोग करके एसआईपी राशि बढ़ा सकते हैं।

ट्रिगर एसआईपी: ट्रिगर एसआईपी में निवेश तभी होता है जब कोई विशेष घटना होती है। यह विशेष घटना एक सकारात्मक बाज़ार प्रवृत्ति या लक्षित एनएवी लेवल भी हो सकता है।

परपेचुअल एसआईपी: जब भी आप sip करते हैं तो उसमें शुरुआत की डेट तो डाल देते हैं पर वो खत्म कब होगी आप में से ज्यादातर लोग यह नहीं डालते। तो जिस भी एसआईपी में खत्म होने की डेट नहीं होती वो परपेचुअल एसआईपी बन जाती है।

मल्टी एसआईपी: आप इसमें केवल एक एसआईपी से ही विभिन्न फंड हाउस योजनाओं में निवेश करने का लाभ उठा सकते है।

बीमा के साथ एसआईपी: इसमें इंश्योरेंस और एसआईपी के फ़ायदे एक साथ आपको मिल सकते हैं। आपका पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है, फंड हाउस आपको उस पर जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करता है। यदि निवेश अवधि के दौरान निवेशक की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती है, तो यह बीमा पॉलिसी उनके नॉमिनी को मिल जाती है।

रेगुलर प्लान में कैसे करें निवेश ?

रेगुलर प्लान में निवेश करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं: म्यूचुअल फंड का चयन : पहला कदम है वह म्यूचुअल फंड चुनना जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं। आप यह चयन आपके वित्तीय लक्ष्यों, रिस्क टॉलरेंस, और निवेश की अवधि के आधार पर करें।

ऑनलाइन खरीदारी के नुकसान और फायदे

ऑनलाइन शॉपिंग Vs ऑफलाइन खरीदारी

सिर्फ कुछ साल पहले, ऑनलाइन शॉपिंग आज के जैसे लोकप्रिय नहीं थी। लेकिन आजकल ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारी के लिए सबसे अच्छी विधि है। इंडिया में अभी भी लोग ऑनलाइन जैसी चीजों पर ज्यदा विश्वास नहीं करते है। लोग इन्टरनेट से शॉपिंग करने को सुरक्षित नहीं मानते थे क्योंकि लोगों को अपनी निजी बैंक खातों की जानकारी या एटीएम कार्ड्स की जानकारी यूँ ऑनलाइन किसी साईट पे इस्तेमाल करना सही नहीं लगता था। कुछ लोग तो Online Shopping सिर्फ इस लिए नहीं करते है क्यों की उनका मानना है की ऑनलाइन ख़रीदा हुआ सामान अच्छा नहीं होता है। लेकिन जागरूकता के कारण सोच बदली है और आज अधिक से अधिक लोग कई फायदों और लाभों के कारण, इन दिनों दुकानों में जाने बजाय चीजों को ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं।

अब ऑनलाइन शॉपिंग साईट विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती है, यहाँ हम कपड़े, जूते, घरेलू उपकरणों, स्मार्टफोन, एयरलाइंस टिकट और यहां तक कि अपनी किराने की सामान भी खरीद सकते है। इन दिनों उपयोग की जा रही सबसे लोकप्रिय वेबसाइटों की सूची यहाँ दी गई हैं।

यहाँ हम ऑनलाइन खरीदारी के नुकसान और फायदे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कारण हैं कि कई लोग ऑनलाइन खरीदारी पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं करना चाहते है? इसके शीर्ष कारण नीचे दिए गए हैं।

हालांकि इंटरनेट सामान खरीदने का एक तेज़ और आसान तरीका प्रदान करता है, कुछ लोग केवल इसे सीमित एरिया में ही इस तकनीक का उपयोग करना पसंद करते हैं। वे एक दुकान में खरीदने से पहले किसी उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के साधन के रूप में इंटरनेट को मानते हैं।

ऑनलाइन शॉपिंग के प्रमुख नुकसान इस प्रकार हैं।

1. डिलेवरी में देरी- डिलीवरी में देरी और उत्पाद कई स्थानों पर वितरित नहीं किया जाता है। लंबी अवधि और उचित प्रबंधन की कमी के परिणामस्वरूप शिपमेंट में देरी अक्सर हो जाती है। हालांकि ऑनलाइन उत्पाद के चयन, खरीद और भुगतान की अवधि में 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है लेकिन ग्राहक के दरवाजे पर उत्पाद की डिलीवरी में लगभग 4-8 दिन लगती है। यह ग्राहक को निराश कर सकता है और उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग से रोकता है।

2. कैश ऑन डिलिवरी विकल्प हमेशा उपलब्ध नहीं होना- बहुत से प्रोडक्ट होते है जिनको खरीदने के लिए कैश ऑन डिलिवरी का ऑप्शन नहीं दिया होता है तब उस स्थिति में हमें ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ते है।

3. ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट की स्पर्श और महसूस की कमी उत्पाद की गुणवत्ता पर चिंता पैदा करता है क्योंकि हम उत्पाद की प्रदर्शित चित्रों और विवरणों पर निर्भर होते हैं।

4. मोलभाव - दुर्भाग्यवश, लगभग हर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सभी कीमतें निर्धारित की जाती हैं और इनके लिए सौदा नहीं किया जा सकता है।

ऑनलाइन खरीदारी के लाभ हैं:

1. समय और प्रयास बचाता है- ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर 24/7, सप्ताह में 7 दिन और 365 दिनों के दौरान खुले होते हैं जो की आपको अपनी गति और सुविधा पर खरीदारी करने की आजादी देती है। बाज़ार की दुकाने आपको यह सुविधा नहीं देते हैं। यदि आपको स्थानीय स्टोर से कुछ खरीदने की ज़रूरत है, तो आपको उस दुकान के लिए 11 बजे तक इंतजार करना होगा। यहां तक कि उत्पाद उपलब्धता भी एक मुद्दा है स्थानीय दुकानों में, आप इसे वहाँ तक पहुंचने के बाद ही जान पाते है की आपकी जरुरत का सामान उपलब्ध है या नहीं। यह सब बहुत सारी परेशानी पैदा करता है जबकि ऑनलाइन खरीदारी करते समय आसानी से ऐसे परेशानी से बचा जा सकता है। कोई पार्किंग का तनाव नहीं, कोई बस / टैक्सी किराया नहीं। बिलिंग काउंटर पर त्योहार के मौसम के दौरान कोई लंबी कतार नहीं। आलसी सह व्यस्त लोगों के लिए सुविधाजनक और सबसे अच्छा विकल्प।

2. विस्तृत विविधता/उत्पादों की श्रृंखला उपलब्ध हैं- आप इन दिनों इंटरनेट से लगभग कुछ भी खरीद सकते हैं! यह फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन, स्नैपडील जैसी अग्रणी ई-कॉमर्स वेबसाइटों की वजह से है जो देश भर में फैले कई विक्रेताओं के उत्पादों की सूची देता है। यह घरेलू उपकरणों, स्मार्टफोन, कपड़े, सहायक उपकरण, और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों सहित उत्पादों के विस्तृत चयन की सुविधा देता है।

3. अच्छी छूट/कम कीमतें- आपने ऑनलाइन साइटों पर बहुत सस्ते में उपलब्ध कोई प्रोडक्ट को देखा होगा। यह संभव है क्योंकि ऑनलाइन शॉप में दुकान किराए, कर्मचारी खर्च और अन्य सहित कई ओवरहेड लागते खत्म हो जाती है। बदले में, यह लाभ कम कीमत पे उपभोक्ता को मुहैया कर दिया जाता है। इस समय ऑनलाइन खरीदारी अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है। चूंकि ऑफ़लाइन खुदरा विक्रेता कीमतों से मेल खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए अधिकांश ऑनलाइन वेबसाइटों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया है, जो बदले में उपभोक्ताओं के रूप में हमारे लिए चीजों को बेहतर बना रहा है। यदि आप नया स्मार्टफोन, टेलीविजन या एयर कंडीशनर खरीदने की तलाश में हैं, जो शायद एक बड़ा खर्च होने जा रहा है, तो आप स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम संभव मूल्य की तलाश करेंगे।

यदि आप ऑनलाइन जांच करते हैं, तो आप देखेंगे कि कीमतें प्रत्येक ई-कॉमर्स साइट से भिन्न होती हैं। इसके साथ आपकी सहायता के लिए, सभी प्रमुख ऑनलाइन विक्रेताओं की कीमतें प्रदर्शित होती हैं जहाँ आप तुलना करके सबसे कम कीमत में सामान खरीद सकेंगे।

4. आसान रिटर्न- क्या आपको कभी दुकान में खरीदी गई चीज़ को बदलने की कोशिश करने के दौरान परेशानी हुई हैं या विक्रेता आपको अनदेखा करता है? दुर्भाग्यवश, यह अक्सर से अधिक होता है। बेस्ट केस परिदृश्य दुकानदार है जो आपको सेवा केंद्र की ओर इशारा करता है यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदा है। यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि अधिकांश ऑफलाइन दुकानें पुनर्विक्रेता हैं और दोषपूर्ण सूची को ढेर करना पसंद नहीं करेंगे।

ट्रेंड अलर्ट: इस सीज़न अपने फैशन गेम को रखें ईज़ी और क्लासिक, जानें किस तरह की नेकलाइन के साथ पहनें कैसी ज्वेलरी?

ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना सोचे-समझे अपने वॉर्डरोब को ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ से भर दें. सिर्फ़ बेस्ट दिखने केलिए ऐसा करना रॉन्ग चॉइस है, क्योंकि ग़लत ज्वेलरी सिलेक्शन से आप क्लम्ज़ी और अनकम्फ़र्टेबल लगेंगी और आपकी ख़राब फ़ैशनसेंस ही सामने नज़र आएगी. वहीं राइट ज्वेलरी आपके लुक को पलभर में बना सकती है बेहद अट्रैक्टिव. किसी भी आउटफ़िट के लिए येसबसे स्ट्रॉन्ग ऐड-ऑन में से एक है क्योंकि एक राइट पीस से आपके स्टाइल सेंस की झलक मिल जाती है और वो आपके लुक को निखार सकता है.

अलग-अलग पीसेज़ के साथ आउटफिट्स को एक्सेसराइज़ करने से आपका लुक पूरी तरह बदल सकता है. लेकिन कभी-कभी सही ज्वेलरी सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल लगता है, ऐसे में फैशन और लाइफस्टाइल प्रोफेशनल आतिफ़ा अख्तर बता रही हैं पॉप्युलर नेकलाइनऔर उनके साथ पेयर किए जा सकने वाली एक्सेसरीज़-ज्वेलरीज़ की चीट शीट.

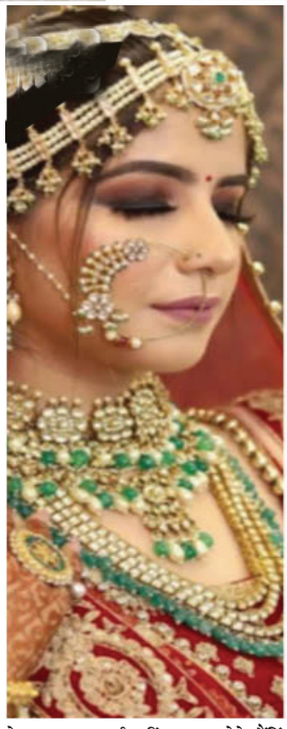

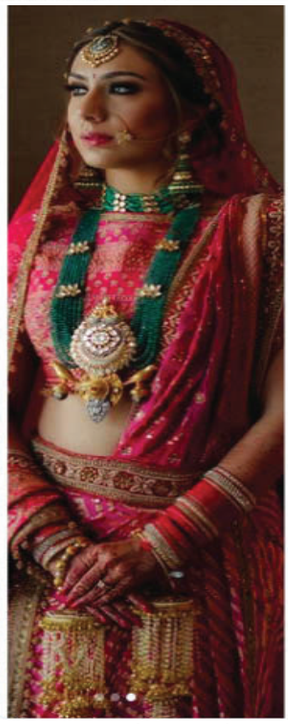

क्रू नेक या हाई-राउंड नेकलाइन

जब आप राउंड नेकलाइन का ब्लाउज़ पहनती हैं तो हेवी ज्वेलरी आपके आउटफ़िट के लुक को खराब कर सकती हैं, क्योंकि ये नेकलाइन कॉलर बोंस को कवर करती है, इसलिए इन ब्लाउज़ के साथ हार पहनने से बचना बेहतर है, खासकर अगर वो ब्रोकेड से बनेहों. एलीगेंट लुक के लिए बड़े स्टड या हेवी-लंबी बालियां,जैसे- झुमका या चांदबाली पहनी जा सकती हैं. हालांकि, बड़े फ़ंक्शन्स के लिए, नेकलाइन को कॉम्प्लिमेंट करते हुए नेकलेस ट्राई किए जा सकते हैं. अगर ब्लाउज़ सॉलिड कलर का है, तो लॉन्ग चेन आपके ब्लाउज़ की सिम्प्लिसिटी को बढ़ा देगी.

बोट नेक, डीप राउंड या स्क्वायर नेक

डीप कॉलरबोन या यहां तक कि बोट नेक जैसी नेकलाइन के लिए चोकर्स हैं परफेक्ट चॉइस. वे आपके कॉलरबोन पर फ़ोकस करते हैं, जिससे आप लम्बी नज़र आती हैं. चोकर के साथ स्टड ईयररिंग्स या छोटे हैंगिंग ईयररिंग्स पेयर करें. जब आप बोट नेक पहनती हैं तोझुमके और बड़े ईयररिंग्स परफेक्ट लगते हैं और कभी-कभी पतला चोकर भी कमाल का काम करता है.

कॉलर नेक

ब्लाउज़ में कॉलर नेकलाइन पिछले कुछ समय से बेहद पॉप्युलर है और ये आज एक ट्रेंड या फैशन बन गया है. टेक्सचर्ड या ब्रोकेडफैब्रिक से बने कॉलर ब्लाउज़ के साथ ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती. आपके आउटफिट को और अधिक पंच देने के लिए सॉलिड कॉलरवाले ब्लाउज़ के साथ लंबी चेन पहनी जा सकती है.

डीप वी नेकलाइन

छोटे, चौड़े नेकलेस या स्टेटमेंट ज्वेलरी डीप वी नेकलाइन्स के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं. वे आपकी नेकलाइन को शेप देती हैं, जिससे आपको और अट्रैक्टिव लुक मिलता है. इसके अलावा, कुछ लॉन्ग-एंग्यूलर पेंडेंट वी-नेक साड़ी-ब्लाउज़ के लिए वॉल्यूम काकाम करते हैं.

स्वीटहार्ट नेकलाइन

स्वीटहार्ट नेकलाइन पहनते समय हमेशा बैलेन्स करने की कोशिश करें ताकि इस ब्रॉड नेकलाइन का लुक अच्छा लगे. छोटी चेन वालास्टेटमेंट नेक पीस जो नेकलाइन के क्लोज़ हो, उसे ट्राई करें. मेटल या स्टोंस का चंकी और बोल्ड नेकपीस इस नेकलाइन को कॉम्प्लिमेंटकरके आपके पूरे लुक को बेहद अट्रैक्टिव बना देगा.

वन शोल्डर नेकलाइन

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वन शोल्डर टॉप या ड्रेस थोड़ा ड्रामैटिक हो सकता है, इसलिए इसे सही ज्वेलरी के साथ पेयर करकेइस रॉयल एसिमेट्रिकल नेकलाइन के साथ आप जस्टिस कर पाएंगी. चंकी या स्टेटमेंट ईयररिंग्स सिलेक्ट करें. ओवरसाइज़्ड हूप्स याडैंगलर्स ट्राई करे और नेकपीस को पूरी तरह स्किप कर दें. कॉकटेल या स्टेटमेंट फ़िंगर रिंग और भी ड्रामा ऐड करेगी और आपका लुकलगेगा और भी रॉयल.

आज लोग ज्वेलरी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके पास इसमें वेरायटी भी काफ़ी है- सिम्पल से लेकर फ़ैंसी तक कोई भीराइट पीस आपके पूरे फेस्टिव लुक को निखार सकता है. यह आपके लुक का सबसे स्ट्रॉन्ग ऐड-ऑन है जो आपके स्टाइल को पूरी तरहसे सबके सामने लाने में मदद करता है

शादी से पहले कुंडली का मिलान क्यों किया जाता है? ज्योतिषी से जानिए

शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े एक-दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शादी के तुरंत बाद ही जोड़े अलग हो जाते हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुंडली दोष माना जाता है. शादी से पहले कुंडली मिलान की महत्ता को समझाने के लिए वडोदरा की प्रसिद्ध ज्योतिषी विजया राज ने विस्तार से जानकारी दी है.

शादी से पहले कुंडली मिलान का महत्व

ज्योतिषी विजया राज का मानना है कि शादी हमेशा कुंडली मिलान करके ही करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "अगर अरेंज मैरिज है तो माता-पिता खुद कुंडली मिलान करवाते हैं, लेकिन लव मैरिज में अक्सर युवक-युवतियां कुंडली मिलाने पर जोर नहीं देते. जब हम अपने जीवन में किसी और व्यक्ति को जोड़ते हैं तो जरूरी है कि हमारे ग्रह और उनके ग्रह आपस में सामंजस्य में हों, ताकि हमारा दांपत्य जीवन शांतिपूर्ण और सफल रहे."

प्रेम विवाह में कुंडली कैसे देखें?

जिन जोड़ों का प्रेम विवाह हो रहा है, वे खुद भी अपनी कुंडली का मिलान कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति की राशि मेष है, तो वह 6, 8, और 12 तारीख के बाद वाली राशियों वाले व्यक्ति से विवाह न करें. मेष राशि का व्यक्ति 6वें भाव की कन्या राशि, 8वें भाव की वृश्चिक राशि, और 12वें भाव की मीन राशि वाले व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता. ऐसा करने से विवाह के बाद झगड़े और विवाद बढ़ने की संभावना होती है.

नाम और राशि के अनुसार मिलान

विजया राज के अनुसार, यदि किसी का नाम सिंह राशि से शुरू होता है, तो उसका जीवनसाथी मकर, मीन, या कर्क राशि से नहीं होना चाहिए. हालांकि, शादी के बाद अपना नाम बदलने का विकल्प भी है, जिससे कुछ हद तक अनुकूलता प्राप्त की जा सकती है.

मंगल दोष: दोष नहीं, एक सकारात्मक तत्व

कुंडली में मंगल का होना हमेशा अशुभ नहीं होता, बल्कि इसे सकारात्मक भी माना जाता है. जिन व्यक्तियों के पास मंगल होता है, उनमें ऊर्जा का स्तर अधिक होता है, जो उन्हें साहसी और दृढ़ बनाता है. ऐसे लोगों के लिए यह बेहतर होता है कि वे उसी ऊर्जा स्तर वाले व्यक्ति से विवाह करें.

शादी हो या कैजुअल फंक्शन, सर्दियों में स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये फैशन फंडे

सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि सर्दियों में भी स्टाइलिश और फैशनेबल रहा जा सकता है। अब आप पूछेंगी कैसे, तो हम आपको यही तो बताने के लिए हैं। पहले यह बताइए कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा किस इवेंट में जाना होता है? हर आवाज़ कहेगी शादी में। और शादी में जाने का मतलब है, नो स्वेटर। यही न! दरअसल, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्वेटर या ऊनी कपड़े साड़ी या किसी भी ट्रडिशनल आउटफिट का लुक खराब कर देते हैं। तो हम बताते हैं कि शादी जैसे इवेंट में अगर साड़ी पहननी है, तो कैसे सर्द हवाओं के बीच आप स्टाइलिश दिख सकती है।

साड़ी

शादी में साड़ी पहनने का मन हो, तो सबसे पहले फैब्रिक पर ध्यान दीजिए। अगर सिल्क फैब्रिक होगा, तो सर्दी से बचाव का आधा इंतज़ाम तो यूं ही हो जाएगा। सिल्क गरमाहट देता है। साड़ी के साथ स्टाइलिश पौंचू या केप बहुत अच्छा लगता है। इससे लुक अलग आता है और सर्दी से बचाव के साथ फैशनेबल होने की चाहत भी पूरी हो जाती है।

इंडो वेस्टर्न लुक

अगर आप कुछ इंडो वेस्टर्न ट्राई करना चाहती हैं, तो किसी डार्क कलर की ट्राउज़र पर वैलवेट का एंब्रॉयडेड जैकेट या कोट भी अच्छी चॉइस हो सकता है। ऐसे आउटफिट्स आपको अलग दिखाएंगे। कोट की जगह आप लॉन्ग वूलन कुर्ता भी ट्राई कर सकती हैं, जिस पर सीक्वेंस का काम हो।

सदाबहार लुक

सदाबहार का मतलब है, यंग लुक देने वाले आउटफिट्स। इसमें चेक्स डिज़ाइन सबसे आगे हैं। सर्दियों में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। किसी आउटडोर फंक्शन या पार्टी के लिए रेड एंड ब्लैक या ब्लैक एंड व्हाइट कलर के चेक्स बढ़िया पसंद हो सकते हैं।

कैजुअल फंक्शन्स

यदि कोई पिकनिक है या ऑफिस का कैजुअल फंक्शन, तो प्लेन वूलन स्कर्ट पर ऑफ शोल्डर टॉप पहनें। साथ में मैचिंग स्टोल और कोई स्मार्ट जैकेट कैरी करें, जिससे अगर सर्द हवाएं सताएं, तो आपके पास बैकअप रहे। ट्राउज़र पर चेक्स प्रिंट का कोट और गले में कंट्रास्ट मफलर भी ट्राई कर सकती हैं।

कभी-कभी ओवरसाइज़

वैसे तो फैशन में फिटिंग सबसे ज़रूरी है। लेकिन सर्दियों में खासकर जब जैकेट की बात हो, तो थोड़ी ओवरसाइज़ जैकेट पहनी जा सकती है। शॉपिंग या फिर कहीं हैंगआउट पर जाने के लिए फिटिंग वाली जींस पर ओवरसाइज़ जैकेट पहनना स्मार्ट लगता है।

बूट करेंगे सूट

सर्दियों में बूट्स पहनना अच्छा लगता है। इनसे आपका स्टाइल ग्राफ अप हो जाता है और ये इतने सारी वैरायटी में मिलते ही पूछिए मत। बूट्स चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें :

BSNL ने शुरू की ऐसी सर्विस, जो अभी तक कोई न कर पाया, घर के बाहर हाई स्पीड नेट का टंटा ही खत्म

बीएसएनएल ने कंज्यूमर्स के लिए नेशनल वाई-फाई रोमिंग सर्विस शुरू की है. इसके तहत बीएसएनएल एफटीटीएच कनेक्शन के यूजर बीएसएनएल के पैन-इंडिया नेटवर्क से जुड़ सकेंगे.

नई दिल्ली. सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपनी नेशनल Wi-Fi रोमिंग सर्विस शुरू की है, जिसकी मदद से BSNL FTTH (फाइबर-टू-द-होम) यूजर्स पूरे भारत में कहीं भी बीएसएनएल के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकेंगे. अभी तक, BSNL के FTTH यूजर्स केवल अपने राउटर की रेंज के भीतर ही इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे.

नेशनल वाई-फाई रोमिंग सर्विस को बीएसएनएल के नए लोगो और 6 अन्य नई इनिशिएटिव के साथ पेश किया गया, जिसमें स्पैम प्रोटेक्शन उपाय, फाइबर-बेस्ड इंट्रानेट टीवी सर्विस, एनी टाइम सिम (ATM) कियोस्क और डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस शामिल हैं. बीएसएनएल के मुताबिक, इसकी नेशनल वाई-फाई रोमिंग सेवा का मकसद अपने मौजूदा FTTH कंज्यूमर्स के डेटा खर्च को कम करना है. वे देशभर में टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा स्थापित वाई-फाई हॉटस्पॉट्स से बिना किसी एक्सट्रा चार्ज के कनेक्ट हो सकते हैं.

BSNL Wi-Fi Roaming का इस्तेमाल कैसे करें?

बीएसएनएल नेशनल वाई-फाई रोमिंग सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए कंज्यूमर को एक एक्टिव बीएसएनएल एफटीटीएच प्लान की जरूरत होगी. इस सर्विस के लिए साइन अप करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

1. बीएसएनएल वाई-फाई रोमिंग पोर्टल https://portal.bsnl.in/ftth/wifiroaming पर जाएं.
2. एक्टिव बीएसएनएल एफटीटीएच नंबर दर्ज करें.
3. इसके बाद, बीएसएनएल एफटीटीएच के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
4. कैप्चा कोड दर्ज करें.
5. ओटीपी वेरिफिकेशन समाप्त करने के लिए वेरिफाई पर क्लिक करें.

इंदौर पुलिस की कार्यवाही में 50 लाख रुपए अंतरराष्ट्रीय कीमत की MD drugs के साथ 02 तस्कर आरोपी गिरफ्तार

उक्त कार्यवाही में आरोपी तस्करो के कब्जे से 105 ग्राम MD Drugs जब्त।थाना क्राईम ब्रांच इंदौर में आरोपी के विरुद्ध NDPS Act में अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही है अग्रिम वैधानिक कार्यवाही। आरोपी से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी(खरीदी-बिक्री) के संबंध में की जा रही है पूछताछ।

प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं इनकी गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही कर इनके नेटवर्क को नेस्तनाबूत करने के सख़्त निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ,मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिये गए हैं। इसी तारतम्य में इंदौर पुलिस द्वारा अभियान चलाकर लगातार अवैध नशे पर कड़ा प्रहार कर रही है।

इंदौर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के क्रय–विक्रय व इनमें संलिप्त व्यक्तियो के संबंध मे गोपनीय रुप से आसूचना संकलन संकलन की जा रही थी। इसी दौरान क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा संदेहियो की तलाश एवं पतारसी इंदौर शहर में

अलग–अलग स्थानो पर करते MR 4 रोड होते हुए पुरानी राजकुमार सब्जी मंडी तरफ़ निकलते दो संदेही व्यक्ति दिखे जो पुलिस की गाड़ी को देखकर घबरा गए , पुलिस टीम के द्वारा दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा और नाम,पता

पूछने पर अपना नाम (1). रोशन कुमावत निवासी रामकमल रेजिडेंसी फ्लैट इंदौर, (2). राजू जाट निवासी नवादापंथ धार रोड इंदौर का होना बताया। संदिग्ध आरोपीयो की तलाशी लेते उसके पास अवैध मादक पदार्थ MD drugs होना पाया गया जिसका विधिवत वजन 105 ग्राम होना पाया गया जिसके संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने कोई उचित उत्तर नही दिया। आरोपीयो के कब्जे से लगभग 105 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MD Drugs (अंतराष्ट्रीय कीमत करीब 50 लाख रुपए) एवं मोबाइल जप्त कर, आरोपियों के विरुद्ध थाना अपराध शाखा में धारा 8/22 NDPS एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना में लिया गया है, जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं । आरोपी से अवैध मादक पदार्थों के स्त्रोत व नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है ।

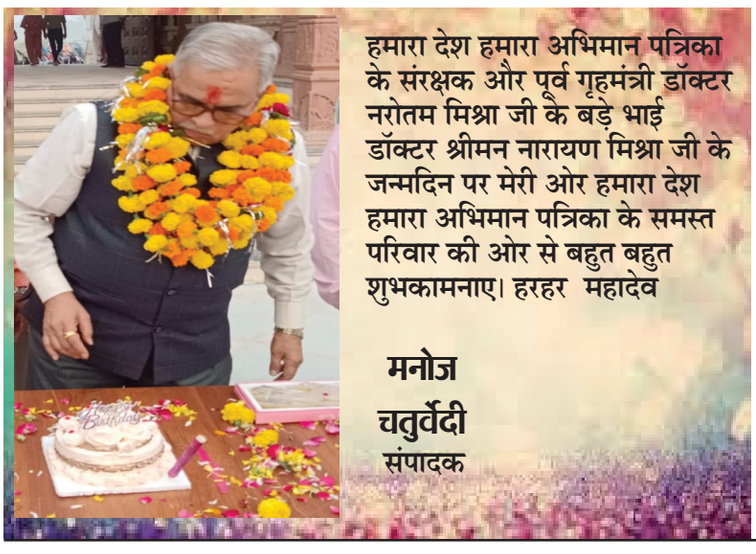

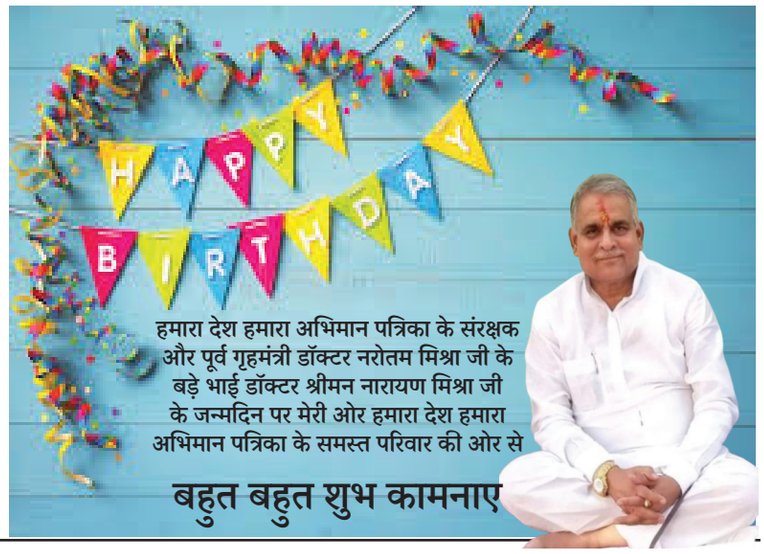

Google पर सर्च किए ये 6 शब्द तो हैकर्स के निशाने पर आ जाएंगे आप, जानें डिटेल्स

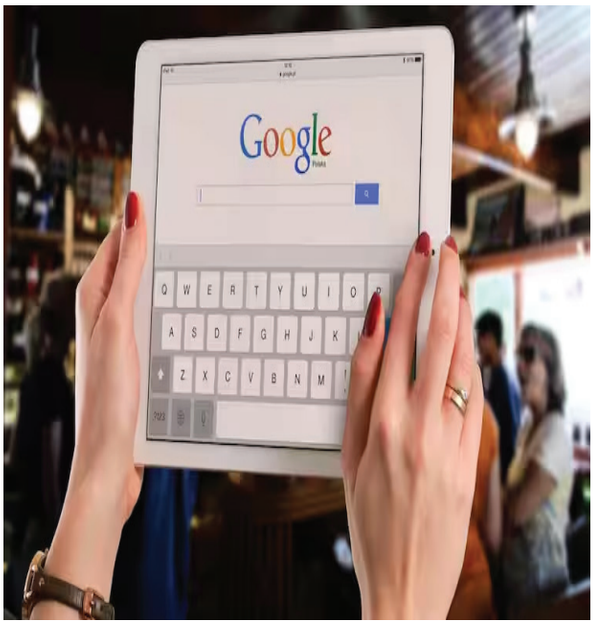

Google Search: आजकल हैकर्स लोगों को धोखा देने के लिए नए-नए तरीके खोज रहे हैं. हाल ही में आई एक रिपोर्ट से यह सामने आया है कि गूगल पर कुछ खास शब्द सर्च करना आपको खतरे में डाल सकता है. गूगल पर कुछ भी टाइप करके सर्च करना इतना सामान्य हो गया है कि हम अक्सर खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इससे साइबर हमलों का जोखिम बढ़ सकता है.

क्या होता है खतरा?

साइबर सिक्योरिटी फर्म Sophos ने इंटरनेट यूजर्स को चेतावनी दी है कि कुछ खास शब्द सर्च करने से बचें, जैसे "Are Bengal Cats legal in Australia?" हैकर्स ने कुछ खतरनाक लिंक बनाए हैं, जिन्हें क्लिक करने पर आपकी निजी जानकारी उनके हाथ लग सकती है. ये लिंक SEO Poisoning नामक तकनीक के माध्यम से गूगल पर ऊपरी परिणामों में आते हैं. जैसे ही आप इन लिंक पर क्लिक करते हैं, हैकर्स आपके सिस्टम पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं.

क्या होता है SEO Poisoning?

अब आपको बताते हैं कि आखिर ये SEO Poisoning होता क्या है. दरअसल, यह एक तकनीक है जिसमें हैकर्स गूगल सर्च परिणामों में अपनी हानिकारक साइट्स को ऊपर दिखाते हैं. जैसे ही आप इन साइट्स पर जाते हैं, ये साइट्स आपकी निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड आदि चुराने का प्रयास करती हैं. Sophos के अनुसार, ये खतरनाक लिंक खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स को निशाना बना रहे हैं.

क्या है बचने के उपाय

इन हैकर्स से बचने के लिए आपको कुछ चीजें करनी होंगी.

अपने सभी अकाउंट्स के लिए अलग-अलग और मजबूत पासवर्ड रखें. पासवर्ड में छोटे-बड़े अक्षर, संख्याएं और विशेष चिन्ह शामिल करें.

हर ऐप में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें. इससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है.

किसी भी अनजान ईमेल, लिंक या मैसेज पर क्लिक न करें. पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग करते समय बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें.

अपने डिवाइस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और नियमित रूप से अपडेट करें ताकि आपके सिस्टम की सुरक्षा बनी रहे.इन सावधानियों को अपनाकर आप साइबर हमलों से बच सकते हैं और अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं.

रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदते समय न खाएं धोखा!

इन बातों का जरूर रखें ख्याल

भारत में आज के समय में एक वर्ग ऐसा भी है जो नया मोबाइल और लैपटॉप न लेकर रिफर्बिश्ड गैजेट ले रहे हैं. रिफर्बिश्ड गैजेट आमतौर पर नए गैजेट से कम दाम में मिल जाते हैं. पैसे बचाने के चक्कर में लोग इन्हें खरीद भी लेते हैं. लेकिन कुछ समय बाद वो गैजेट अच्छे से काम नहीं करते हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इन परेशानियों से बचने के लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखकर रिफर्बिश्ड गैजेट खरीदने चाहिए. इन चीजों का ध्यान रखने से आपको और आपके डिवाइस को कोई परेशानी नहीं होगी.

ग्रेडिंग और कंडीशन देखें

बता दें कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप की ग्रेडिंग (Grade A, B, C) के रूप में होती है. Grade A सबसे अच्छा होता है. अगर आप Grade A ग्रेडिंग का लैपटॉप लेते हैं तो आपका लैपटॉप अच्छे से पर्फाम करेगा.

लैपटॉप की बैटरी लाइफ

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में खरीदते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान उसकी बैटरी पर होना चाहिए. रिफर्बिश्ड लैपटॉप की बैटरी लाइफ कितनी है. कम बैटरी लाइफ वाला रिफर्बिश्ड लैपटॉप न खरीदें.

जरूरी सॉफ्टवेयर होने चाहिए इंस्टॉल

रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदते वक्त उसमें मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अच्छे से चेक कर लें. ये भी सुनिश्चित करें कि एक्सटेंडेड वारंटी-एंटी-वायरस सब्सक्रिप्शन की सुविधाओं मिल रही है कि नहीं.

कीबोर्ड और ड्राइव चेक करें

कई बार सेकेंड हैंड लैपटॉप के कीबोर्ड में दिक्कत आती है. उनमें कुछ कीज खराब होती हैं या ठीक से काम नहीं करती हैं, इसलिए इसकी जांच कर लें. साथ ही यूज्ड लैपटॉप लेते समय सीडी व डीवीडी ड्राइव जरूर चेक करें. क्योंकि कई लैपटॉप में ये सीधे मदरबोर्ड से जुड़ा होता है. ऐसे में अगर इसमें खराबी है तो आपका काफी पैसा इसे सही कराने में लग सकता है.

ग्रेडिंग और कंडीशन देखें

बता दें कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप की ग्रेडिंग (Grade A, B, C) के रूप में होती है. Grade A सबसे अच्छा होता है. अगर आप Grade A ग्रेडिंग का लैपटॉप लेते हैं तो आपका लैपटॉप अच्छे से पर्फाम करेगा.

लैपटॉप की बैटरी लाइफ

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में खरीदते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान उसकी बैटरी पर होना चाहिए. रिफर्बिश्ड लैपटॉप की बैटरी लाइफ कितनी है. कम बैटरी लाइफ वाला रिफर्बिश्ड लैपटॉप न खरीदें.

जरूरी सॉफ्टवेयर होने चाहिए इंस्टॉल

रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदते वक्त उसमें मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अच्छे से चेक कर लें. ये भी सुनिश्चित करें कि एक्सटेंडेड वारंटी-एंटी-वायरस सब्सक्रिप्शन की सुविधाओं मिल रही है कि नहीं.

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

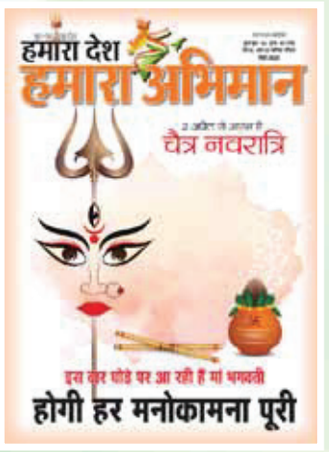

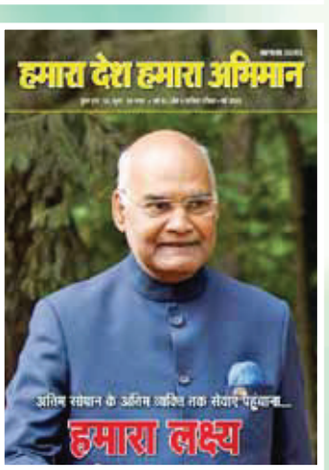

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136